₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

फरवरी 2020

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO.:- PT-35

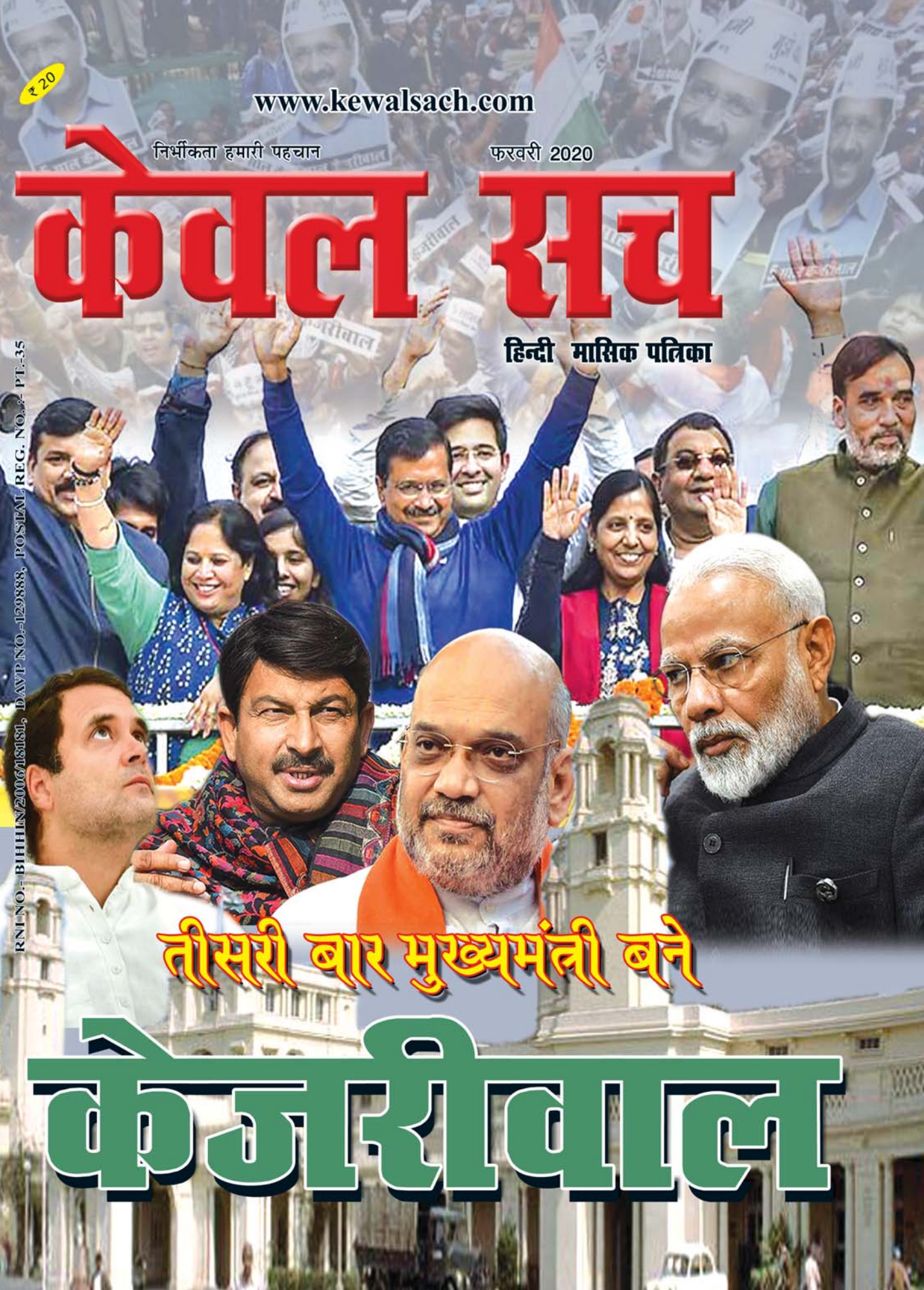

तीसरी बार मुख्यमंत्री बने

केजरीवाल

चलें गाँधी मैदान! पायें प्रतिष्ठा और सम्मान!!

12 अप्रैल 2020

ब्राह्मण परिवार मिलन महाकुम्भ

भविष्य की रक्षा करनें पहुचे

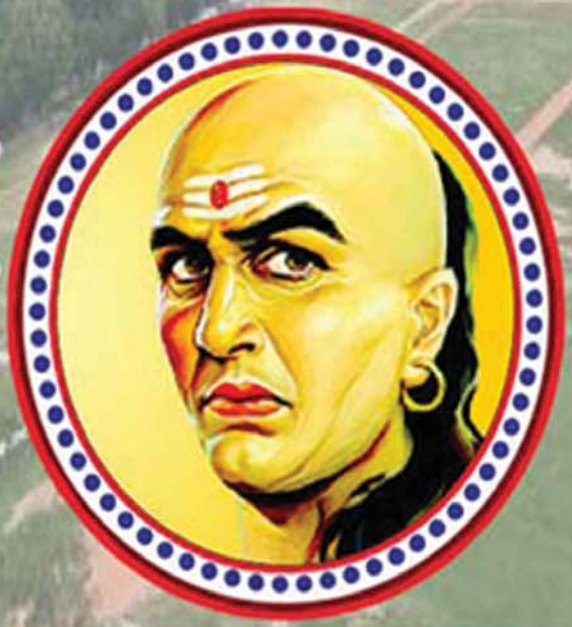

समय 11 बजे AM

1001 ब्राह्मणों के द्वारा सुन्दर कांड का पाठ

पारिवारिक प्रीतिभोज

परिवार के साथ पहुचें गाँधी मैदान, पटना

आयोजक

चाणक्य विकास मोर्चा

पता - पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

Mob. 9431073769, 9955077308

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

जैकी श्रॉप
01 फरवरी 1960

मनोज तिवारी
01 फरवरी 1971

ब्रह्मनंदम
01 फरवरी 1956

खुशवंत सिंह
02 फरवरी 1915

शमीता शेट्टी
02 फरवरी 1979

रघुराम राजन
03 फरवरी 1963

उर्मिला मांदोडकर
04 फरवरी 1974

अभिषेक बच्चन
05 फरवरी 1976

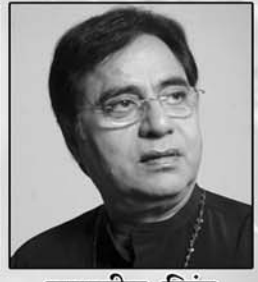

जगजीत सिंह
08 फरवरी 1941

मो० अजहरूद्दीन
08 फरवरी 1963

राहुल रॉय
09 फरवरी 1968

उदिता गोस्वामी
09 फरवरी 1984

कुमार विश्वास
10 फरवरी 1970

चौधरी अजीत सिंह
12 फरवरी 1939

स्व० सुषमा स्वराज
14 फरवरी 1952

टेकलाल महतो
15 फरवरी 1945

रणधीर कपूर
15 फरवरी 1947

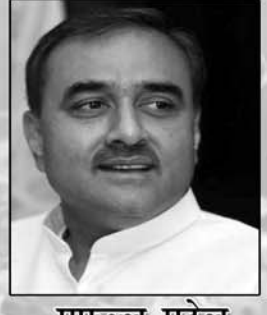

प्रफुल्ल पटेल
17 फरवरी 1957

स्व० जयललिता जयराम
24 फरवरी 1948

शाहीद कपूर
25 फरवरी 1981

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

अब कैसी आजादी.!

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

एक डफली बजाता है और बाकी लोग थपड़ी और मिलकर आजादी मांग रहे हैं और कैसी आजादी मांग रहे हैं यह पूरी दुनिया देख रही है और सच तो यही है की डफली पर हाथ भले ही हिन्दुस्तानी का हो पर वह ताकत कहीं और से मिल रही है जिसको इस देश की आजादी और संविधान से खतरा है। पहले सनातन धर्म वाले भगवान के अराधना में डफली बजाते थे लेकिन आजादी के बाद वामपंथी विचार वाला डफली बजाता रहा लेकिन कुछ ऐसे चंद युवा जिन्हें आजादी में ही गुलामी का एहसास हो रहा है, वह अपने चंद युवाओं के साथ किसी मंच पर डफली के साथ खड़ा होकर उनलोगों की आजादी का मांग कर रहा है जिनका उद्देश्य भारत को बेवस करना है। पहले जेएनयू का छोरा डफली बजाता था अब तो बिहार के पप्पु यादव भी वहीं मोर्चा संभाल रहे हैं और आजाद भारत में आजादी मांग रहे हैं। संविधान के महानायक के प्रति आस्था रखने वाले लोग शायद संविधान के रचयिता को मानते हैं परन्तु उस संविधान को नहीं जिसमें आजादी का क्या मायने बताया गया है। भारत की जनता ने डफली बजाकर सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों को वर्ष 2014 में सत्ता में आने से रोक दिया और 2019 में मोदी को प्रचंड बहुमत देकर देशहित ठोस कानून लागू करने का अधिकार सौंप दिया है जिसके बाद 2019 में कई समस्या से एक साथ निजात दिलाने का सरकार के प्रयास ने डफली बजाने वाले लोगों को रोजगार दे दिया है क्योंकि देश की जनता मोदी के किये गये निर्णयों का कितना समर्थन करती है या नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। जेएनयू के नेता रहे कन्हैया अब वामपंथ का नेता हो चुके हैं और आजादी मांगते-मांगते देश का युवाओं को गोलबंद करना चाहते हैं लेकिन बेगूसराय की जनता ने उन्हें क्षेत्र से दूर रहने की आजादी दे दी है। कन्हैया भले ही डफली बजाकर राजनीतिक ड्रामा करके मीडिया के सुर्खियों में बना रहे लेकिन कन्हैया ने कभी जेएनयू में चल रहे सेक्स का खेल से आजादी नहीं मांगी! देश को मजबूत बनाने वाले छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई के नाम पर चरस-गांजा-अफीम का मजा ले रहे हैं उससे कभी आजादी की मांग नहीं की! जेएनयू में इंस्तेमाल कंडोम का घिनौना सच से आजादी की मांग कभी नहीं की? आजादी के मतवालों को समर्थन में आयी दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म का छपाक का लाभ जेएनयू के उन वामपंथी छात्रों को दे देना चाहिए जो आजादी मांग रहे हैं जैसा की अजय देवगन की फिल्म तानाजी का कमाई राम मंदिर में दान कर दिया है। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी हिन्दुस्तान की खूबसूरती को पहले भी जयचंदों की वजह से बिगड़ी थी और अब तो जयचंदों की संख्या भी इस देश में बहुतात हो गये हैं और आजादी मांग रहे हैं। 85 हमारा - 15 तुम्हारा की राजनीति की बात करने वाले आजादी के दिवाने को क्यों नहीं समझ में आता की देश की बागडोर 85 प्रतिशत वाले के पास ही है और देश का वजीर नरेन्द्र मोदी और महावजीर रामनाथ कोविन्द सहित देश के विभिन्न हिस्सों में राजा कौन है और आपको किससे आजादी चाहिए? देश में समानता की बात करने वाले बिरादरी अपने बिरादरी का कितना विकास की है वह उसकी बिरादरी ऑफ द रिकार्ड में सबकुछ बताती है लेकिन जाति आधारित राजनीति के दलदल में धंसा भारत की सभी जाति अपने ही नेताओं से आजादी चाहती है भले ही उनके सामने मौन बनी रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक योजना ही योजना है, क्या उससे आजादी चाहिए? 2 रू० किलो अनाज, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सैकड़ों योजना से आजादी चाहिए जो मुफ्त में मिल रही है? टैक्स हमारा, योजना तुम्हारा उससे आजादी चाहिए? कैसी और कितनी तथा किससे आजादी चाहिए? भारत सरकार को मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं अन्य किसी मामले में मोदी की सरकार को घेरने में नाकामयाब दस्ता डफली बजाकर सत्ता से आजादी मांग रहा है और देश की जनता सत्ता मोदी को सौंप चुकी है और जिसके लिए वह आजादी मांग रहा है वह आजादी मांगने वाले डफली की धुन सुनने के बजाय देश के वोटरों ने 2019 में 2014 से अधिक सीट पर विजय बनाकर आजादी दे चुकी है। देश की मीडिया भी समस्या के समाधान का रास्ता बताने के बजाय बयानों से देश कैसे सुलग सकता है की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है और मोदी की सरकार भी बड़े घरानों की मीडिया को और बड़ा करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्थानीय स्तर पर बुनियादी आवाज वाले पत्रकारिता को विज्ञापन नीति से लाचार बना चुकी है जिसकी वजह से आजादी जैसे समस्याओं पर वह फंस जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और कुछेक राज्यों में आजादी मांगने वाले भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि आजादी दिलाकर यह अपना नाम अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले क्रांतिवीरों की जगह ले सकें। आखिरकार कन्हैया और पप्पु यादव कैसी आजादी की डफली बजा रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है और वास्तव में आजादी के पीछे दम है तो सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और अगर समझ से परे है तो इन्हें राजनीति से आजादी मिलनी चाहिए....

15 अगस्त 1947 की आजादी और 26 जनवरी 1950 का संविधान पर ही आजकल भीमराव अम्बेडकर को आदर्श मानने वाले ही डफली बजाकर आजकल आजादी मांग रहे हैं। ऐसे में एक सवाल का जन्म लेना स्वाभाविक है की आखिरकार डफली बजाकर यह किस चीज की आजादी मांग रहे हैं? पहले यह आजादी जेएनयू में ही मांगते थे, लग रहा था कि छात्रों की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं परन्तु जेएनयू के कैंपस से निकलकर अब पूरे देश में जब आजादी मांगने लगे तो देशवासियों का कान खड़का की आखिरकार यह किस चीज की आजादी मांग रहे हैं? बेशर्मी का हद तो यह है की जब यह आतंकवादी से आजादी नहीं मांगते, बल्कि आतंकवादियों के लिए आजादी मांग रहे हैं। हर-हर मोदी, घर-घर मोदी का मुकाबला घर-घर से अफजल निकलेगा कहकर करना चाहते हैं जिसको देश की जनता ने 2014 एवं उससे भी अधिक प्रचंड बहुमत देकर 2019 में भी मोदी के हाथ में सिंहासन सौंप दिया। इन्हें आजादी समस्या से नहीं बल्कि समाधान से है और ऐसे डफली के राग पर नाचने वालों को यह चंद लोग आजादी के नाम पर नचा रहे हैं। इन्हें आरक्षण चाहिए, इन्हें सरकार की सभी योजना चाहिए चाहे वह योजना लेने वाला सम्पन्न ही क्यों नहीं हो, इन्हें एससी/एसटी एक्ट चाहिए। देश के संविधान में भरोसा दिलाना चाहते हैं और जब उसी संविधान से कार्य हो रहा है तब भी आजादी मांगने वाले देश को आग में धकेलना चाहते हैं। सरकार की संपत्ति जलाने की आजादी चाहिए? आजाद लोकतंत्र में कैसी आजादी की मांग हो रही है की राजनीति से देश का युवा के भीतर आक्रोश है..

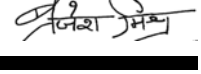

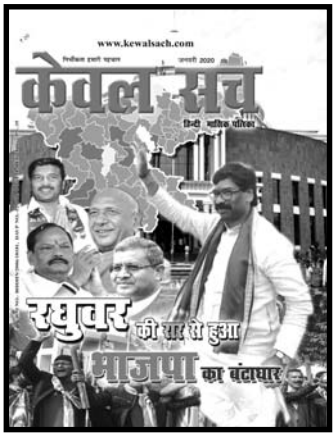

जनवरी 2020

हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769, 9955077308
kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

शिक्षा

संपादक जी,

आपकी पत्रिका केवल सच का मैं नियमित पाठक हूं और जनवरी 2020 अंक पढ़कर लगा की वास्तव में केवल सच पत्रिका अपनी सच्चाई के लिए पहचान बनाने में कामयाब हैं। इस अंक में प्रकाशित खबर सही मायने में देशवासियों का आंख खोलने वाला है चाहे वह नागरिकता का बिल हो या फिर कुर्सी बनाम कुर्सी का खबर हो। रघुरदास की खबर हो या साक्षात्कार सभी गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ लिखा गया है वह बधाई योग्य है।

✦ **संतोष साह, लहेरियासराय चौक, दरभंगा**

आर्यभट् के अवतार

ब्रजेश जी,

ललन कुमार प्रसाद की खबर जनवरी 2020 अंक में गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के जीवन एवं लक्ष्य को केन्द्र बनाकर लिखा गया वह काफी सराहनीय एवं प्रंशसनीय है। ''आर्यभट्ट के अवतार थे डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह'' खबर में गांव की मिटट्ी से लेकर राजधानी की राजनीति के सभी दांव-पैतरे को बखूबी लिखा गया है। इस प्रकार की खबर समाज में लोगों को बेहतरीन कार्य के लिए प्रेरित करती है और सकारात्मक पत्रकारिता का भी परिचय देता है।

✦ **मोहन सिंह, सिंह मॉर्केट, धनबाद**

नागरिकता बिल

मिश्रा जी,

जनवरी 2020 के अंक में ललन कुमार प्रसाद की खबर ''भारी संवैधानिक भूल का सुधार है नागरिकता संशोधन बिल'' में पूर्व एवं वर्त्तमान सरकार की नीति एवं नियति पर बहुत ही सटीक समीक्षा करके आपने देशवासियों के बीच गंभीरता से इस विषय पर सोचने को विवश करता है। नागरिकता बिल की सच्चाई को समझे बगैर देश में अस्थिरता का वातावरण खड़ा करके मोदी के विरोध के आड़ में देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। आपकी यह खबर देश की ज्वलंत समस्या को उजागर कर रही है। सटीक लेख के लिए धन्यवाद।

✦ **अभिजीत बनर्जी, श्याम बाजार, कोलकाता**

कुर्सी बनाम कुर्सी

संपादक जी,

आपकी खबर दिल को झकझोर देती है और केवल सच, पत्रिका बिल्कुल केवल सच ही लिखती है। जनवरी 2020 अंक में संपादकीय कुर्सी बनाम कुर्सी संपादकीय में आपने वर्त्तमान समय का सारा सच उजागर करने का मजबूत साहस किया है। आपकी लेखनी एक दिन पूरे देश में क्रांति को जन्म देगी। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीतिक कहानी को आपने अपनी लेखनी के माध्यम से समझाने का सार्थक प्रयास किया है। ऐसी खबरें न सिर्फ समाज को जागृत करेगी बल्कि राजनीति को भी नई दिशा मिलेगी इसमें कोई शक नहीं है। समीक्षात्मक खबर है।

✦ **कुमुद कुमार, राजा बाजार, पटना**

भाजपा का बंटाधार

ब्रजेश जी,

अमित कुमार एवं कामोद कुमार कंचन की झारखण्ड विधानसभा चुनाव 2019 के परिणाम का मजबूत खबर जनवरी 2020 के अंक में ''रघुवर की रार से हुआ भाजपा का बंटाधार'' खबर में सरयू राय की खबर को प्राथमिकता से भी प्रकाशित किया है तथा चुनाव में करारी हार का कारण की बेहतरीन समीक्षा किया है। झारखण्ड की समस्याओं से संबधित बातों को भी और रघुवर दास के अहंकार की विभिन्न पहलुओं को भी गंभीरता के साथ रखकर यह आलेख तैयार किया है जिसको पढ़ने के बाद राजनीति के बारीकी को समझना आसान है।

✦ **प्रमोद किशोर, सेक्टर 6, बोकारो, झा**

स्थापना वर्ष

मिश्रा जी,

जनवरी 2020 अंक के केवल सच पत्रिका में दिसम्बर 2019 में दिल्ली में हुए कार्यक्रम की खबर वास्तव में बिहार का सिर गर्व से उंचा करता है की बिहार की पत्रिका देश की राजधानी दिल्ली में भी अपना झंडा गाड़ने में कामयाब है। लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 69वीं पुण्यतिथि को युवाओं के बीच मनाकर देश के महापुरूषों के विषय में जानकारी वितरण करने का प्रयास प्रशंसनीय है। केवल सच की खबर और कार्यक्रम भारत के गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने का प्रयास कर रहा है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है।

✦ **जितन्द्र श्रीवास्तव, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली**

अन्दर के पन्नों में

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 14 अंक:- 166 माह:- फरवरी 2020, मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

गोपाल मिश्र **0612/2362784**

संपादक

ब्रजेश मिश्र

09431073769

09955077308 08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

सच्चिदानन्द मिश्र 09431878843

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 09430888060, 08873004350

अमोद कुमार 09431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 09308815605, 09122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

रीता सिंह 7004100454, 9308729879

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उपसंपादक

शिवचन्द्र झा 7488742471, 8521329144

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 9576438501

अजित कुमार त्रिपाठी 9430826676, 9294942868

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

संजीव रंजन तिवारी 9430915909

कृष्ण कुमार चंचल 9430520291, 7870421678

संदीप स्नेह 9971679857, 9667977987

रविन्द्र कुमार सिंह 7004238997, 9576084702

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 09608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 09308454485

रणविजय सिंह यादव 09334612716, 09801111138

रवि कुमार पाण्डेय 09507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

प्रिया सिंह मौर्य 7764062233

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 09905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 08002647553, 09060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 09905203164

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 7654122344, 7979769647

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो चीफ

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:-	अभिषेक मिश्र	09431732481
साहेबगंज	:-	अनंत मोहन यादव	09546624444
खूँटी	:-		
जमशेदपुर	:-		
हजारीबाग	:-	शैलेश मेहता	09973027485
जामताड़ा	:-		
दुमका	:-		
देवघर	:-		
धनबाद	:-		
बोकारो	:-	विनय कुमार सिंह	07903166519
रामगढ़	:-	दिव्य प्रकाश सिंह	08227979999
चाईबासा	:-		
कोडरमा	:-		
गिरीडीह	:-		
चतरा	:-	धीरज ठाकुर	09430353639
लातेहार	:-	रविकांत पासवान	09801637947
गोड्डा	:-		
गुमला	:-		
पलामू	:-		
गढ़वा	:-		
पाकुड़	:-		
सरायकेला	:-		
सिमडेगा	:-		
लोहरदगा	:-		

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	09470709185
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
भोजपुर	:-		
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-	मयंक कुमार	9852569398
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-	ललन प्रसाद	6299793069
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-	रवि शंकर कुमार	6204758273
बेगूसराय	:-	निलेश कुमार	9113384406
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-	सनोज कुमार	9955672241
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	अविनाश कुमार	9470659050
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-		
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-		
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:-		
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-		
नवगछिया	:-		
बांका	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०-09868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०-09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
रिया प्लाजा, फ्लैट नं0-303,
कोकर चौक, राँची-834001
मो०- 9955077308, 9431073769

मध्य प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास,
बेलभाँटा, अभनपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो०-09835845781,
08602674503

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश कुमार मिश्रा 07992327070
09631400205

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 09433567880
09339740757

उत्तर प्रदेश हेड
गदाधर नाथ मिश्रा 09452127278

महाराष्ट्र हेड
कमोद कुमार कंचन 07783822144

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 7492868363

उत्तर प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उत्तराखण्ड कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

गुजरात कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

राजस्थान कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

हरियाणा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

कर्नाटक कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उड़ीसा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

आसाम कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- शम्भू नाथ मिश्र
रेलवे गेट नं.- 02 राजेन्द्र नगर
वार्ड नं.- 08, लंका, पोस्ट- लंका
जिला-नगावँ, दिसपुर (आसाम)
मो०- 08135023285, 07631376135

एक नजर इधर भी

जमुई के सिकन्दरा के अकोनी गांव में एक गाय ने चार बछड़े का जन्म दिया है। चारो बछड़े स्वस्थ है। इसमें से एक बाछा और 3 बाछी है।

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए-17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- United Bank Of India
IFSC Code :- UTBI0KKB463
PAN No. :- AAJFK0065A

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

देवब्रत कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी

53 ठाकुरगंज विधानसभा

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

8986196502/9304877184

devbartkumar15@gmail.com

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009

09437029875

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.)

N.B.C.C

08877663300

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, आई. टी. विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी, रालोसपा	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

www.kewalsach.com

विशेष प्रतिनिधि

राजेश कुमार मिश्र	8757834700, 7004296529
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
कामोद कुमार कंचन	8971844318, 9110187832
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
विवेक कुमार मिश्र	7461803110,
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
प्रणव कुमार कश्यप	8809903185
सलाम साबरी	9835094832
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
अजय कुमार	8409103023, 6203723995
राजेश कुमार	7632936806, 7563816708
अवधेश कुमार शर्मा	9304827131, 8789324045
शिव कुमार ओझा	9162841133, 9162746866
राजमंति पाण्डेय	6201672831, 9155794800
वंदना सिंह	7903669215,

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000,	9431096964
मुकेश कुमार	9835054762,	9304377779
जय प्रसाद	9386899670,	
कृष्णा प्रसाद	9608084774,	9835829947

तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने केजरीवाल

● **संजय कुमार सिन्हा**

62 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रुप में उभर कर सामने आई आम आदमी पार्टी ने सबको हैरान कर दिया। बीजेपी ने अपना पुरा जोश के साथ चूनाव मैदान में काम किया परंतु उसे मात्र आठ सीटों से संतोष करना पड़ा। राजनिति के गलियारे में भी बीजेपी को कमसे कम 20 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। पिछले चूनाव के मुकाबले इस बार के चूनाव मे बीजेपी की मत प्रतिशत 6.5 बढ़ा है परंतु सीट मे मात्र पांच का ही इजाफा हो पाया और पिछले 3 सीट के मुकाबले 8 सीट पर जीत हासिल हुई। पिछले चुनाव के परिणाम को जनता एक क्रांती या आँधी मानती थी जिसमे 67 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी।दूसरे तरफ 3 सीटों पर बीजेपी को छोड़ दें तो काँग्रेस का सुफरा साफ हो गई थी। काँग्रेस की सुफरा तो इस बार भी साफ है यहाँ तक की उसके 66 उम्मीदवार में 63 के जमानत राशि चुनाव आयोग वापस नहीं लौटायेगी जबकि उसके सहयोगी दल राजद के चार प्रत्याशी मे तीन के जमानत राशि आयोग नहीं लौटायेगी। इस चुनाव मे बीजेपी को कोई स्पेश नहीं मिला जैसे अमूमन किसी चुनाव मे मिलता है। बहुजन समाज पार्टी मैदान में तो थी परंतु उसने अपने कोर वोटर के वोट भी नहीं ले सकी और सभी वोट केजरीवाल को सिफ्ट कर गया। समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं थी, जबकि जदयू और लोजपा से बीजेपी के तालमेल थे और इन दोनों पार्टीयों के एक-एक सीट पर उम्मीदवार खड़े थे। दूसरी तरफ काँग्रेस से तालमेल कर राजद भी चार सीट बंटवारे मे लेकर प्रसन्न थी। जबकि ऐसे पार्टीयों का कोर मत हमेशा राष्ट्रीय पार्टी के विरूद्ध जाती है और इनके सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से अंतवोगत्वा बीजेपी को ही फायदा होता नजर आती। काँग्रेस ने तो अपने को चुनाव से बिल्कुल अलग कर लिया था। उसके कोई बड़े सभा नहीं हुये, सिर्फ उम्मीदवार अपने स्तर चुनाव मे लगे रहे। काँग्रेस अपने पिछले चुनाव से पांच प्रतिशत कम वोट लाई उसे सिर्फ 4.25 प्रतिशत वोट मिला। दिल्ली विधान सभा में 12 सीट सुरक्षित है जो कि सभी पर आम आदमी पार्टी की विजयी रही, खास बात रही कि इन सभी 12 सीटों पर कम से कम जीत का अंतर 12000 हजार वोटों का रहा है।

'अबदुल्ला हुआ दीवाना' :- दिल्ली चुनाव में काँग्रेस के लिए वही कहावत चरितार्थ हो गई,

बेगाना शादी में अबदुल्ला हुआ दीवाना। काँग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, चरण सिंह सापरा व दिल्ली प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली चुनाव परिणाम 11 जनवरी को परिणाम आने के पहले 1 बजकर 10 मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी हार का अफसोस न कर उन तीनों ने केजरीवाल को विकास वाली सरकार बता कर उन्हें बधाई दे दी और सैकुलर की जीत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काँग्रेस के सभी नेताओं के बाँडी व्यवहार यह बता रहा था कि यही हमारी जीत है। उन्होंने केजरीवाल की इस फ्री वाली राजनीति को विकास वाली सरकार बताने में कोई शर्म महसूस नहीं किया। कहावत चरितार्थ लगा 'बेगाने की शादी में अब्दुल्ला हुआ दीवान' काँग्रेस इतनी खुश कभी नहीं हुई जब उन्होंने मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, राजस्थान की ऐसेबली जीती थी। मीडिया और राजनितिक गलियारे जान चुकी थी कि काँग्रेस अपने को दिल्ली चूनाव से अलग कर चुकी हैं। अलका लांबा जो कि आम आदमी पार्टी से काँग्रेस का दामन थाम लिया था उन्हें अपने जमानत की राशि भी वापस नहीं

मिली। अलका लांबा ने मुस्लिमों के दिल जितने के लिए जामा मस्जिद के सीढ़ी पर सीएए कानून का विरोध किया उन्होंने मुस्लिमों के नेता बन कर सीएए के विरोध में ऐसे- ऐसे संवाद किया जिससे उन्हें बचना चाहिए था। उन्होंने यही पर नहीं रुका उन्होंने बिडियों कैमरे के सामने बुरक्का शो रुम मे जाकर बुरका पहना अलटर कराने के लिए दुकानदार को बोला और कैमरे के सामने बीजेपी को संदेश दिया कि आज बीजेपी को मेरे इस बुरका से उन्हें एक मुद्दा मिल जायेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि मेरे काम को जनता ने. सराहा और बीजेपी के हिन्दू मुस्लिम कार्ड को लोगों ने नकार दिया।

★ **फ्री की होगी राजनिति अब देश में :-** दिल्ली चुनाव मिल का पथ्थर साबित होगा अभी चुनाव परिणाम नहीं आये थे सिर्फ एक्जिट पोल आने के बाद ही मध्यप्रदेश सरकार बंगाल सरकार बिजली की कुछ युनिट फ्री देने की बात शुरु हो गई। आने वाले बिहार चुनाव मे भी ऐसा प्रयोग होगा ऐसी संभावना बढ़ गई है। अब श्वाल उठता है दिल्ली ऐसे प्रदेश में महिलाओं को डीटीसी बस में फ्री यात्रा, बीस हजार लीटर पानी प्रत्येक परिवार, 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार अभी फिलहाल लोंगों को मिल रही है। क्या ये फ्री दिल्ली ऐसे प्रदेश में होना चाहिए? दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहाँ प्रति व्यक्ति आय भारत के किसी प्रदेश से ज्यादा है। यही नहीं दिल्ली सरकार की आय भी जन्संख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक है। अगर ऐसे प्रदेश को केन्द्रीय अनुदान राशि कम दिया जाता और ऐसे प्रदेश जैसे-बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड व उत्तर प्रदेश के सरकारों के स्वास्थ सेवा में खर्च होता तो

दिल्ली विधान सभा 2020 चुनाव के आँकड़े

☞ आम आदमी पार्टी को 53.57 प्रतिशत वोट मिला, पिछले चुनाव में 54.34 प्रतिशत रहा था।

बीजेपी को 38.51 प्रतिशत वोट मिला, पिछले चुनाव मे 32.1 प्रतिशत रहा था।

☞ काँग्रेस- 4.26 प्रतिशत वोट मिला, पिछले चुनाव मे 9.65 प्रतिशत रहा था। अन्य को 3.66 प्रतिशत वोट मिला, पिछले चुनाव मे 3.91 प्रतिशत रहा था।

☞ सबसे अधिक अंतर से विजयी उम्मीदवार क्षेत्र-बुराड़ी, आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 88158 हजार वोट से विजयी हुए।

☞ सबसे कम अंतर से विजयी उम्मीदवार क्षेत्र बिजवासन रहा, जहां आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह 895 वोट से विजयी हुए।

☞ आम आदमी पार्टी से हटे या टिकट नहीं दिये गए वैसे आठ उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाये गये थे, जिसमे सिर्फ गाँधीनगर से बीजेपी से चुनाव लड़े अनिल बाजपेयी ही चुनाव जीते।

☞ काँग्रेस से तीन उम्मीदवार अपना जमानत की राशि वापस आयोग से ले पाये। उसमे गाँधीनगर विधान सभा से अरविंदर सिंह लवली, बादली विधान सभा से देवेन्द्र यादव, कसतूरबा नगर विधान सभा से अभिषेक दत्त हैं।

ऐसे प्रदेशों से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा के लिए आने वाले का भीड़ कम होती। दिल्ली में पहले से ही राशन कार्ड पर मिलने वाले मिट्टी के तेल के बदले गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाता है। ऐसे भी एक विकासशील देश जो विकसित देश होने की सोच रखता है उसे ऐसी फ्री की अर्थव्यवस्था से बचनी चाहिये।

★ **मुस्लिम तुष्टिकरण काँग्रेस को साथ नहीं दिया :-** मुस्लिम तुष्टिकरण के अगुआ काँग्रेस ने इस दिल्ली विधानसभा में बता दिया कि अब हम काँग्रेस के बंधुआ नहीं रहे। लोक सभा चुनाव में जहाँ मुस्लिमों के पड़े मत का 90 प्रतिशत तक काँग्रेस को वोट मिले वहीं इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने पहले वफा की इस बार हिन्दू के वोट ज्यादा किसे मिलने वाले है? आम आदमी पार्टी को या काँग्रेस को फिर उन्होंने अपना मन बनाया कि केजरीवाल सरकार के इस फ्री स्किम मे बड़ी संख्या हिन्दूओं का आम आदमी पार्टी के साथ होगा फिर क्या था, उधर शाहीनबाग के समर्थन यानि कि सीएए के बिरोध मे पोलराइट हुये शत प्रतिशत मुस्लिम देखते-देखते आम आदमी पार्टी के साथ हो लिये। काँग्रेस ने अपने 66 टिकट विधानसभा में बाटे थे उसमे पांच बड़े नाम मुस्लिम उम्मीदवार मतीन अहमद, अली मेहंदी, परवेश हाशमी, हारुन युसूफ व मिर्जा जावेद अली घोषित हुये थे। वे पांचो अपनी जमानत की राशी तक चूनाव आयोग से वापस लेने लायक उन्हें वोट नहीं मिला, जबकि चार सीट राजद को मिले उसमे भी उन्होने किराड़ी विधान सभा में डा. रियाजुद्दीन को दिया था उनकी भी जमानत राशि चली गई। काँग्रेस अपने को मुस्लिम समाज के वोटों मालिक समझते रहा है ये पीछे आजादी के बाद से ही ऐसा सोच काँग्रेस ने पाल रखा था। जो पिछले 1989 के लोक सभा चुनाव के बाद से नहीं रहा अब उनके अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टीयां है।

Delhi Assembly Poll Outcome 2020

Constituency-wise winners and victory margin

	Constituency	Winner	Runner-up	Victory Margin
1	Nerela	AAP	BJP	17,429
2	Burari	AAP	JD(U)	88,158
3	Timarpur	AAP	BJP	24,144
4	Adarsh Nagar	AAP	BJP	1,589
5	Badli	AAP	BJP	29,123
6	Rithala	AAP	BJP	13,873
7	Bawana	AAP	BJP	11,526
8	Mundka	AAP	BJP	19,158
9	Kirari	AAP	BJP	5,654
10	Sultanpur Majra	AAP	BJP	48,052
11	Nangloi Jat	AAP	BJP	11,624
12	Mangol Puri	AAP	BJP	30,116
13	Rohini	BJP	AAP	12,648
14	Shalimar Bagh	AAP	BJP	3,440
15	Shakur Basti	AAP	BJP	7,592
16	Tri Nagar	AAP	BJP	10,710
17	Wazirpur	AAP	BJP	11,690
18	Model Town	AAP	BJP	11,133
19	Sadar Bazar	AAP	BJP	25,644
20	Chandni Chowk	AAP	BJP	29,584
21	Matia Mahal	AAP	BJP	50,241
22	Ballimaran	AAP	BJP	36,172
23	Karol Bagh	AAP	BJP	31,760
24	Patel Nagar	AAP	BJP	30,935
25	Moti Nagar	AAP	BJP	14,072
26	Madipur	AAP	BJP	22,719
27	Rajouri Garden	AAP	BJP	22,972
28	Hari Nagar	AAP	BJP	20,131
29	Tilak Nagar	AAP	BJP	28,029
30	Janakpuri	AAP	BJP	14,917
31	Vikaspuri	AAP	BJP	42,058
32	Uttam Nagar	AAP	BJP	19,759
33	Dwarka	AAP	BJP	14,387
34	Matiala	AAP	BJP	28,075
35	Najafgarh	AAP	BJP	6,231
36	Bijwasan	AAP	BJP	753
37	Palam	AAP	BJP	32,765
38	Delhi Cantt	AAP	BJP	10,590
39	Rajinder Nagar	AAP	BJP	20,058
40	New Delhi	AAP	BJP	21,697
41	Jangpura	AAP	BJP	16,063
42	Kasturba Nagar	AAP	BJP	3,165
43	Malviya Nagar	AAP	BJP	18,144
44	R.K. Puram	AAP	BJP	10,369
45	Mehrauli	AAP	BJP	18,161
46	Chhatarpur	AAP	BJP	3,720
47	Deoli	AAP	BJP	40,173
48	Ambedkar Nagar	AAP	BJP	28,327
49	Sangam Vihar	AAP	JD(U)	42,522
50	Greater Kailash	AAP	BJP	16,809
51	Kalkaji	AAP	BJP	11,393
52	Tughlakabad	AAP	BJP	13,758
53	Badarpur	BJP	AAP	3,719
54	Okhla	AAP	BJP	71,827
55	Trilokpuri	AAP	BJP	12,486
56	Kondli	AAP	BJP	17,907
57	Patparganj	AAP	BJP	3,207
58	Laxmi Nagar	BJP	AAP	880
59	Vishwas Nagar	BJP	AAP	16,457
60	Krishna Nagar	AAP	BJP	3,995
61	Gandhi Nagar	BJP	AAP	6,079
62	Shahdara	AAP	BJP	5,294
63	Seemapuri	AAP	LJP	56,108
64	Rohtas Nagar	BJP	AAP	13,241
65	Seelampur	AAP	BJP	36,920
66	Ghonda	BJP	AAP	28,370
67	Babarpur	AAP	BJP	33,062
68	Gokalpur	AAP	BJP	19,488
69	Mustafabad	AAP	BJP	20,704
70	Karawal Nagar	BJP	AAP	8,223

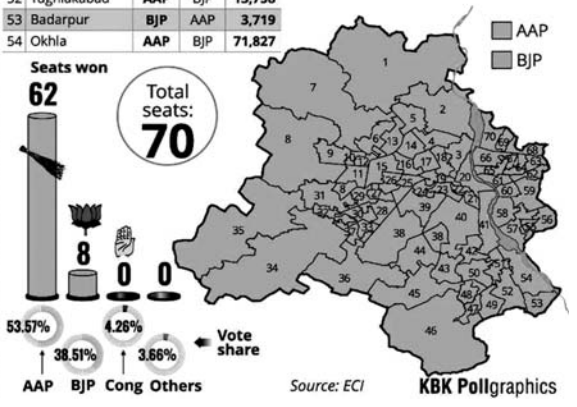

बिहार में राजद, यूपी में बसपा और सपा बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृण मुल काँग्रेस या वामपंथी दलों इसी तरह दक्षिण भारत के राज्यों में भी अलग-अलग पार्टीयां इनके पसंद के होते हैं। हाँ मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय में अच्छी पकड़ है। क्योंकि यहाँ और पार्टी नहीं है क्षेत्रीय दलों जैसे। सबसे मजे की बात तब होती है जब किसी विधानसभा या लोकसभा में मुस्लिमों की संख्या 50 प्रतिशत से पार रहती है तो इनके लिये एक और आँपसन होता है औवैसी की पार्टी और फिर उसकी जीत पक्की हो जाती है। भले वो बंगाल हो बिहार यूपी या महाराष्ट्र अब प्रश्न है काँग्रेस अपना अधार कैसे बढ़ाती है फिलहाल वो हार के बाद भी इतनी खुश है कि जैसे उसे केन्द्र मे सरकार मिल गई हो मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ के शब्दों में-जनता ने केवल विकास की बात की। पर सबसे बड़ी बात है कि इतनी लंबी-चौड़ी बातें करने वाली भाजपा का क्या परिणाम हुआ। इसी तरह पी. चिदंबरम ने - आप की जीत हुई।

दिल्ली जहाँ भारत के सभी हिस्सो के लोग हैं, ने भाजपा के ध्रूवीकरण विभानकारी और खतरनाक एजेंडे को हराया है। मैं दिल्ली के लोंगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने उन राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है जहाँ 2021 और 2022 में चुनाव होने वाले हैं।' इसी तरह लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री अधीश रंजन चौधरी ने भी आम आदमी पार्टी के जीत को जनता की जीत बताई। इससे साफ है कि आगे आने वाले समय में बिहार बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक दो सीट से ज्यादा इन्हें तालमेल मे सहयोगी दल नहीं देगी। ●

जेएनयू देश को कब तक गलत दिशा देगी

● संजय कुमार सिन्हा

हमारे देश के छोटे-छोटे कसबे शहर के विधार्थी जब जेएनयू का नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक समान्य होता है ऐसे विश्वविघालय के लिए। पर ऐसा है नहीं जेएनयू ऐसी विश्व विख्यात संस्था अपनी गरिमा हमेशा से खोती जा रही है, वो भले किसी जमाने में स्व. इन्दिरा गांधी के द्वारा भेजे गये दूत से जेएनयू प्रांगण मे तत्कालीन छात्र संघ नेता सीताराम येचुरी की पिटाई हो या अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जेएनयू प्रकरण में परिसर में उपस्थित होना। इसके बीच कन्हैया, राहुल गांधी, कुछ कशमिरी मुस्लिम छात्र नेता के द्वारा देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करना या समर्थन में खड़ा होना इनकी प्रतिष्ठा और विश्वनियता कम करता है। और ऐसे छात्र जो छोटे कसबे के है उन्हें ये सब समझ नहीं आ पाती या समझते हैं तो वैसे संस्थान से घृणा करते हैं। अगर छोटे शहर के विधार्थी अपने विधालय, महाविधालय या विश्वविधालय मे तोड़फोड़ करे तो उनको संस्थान से नाम काट दिये जाते हैं अन्यथा कभी भी उन्हें मागने पर अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते हैं। लेकिन इन सब से अलग दुनिया का अलबेला ऐसे कुछ विश्वविधालयों के जिसमे जेएनयू के अलावे अलीगढ़ मुस्लिम, जामिया मिलिया, यादवपुर जैसे नामचीन विश्वविधालय के। छात्र ऐसे होते हैं कि अपने पसंद के कुलपति तय करते हैं और पसंद नहीं होने पर उनको हटाने पर अडिंग हो जाते हैं वे यही तक नहीं रुकते उनकी हुक्का पानी भी बंद कर देते हैं। जरुरत के हिसाब से उनकी पिटाई व घसीटाई भी की जाती है। इसके विपरित छोटे शहर के विधार्थी अगर कभी किसी जायज या नजायज मुद्दों पर अपने प्रोफेसर से बकछक या लड़ाई हो जाती

है तो वे कुछ दिनों तक उनसे नजर नहीं मिला पाते। लेकिन यहाँ आपको कुछ तिथिवार वाक्या याद दिलाना चाहूगा- 25मार्च, 2019 को छात्रों ने कुलपति के घर में जबरन घुस कर हुड़दंग मचाया जिसे देखकर कुलपति की पत्नी बेहोश हो गई थी।

☆ **कैमरा मीडिया का दोगला चरित्र भी सामने आया :-** जेएनयू में हिंसा के बाद एक ग्रुप फौरन सक्रिय हो गया और झूठी खबरें फैलाने लगा। झूठी कहानी के लिए अग्रनी पोर्टल न्यूजलाउंडी् और एकतरफा गलत रिपोंटिंग के लिए प्रसिद्व पत्रकार बरखा दत्त सबसे आगे रही। ये दोनों ने खबरें चलाई कि अस्पताल में भत्ती एबीवीपी के छात्रों को लगी चोटे बहुत ही मामूली है। लेकिन कुछ ही मिनटों में इसका पोल खुल गई कि जिस कथित डॉक्टर के हवाले से यह खबर फैलाई जा रही थीं उसका ऐम्स से कोई लेना देना ही नहीं था। बल्कि वह काँग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था। इन सभी बातों के खुलासा के बाद भी एकतरफा मीडिया झूठी खबरें फैलाती रही। वामपंथी विचारधारा के छात्रों के कारनामों को कैमरे में कैद होने के बाद भी अपने को पीड़ित बताते और दिखाते रहे। विपरित एबीवीपी के छात्रों को विलेन बनाने की कोशीश जारी रही। जबकि वामपंथी छात्र अध्यक्षा आईशी घोष नकाबपोश के साथ दिखने के बाद भी उसे काँतिकारी दिखाने के प्रयास जारी रहा इन सभी की जिम्मेवारी विवादित पत्रकार बरखा दत्त का सोशल मीडिया के माध्यम से जारी रहा। उन्होंने जाली स्क्रिन शाँट जारी किया जो कि बाद में उसका भी पर्दाफास हो गये ये सभी नंबर भी काँग्रेस के ही थे। एक सुनियोजित तरीके से अंतरास्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि खराब करने की कवायद चल रही थी। भारत के जाने माने पत्रकार विदेशों में लेख के द्वारा भारत की छवि खराब करने की योजना में लगे हुए रहे। न्यूयाँक टाईम्स ने छापा कि जेएनयू में हिंसा के

—: घटनाक्रम :—

☞ 28अक्टूबर 2019 को डीन ऑफ स्टुडेन्ट्स अशोक कदम को कन्वेंशन सेन्टर मे घेरा और उनकी तबियत बिगड़ने पर उन्हें एम्बलेंस से ले जाने नहीं दिया गया।

☞ 8 नवंबर 2019 एडीशनल डीन ऑफ स्टूडेंट्स वंदना मिश्रा को कक्षा में 26 घंटे से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखा। उनके साथ गाली-गलौज व हाथा पाई की गई और सबसे बड़ी शर्म की बात की उस कमरे में कोई भी शौचालय वाथरुम तक नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि एक महिला कैसे 26 घंटे बिताया होगा।

☞ 22 नवंबर, 2019 प्रोफेसर आनंद रंगनाथन को स्कूल ऑफ माँलीक्यूलर मेडिसिन की लैब में घुसने नहीं दिया उसके तीन सप्ताह बाद उन्हें अपने विभाग से जाने से रोका गया।

☞ 3 जनवरी, 2020 पूर्व छात्र संघ अध्यक्षा गीता कुमारी के नेतृत्व में वाई-फाई तंत्र और रजिस्ट्रेशन के सर्वर को बंद किया और क्षतिग्रस्त करके बंद कर दिया और वही पर धरने पर बैठ गई।

☞ 4 जनवरी, 2020 सुबह जब विश्विधालय के सुरक्षाकर्मी ने सर्वर क्षेत्र खुलवाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई और अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। दुबारा कमरा खोलने के लिए सुरक्षाकर्मी ने प्रयास किया तो छात्र संघ अध्यक्षा आईशी घोष के नेतृत्व मे मारपीट किया गया।

☞ 5 जनवरी, 2020 को जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्षा के नेतृत्व में 300से अधिक दिल्ली और देश के बाहर के गुडों को बुला कर लाठी डंडे रड से छात्रों को मार कर कईयो घायल कर दिया गया। ये जितने भी वाक्या हुआ ये सभी नक्सल या वामपंथी छात्र संघ परिवार रहा। उसके उपरांत अखिल भारतीय विधार्थी संघ के छात्रों ने भी 5 जनवरी के देर शाम वामपंथी विचारधारा को पिटने मे पीछे नहीं रहे।

दौरान जयश्रीराम के नारे लगे। समय आ गया है कि ऐसे नामचीन पत्रकारों के पोल खोलने की जिससे भारत की छवि खराब करने की साजिस का पर्दाफास हो और ऐसे पत्रकार प्रताड़ित हो उन्हें समान नहीं मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले आईआईटी कानपुर छात्रों और प्राध्यापकों के द्वारा अवैध रूप से बिना अनुमति के आईआईटी प्रांगण मे किया गया और विवादित पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज के विवादित नज्म गाई गई जिसका एक दूसरे प्रोफेसर ने आईआईटी प्रशासन से शिकायत की तो झूठी मीडिया ने भ्रम फैलाने लगा कि आईआईटी प्रशासन जाँच करेगी कि फैज की नज्म कही हिन्दू विरोधी तो नहीं। एक बेबसाइट ने फेक न्यूज पोस्ट कर दी कि शिकायत करने वाले प्रोफेसर वासी शर्मा दलित विरोधी हैं, दलित के सुधार प्रयास का विरोध करते हैं। ऐसे सारी खबरें 'दी प्रिंट' मीडिया ने फैलाई जिसके संपादक शेखर गुप्ता है जो झूठी खबर फैलाने के माहिर हैं, जो कि एडिटर्स गिल्ट के अध्यक्ष है। जिसका काम है कि पत्रकारिता के स्तर को बनाये रखना।

★ **जेएनयू पर अभी तक लिपा पोती** :- 5 जनवरी, 2020 को जेएनयू में हुई हिंसा में अभी तक लिपा पोती ही हुई है कारवाई नहीं। कहने को तो एसआईटी 29 लोगों से पूछताछ और 77 लोगों के बयान दर्ज कर चूकी है । लेकिन एसआईटी के मुताबिक अभी तक पुख्ता सबूत न मिलने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में एसआईटी फॉरेंसिक जाँच रिर्पोट के इन्तजार मे है। जबकि कई मामले में पुख्ता सबूत का इन्तजार है। अभी तक एस आईटी लोगों को नोटिस जारी कर रही है। क्राईम ब्राँच के हिसाब से जाँच के मामले में आये हुये व्यक्ति के ग्यारह मोबाईल अभी भी जब्त कर रखा गया है। अभी भी कई तरीके से जाँच किया जा रहा है। जिसमे एफएसएल की टीम भी जाँच कर रही है। ●

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब यूनिक पब्लिक स्कूल

21 वीं सदी की दस्तक के साथ ही यूनिक पब्लिक स्कूल 'बिहिया चौरास्त' गुणवतापूर्ण शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ किया, जो वर्तमान में जिला में द्वितीय व प्रखण्ड में प्रथम स्थान विगत कई वर्षो से प्राप्त किये है। जिसके फाउंडर व संरक्षक परम आरणीय श्री जनार्दन तिवारी है। जानकारों के अनुसार यूनिक पब्लिक 'बिहिया चौरास्ता' शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रत्येक मापदण्ड को पूरा करते हुये विगत कई वर्षो से गुणवतापूर्ण शिक्षा देने में अहम भूमिका रखता है। अपनी निजी भवन में संचालित होने वाला प्रखण्ड का प्रथम प्राइवेट विद्यालय है, जो शांतिपूर्ण व स्वच्छ वातावरण में छात्रों को शिक्षा दी जाती है। संयुक्त परिवार का मिशाल प्रस्तुत करते हुये विद्यालय में कुल लगभग 650 शिक्षक-छात्र है। विद्यालय में शिक्षा दे रहे शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक के साथ प्रशिक्षित भी है। जिसका श्रेय विद्यालय संरक्षक को दी जाती है। जबकि प्रखण्ड में अधिकतर प्राइवेट विद्यालय में दसवीं व इन्टर पास लड़कियों से शिक्षा दिलवाई जा रही है। अर्थात् दूसरे शब्द में - अधिकतर निर्देशक शिक्षा को व्यवसाय बना चुके है। जिससे ऊँची सोच रखने वाले निर्देशक को बदनाम कर रहे हैं। वही अधिकतर विद्यालय प्रत्येक वर्ष किताब भी बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय के निर्देशक शिक्षा के नाम पर स्कूल ड्रेस, टाई, बेल्ट और किताब की दुकान भी संचालित करते है। किसी-किसी प्राइवेट विद्यालय में सुविधा के नाम पर शौचालय व पेशाबखाना भी नही है, जो जाँच का विषय है। प्रिय पाठकगण आपलोगों को बताते चले कि यूनिक से शिक्षा प्राप्त कर अधिकतर बच्चे सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जिसका श्रेय विद्यालय में चलाये जाने वाली विशेष कक्षाएँ को दी जाती है। **रिपोर्ट :- बिन्ध्याचल सिंह**

भारत में एक नहीं कई कश्मीर

● ललन कुमार प्रसाद

यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों यानि हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के प्रति अपने वायदे निभाये होते तो नागरिकता अधिनियम में संसोधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत में मुस्लिम समाज के नेताओं और धर्मगुरूओं को यह सच स्वीकार करना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में वाकई आजादी के बाद से ही वहां के हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों पर लगातार जबरदस्त अमानवीय होता आ रहा है, जो आज भी जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर हिन्दू और सिख समुदाय के 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की लड़कियों पर पड़ा है। पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों की लड़कियों को अगवा करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना और फिर उनसे निकाह कराने का दस्तूर बन गया है। इसलिए भारत के मुसलमानों को नागरिकता संसोधन अधिनियम का स्वागत करना चाहिए, लेकिन भारत के ज्यादातर मुसलमान ठीक उलटा कर रहे हैं। साथ ही भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिदायद देनी चाहिए कि वे अपने यहां अल्पसंख्यकों यानि हिन्दुओं और सिखों के साथ प्यार से पेश आये। लेकिन भारत के मुस्लिम नेता और धर्मगुरू भारत की आजादी के समय से ही इस तथ्य की अनदेखी करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भारत के मुसलमान पूरे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश के विरोध में धरना- प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब 19 जनवरी 1990 को रातों-रात 4 लाख कश्मीरी पंडितों को जबरन कश्मीर से खदेड़कर भगा दिया गया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उनके हजारों घरों को आग लगा दी गई और कश्मीर की सड़कों पर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से खींच-खींचकर हत्या कर दी गई। जिससे वहां की सड़के कश्मीरी पंडितों के शवों से पट गयी थी। ऐसे में मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरूओं ने क्यों नहीं प्रदर्शन किया। आज भी भारत के मुसलमानों द्वारा देश में लव जेहाद के नाम पर यहां के हिन्दू लड़कियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। मसलन, एकदम से ताजा मामला केरल का ही ले लिजिए। वहां के सबसे बड़े चर्च के पादरी केरल सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ के मुस्लिम ईसाई लड़कियों और महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लोआयटेशन कर रहे हैं, फिर भी केरल सरकार चुप है। ये सब एकतरफा धर्म निरपेक्षता या इस्लामीकृत धर्म निरपेक्षता नहीं तो और क्या है?

संविधान निश्चित रूप से सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की किसी भी सूरत में आजादी नहीं देता है। ऐसे में तोड़-फोड़, आगजनी और हिंसा किये जाने का अधिकार दिये जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली के शाहीनबाग में बैठी तमाम मुस्लिम महिलाओं को धरना-प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नोयडा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क को पुरी तरह से बंद करके बंधक बनाने

का अधिकार हरगिज नहीं है। संविधान सड़कों को बंधक बनाकर पूरी तरह से जाम करके मुद्दे को सुलझाने का कोई अधिकार नहीं देता, चाहे मुद्दा जायज ही क्यों न हो? लेकिन नागरिकता संसोधन विधेयक का विरोध किया जाना तो सौ फिसदी अवैध है, क्योंकि सीएए संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित वहां के अल्पसंख्यकों यानि हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों को मानवीय आधार पर आश्रय देने वाला कानून है, यह मुस्लिम विरोधी नहीं है। सच तो यह है कि पिछले कुछ अरसे में उपर्युक्त तीनों देशों से आये छः सौ मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। यह कानून तनीक भी विभाजनकारी नहीं है। यह सच्चाई है कि नागरिकता संसोधन अधिनियम कानून का एक हिस्सा है, जिसे सभी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मेराथन बहस के बाद बहुमत से पारित किया गया है। ऐसे में सीएए के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करना किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। यह तो संविधान का खुल्लम-खुल्ला उलंघन है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पिछले लगभग पचास दिनों से शाहीनबाग स्थित नोयडा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क को बंधक बना लिया है। सड़क पर खाना बनाना, सड़क पर ही खाना खाना, सड़क पर तम्बू लगाकर रजाई-कंबल का इस्तेमाल कर आराम फरमाना, फ्री कश्मीर और जिन्ने वाली आजादी जैसे देश को तोड़ने वाली नारे लगाना। पांच साल, छः साल के छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों द्वारा देश विरोधी नारे लगवाना-'मोदी और शाह हमें मारने वाला है, हम उसे मारेंगे', 'जो हिटलर की चाल चलेगा, वह हिटलर की मौत मरेगा'। प्रदर्शन के नाम पर छोटे-छोटे बच्चों को शामिल किया जाना, छोटे-छोटे बच्चों पर जुर्म नहीं तो और क्या है? प्रदर्शनकारियों को छोटे-छोटे बच्चों पर जुर्म करने का अधिकार किसने दे दिया है? मुस्लिम महिलायें ऐसा क्यों कर रही हैं? याद रहे अम्बेडकर का चित्र लगाने, जन-गण-मन गाने और तिरंगा फहराने से असंवैधानिक कार्य कभी भी संवैधानिक नहीं हो सकता। शाहीनबाग में मुस्लिम महिलाओं के चलते स्थानीय लोगों के अलावा दिल्ली के अन्य मोहल्लों के लाखों लोगों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का व्यापार ठप पड़ गया है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मतलब सिर्फ धरना- प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि अव्यवस्था और अराजकता फैलाना है। जो सरासर संविधान का उलंघन है। यह संविधान के मूलभूत कर्तव्यों से जुड़े अनुच्छेद 51-ए का खुल्लम-खुल्ला उलंघन है, क्योंकि प्रदर्शनकारी आम आदमी के लिए जान-बूझकर ढ़ेर सारी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की दादागिरी संवैधानिक नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने वाली है। मोदी सरकार ने मुस्लिम बहु-बेटियों के लिए तीन तलाक हटवाया, जिससे की पुरूषों द्वारा उनका शोषण नहीं किया जा सके, उनकी भलाई के लिए हुनर कार्यक्रम चलाया, मुस्लिम विधवाओं को हजारों करोड़ रूपये की आर्थिक मदद दिलवा रही है, आज वही मुस्लिम महिलाएं सड़क जाम करके दादागिरी दिखा रही है। इससे तो अच्छा था कि तीन तलाक लागू ही रहता। यह मोदी सरकार के प्रति मुस्लिम महिलाओं की बेवफाई नहीं तो और क्या है?

शाहीनबाग में वहां के लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन का कवरेज करके टीवी पर प्रसारित करने के लिए बुलाया गया था, वही पर मौजूद कुछ लोगों ने दीपक चौरसिया, कैमरामैन सहित न्यूज नेशन के पत्रकारों पर हमला कर दिया। उनके कैमरे या तो तोड़ दिये गये या छिन लिए गये। उनकी पिटाई कर दी गई। बामुश्किल वे लोग भागकर वहां से कुछ दूरी पर स्थित पुलिस की गाड़ी में शरण लेकर अपनी जान बचाने में सफल हो गये। वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा टीवी के पत्रकारों और कैमरामैन पर हमला कर उनकी पिटाई कर देने को गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहेंगे? पूरे देश के मुसलमान और मुस्लिम धर्मगुरूओं ने कसम खा रखा है कि उन्हें सीएए कबूल नहीं है, इसलिए वे पूरे देश में सीएए के विरोध में धरना-प्रदर्शन और मानव श्रृंखला बना रहे हैं, जिन्हे उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जो मुस्लिमों के साथ, मुस्लिमों के विकास और मुस्लिमों के विश्वास के सिद्धांत पर चलते हैं। मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास

और सबका विश्वास के सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में देश का हिन्दू समाज, मुस्लिम समाज से काफी डर गया है। देश के हिन्दू समाज के मन में पैदा हो गया है कि मुसलमान, पूरे भारत को कश्मीर बना देंगे, हिन्दू मुक्त बना देंगे। ऐसे में भारत के हिन्दू समाज को भारत को हिन्दू राष्ट्र तुरंत घोषित किये जाने के लिए मोदी सरकार से गुजारीश करनी चाहिए और मोदी सरकार को भी हिन्दुओं के इस मांग को यथाशीघ्र पूरा कर देने का प्रयास करना चाहिए। पूरी दुनियां में 58 मुस्लिम देश है, लेकिन एक भी हिन्दू देश नहीं है। पूरी दुनियां में कम से कम एक तो हिन्दू देश होना ही चाहिए, यह एकदम अनिवार्य है। हिन्दुओं

का मूल देश भारत है, इसलिए मोदी सरकार को संसद में बिल लाकर भारत को हिन्दू देश घोषित कर दिये जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हिन्दुओं को सड़क-सड़क, गली-गली ऐसी तख्तियां लगानी चाहिए, जिसपर लिखा हो-'पूरे देश को कश्मीर बनने से बचाने के लिए भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करो', 'पूरी दुनियां में हिन्दुओं का वजूद मिटने से बचाने के लिए जरूरी है भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाना', 'हिन्दुओं का वजूद खतरे में है, इसलिए सभी हिन्दू जात-पात और ऊँच-चीन के भेदभाव को भुलाकर एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और सरकार की इस्लामीकृत एकतरफा धर्म निरपेक्षता का जोरदार विरोध करो', इत्यादि। मोदी सरकार से भारत के हिन्दुओं का नम्र निवेदन है कि वे भारत को संवैधानिक रूप से हिन्दू राष्ट्र घोषित करा दे, वरना देश की दूसरी पार्टियों के नेता निश्चित रूप से भारत को हिन्दू मुक्त कश्मीर बना देंगे। इसका प्रमाण है कांग्रेस पार्टी ने 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर 'पीओके' बनाया। कश्मीर में 370 और 35ए लागू किया और कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को जबरन खदेड़वा कर भगा दिया। इस मुद्दे पर भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां कांग्रेस का साथ दे रही है। इसलिए देश का समस्त हिन्दू समाज मोदी सरकार से हांथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिन्दू राष्ट्र बनाकर हिन्दुओं के मूल देश भारत में हिन्दुओं का खात्मा होने से बचा ले।

आज भारत में एक नहीं कई कश्मीर

है, जिसका असली श्रेय भारत की सर्वाधिक पुरानी पार्टी कांग्रेस को जाता है। ऐसा इसलिए कांग्रेस ने भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह इस्लामी देश तो नहीं, लेकिन इस्लामीकृत धर्म निरपेक्ष देश अवश्य ही बना दिया है। यदि कांग्रेस पुन: देश की सत्ता में आयेगी तो भारत को भी इस्लामिक देश बनाकर ही दम लेगी, क्योंकि इस घृणित कार्य में भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां कांग्रेस को भरपूर सहयोग दे रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। अत: इस घृणित कार्य को अंजाम तक पहुंचा देने के लिए कांग्रेस पार्टी बेताब है, इसके ढ़ेर सारे सबूत है। पहला सबूत है 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर यानि पीओके का निर्माण, दूसरा सबूत है महाराजा हरी सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किये जाने के बाद बगैर मंत्रीमंडल के सहयोगियों से राय लिये नेहरू जी द्वारा कश्मीर के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में ले जाया जाना, तीसरा सबूत है 26 जनवरी को अनुच्छेद 370 को प्रधानमंत्री के पद का दुरूपयोग कर 26 जनवरी को कश्मीर में अस्थायी रूप से लागू किया जाना, चौथा सबूत है देश की जनता को धोखा देकर अस्थायी अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में चोरी चुपके अनुच्छेद 35ए का लागू किया जाना, पांचवा सबूत है 19 जनवरी 1990 को चार लाख कश्मीरी पंडितों को उन्ही के मूल स्थान कश्मीर से जबरन खदेरवा कर कश्मीर से भगाया जाना, छठा सबूत है राहुल गांधी द्वारा जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी में देश के टुकडे-टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर उनकी हौसला अफजाही करना, सातवां सबूत है 2019 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में यह घोषित किया जाना कि अगर कांग्रेस पाटी सत्ता में आयी तो अनुच्छेद 124 ए को खत्म कर देगी, आठवां सबूत है दिल्ली के शाहीनबाग में असंवैधानिक रूप से चलाये जा रहे धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेताओं मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर द्वारा सौ फिसदी उनके धरना प्रदर्शन को अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया जाना, इत्यादि। शाहीनबाग के धरना प्रदर्शन का मकसद सिर्फ सीएए के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा अव्यवस्था और अराजकता तक फैला हुआ है। 27 जनवरी 2020 को रात 9 बजे न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया और जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी को धरना प्रदर्शन के स्थान तक नहीं जाने दिया जाना। शाहीनबाग में धरना प्रदर्शन के स्थल तक पुलिस को भी जाना एलाउड नहीं है। मुख्यत: मुस्लिम महिलाओं द्वारा किये जा रहे इस धरना प्रदर्शन को केजरीवाल के आप पार्टी का भरपूर समर्थन प्राप्त है, जिसकी घोषणा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कर रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की खासियत है कि उन्हे हर वह कार्य पसंद है, जिससे देश को टुकड़े-टुकड़े करने में मदद मिलती है। तभी तो जेएनयू में जाकर वे ना सिर्फ देश के टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस द्वारा कन्हैया कुमार और उमर खारिद के विरूद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किये जाने वाली अर्जी को वर्षो से दाबकर बैठे हुए हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं जब 29 दिसम्बर 2016 को भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और 26 जनवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने अपने ही देश की आकाशीय सीमा लांघकर पाकिस्तान में घूसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, तो केजरीवाल ने इन दोनो स्ट्राइक का सबूत मांगा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की बहादूरी के सबूत मांगे थे। आज शाहीनबाग की स्थिति है कि शाहीनबाग के डेढ़ किलोमीटर के दायरे से होकर गुजरने से हर हिन्दू डरता है। हिन्दू तो हिन्दू पुलिस भी शाहीनबाग के डेढ़ किलोमीटर के दायरे के अंदर जाने से डरती है। क्या शाहीनबाग का इलाका दिल्ली में कश्मीर नहीं तो और क्या है? आज दिल्ली में ही नहीं देश के कई भागों में छोटे-छोटे ढ़ेर सारे कश्मीर है। ऐसे में भारत में रह रहे यहां के मूल निवासी हिन्दुओं का क्या होगा? क्या वे अपने ही देश में आत्महत्या कर लिए जाने को मजबूर कर दिये जायेंगे? इसलिए अब जरूरी हो गया है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाना। आज वास्तविकता ता यह है कि पूरे देश का हिन्दू समाज, मुसलमानों की दादागिरी से त्रस्त है। पूरे देश में मुसलमानों द्वारा हिन्दू समाज के मुंह पर ताला जड़ दिया है और वोट के खातीर भाजपा को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां उनका साथ दे रही है, जिनमें पी. विजयन की कम्युनिष्ट पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और केजरीवाल की आप पार्टी अग्रणी है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने तो घोषणा कर दी है कि शाहीनबाग में धरना पर बैठी मुस्लिम महिलाओं को पुरस्कार देकर बहादूरी के लिए उन्हे सम्मानित करेंगे। पहले ही बहुत विलंब हो गया है, अब और अधिक विलंब किया जाना हिन्दुओं के लिए आत्मघाती होगा, उनके वजूद को मिटाने वाला होगा।

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व नेता खालिद उमर ने घोषणा कर रखी है कि भारत में बहुत ही जल्दी एक लाख शाहीन बाग बना देंगे। ऐसा इसलिए देश के तमाम मुस्लिम भाई हर तरह से उनका साथ दे रहे है, जिससे उनमें काम को

अंजाम तक पहुंचाने हेतु काफी ऊर्जा मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत के मुसलमान यहां के हिन्दुओं को किस नजर से देखते हैं। बिहार के जहानाबाद के शरजील इमाम, जो फिलहाल जेएनयू के छात्र हैं, ने देश के टुकड़े-टुकड़े करने के साथ ही भारत को इस्लामिक देश बनाने का ब्लू प्रिंट तैयार करके देश के विभिन्न हिस्सों में घूम-घूमकर अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन-रात एक किये हुए हैं। लेकिन संयोग से वे फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उनका प्लान है कि इस देश से पहले आसाम को अलग कर देगे और तब भारत सरकार को मजबूर कर देगे कि वह भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करे। दिल्ली की शाहीनबाग की तरह देश भर के हजारों अलग-अलग जगहों पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह इस्लामिक देश बना दिया जाये। मसलन, मुम्बई के नागपारा में धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाएं ताली बजा-बजाकर और हांथ उठा-उठाकर नारा लगा रही हैं 'शरजील तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचायेंगे'।

☆ **कश्मीरी पंडित और वहां के मुसलमान** :- वैसे तो आजादी के बाद से ही वहां के मुसलमान पाकिस्तान की सह पर कश्मीरी पंडितों पर अमानवीय जुल्म ठाहते रहे हैं, जिसकी वजह से 19 जनवरी 1990 के कई दशक पहले से ही कश्मीर से कश्मीरी पंडित खदेड़े जाते रहे हैं, लेकिन 19 जनवरी 1990 को वहां के मुसलमानों द्वारा कश्मीरी पंडितों पर अमानवीय जुल्मों का इंतिहास हो गया, जिसके कारण मजबूरन चार लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कश्मीर के मस्जिदों से उस दिन ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीरी पंडितों अपनी बहन-बेटियों को छोड़कर कश्मीर से बाहर चले जाओ, वरना तुम सबों की हत्या कर दी जायेगी और वहां के मुसलमानों द्वारा ऐसा किया भी गया। कश्मीर की सड़के, कश्मीरी पंडितों के शव से पट गयी। कितने हजार कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गयी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कश्मीर के मुसलमानों द्वारा हजारों कश्मीरी पंडितों के घरों में आग लगा दी गई, उनकी बहु-बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी ढ़ेर सारी मंदिरों को तोड़ दिया गया और उनकी जमीन-जायदाद को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया गया। आश्चर्यजनक है कि मस्जिद जहां खुदा की इबादत की जाती है, वहां से लाउड स्पीकर पर ऐसा फरमान सुनाया जाने लगा। मस्जिद के इमाम ऐसा करने के लिए मुसलमानों को उकसाते रहे। वहां के मस्जिदों के इमाम इस्लाम के नाम पर ऐसा क्यों किया? भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल दारूउलूम से यह फतवा क्यों नहीं जारी किया गया कि कश्मीर के मुसलमान इस्लाम के नाम पर कलंक हैं, इसलिए इनका समाजिक बहिष्कार कर दें। देश में जगह-जगह मुसलमानों द्वारा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? जुलूस क्यों नहीं निकाला गया कि कश्मीरी मुसलमान इंसान के रूप में शैतान है। इसलिए इनका समाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर देशभर के तथाकथित बुद्धिजीवी जो बात-बात पर पद्मश्री, पद्मभूषण तथा अन्य पुरस्कारों को लौटाते हैं या लौटा देने की धमकी देते हैं तो कश्मीरी पंडितों पर हुए दिल को दहला देने वाली जुल्म को लेकर अपने पुरस्कारों को क्यों नहीं लौटा देते हैं? अभी भी समय है आज ही अपने सभी पुरस्कारों को कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को लेकर लौटा दे। ऐसा करने से उन्हें कौन रोक रहा है। लेकिन, वे ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों को खुश रखना है। झूठमूठ के अपने आप को बुद्धिजीवी होने का नाटक क्यों कर रह हैं? क्या ऐसे बुद्धिजीवी बेशर्म नहीं तो और क्या हैं? क्या ऐसे बुद्धिजीवियों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर नहीं जाना चाहिए! ऐसे बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों के नाम पर कलंक नहीं तो और क्या हैं? ऐसे बुद्धिजीवियों का एक ही मकसद है, चाहे जैसे भी हो उन्हें शोहरत और दौलत मिलनी चाहिए। इसके लिए गलत मुद्दे को लेकर मुसलमानों का समर्थन करना पड़े तो करेंगे और सही मुद्दे को लेकर हिन्दुओं का विरोध करना पड़े तो करेंगे। ऐसे लोग मुगल बादशॉह औरंगजेब का गुण गाते नहीं थकते और देशभक्त सावरकर को गाली देते नहीं थकते। धिक्कार है देश के ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों पर।

☆ **देश के गद्दार हैं सीएए के विरोधी** :- भारत का कोई भी नागरिक या किसी भी पार्टी के नेता जो सीएए का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं, वे सभी गद्दार हैं। वे चाहते हैं कि जिस तरह से हिन्दुओं को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बेहरहमी से क्रूरतापूर्वक हर तरह की यातनाएं दी जाती है, ठीक वैसे ही हिन्दुओं को भारत में भी यातनाएं दी जाये। वे चाहते हैं कि भारत को इस्लामिक देश बना दिया

जाये। वे जाने-अनजाने में चाह रहे हैं कि भारत में हिन्दुओं का नामो-निशां मिटा दिया जाये। अगर वे हिन्दू हैं और मंदिर जाते हैं तो सिर्फ हिन्दुओं को मूर्ख बनाकर सत्ता पाने के लिए अथवा सत्ता में बने रहने के लिए। अगर वे सिख हैं और गुरूद्वारा जाते हैं तो सिखों की पीठ में छूड़ा घोपने के लिए। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव, जीतनराम मांझी हो या फिर शरद पवार यह तो बता दें कि जो मुसलमान आज भारत का नागरिक है, कल भारत का नागरिक कैसे नहीं रह पायेगा? क्या ऐसे एक भी शब्द को नागरिकता संसोधन कानून में शामिल किया गया है? क्या ये नेतागण लिखित रूप में दे सकते हैं कि सीएए लागू होने से एक भी भारतीय नागरिक की नागरिकता खत्म हो जायेगी, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या बौद्ध, जैन हो या पारसी या ईसाई? लिखकर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लिखकर दे देने से उन्हें जेल हो जायेगी। तब सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? इससे स्पष्ट है कि भारत देश का नाम तो रहेगा, लेकिन देश के मूल निवासी हिन्दू भारत से ही नदारद हो जायेंगे। उपर्युक्त सभी नेता चाहे किसी भी धर्म को मानने का दिखावा करते हैं, उन्होंने भीतर ही भीतर इस्लाम कबूल कर लिया है। अर्थात् उन्हें अपने मूल धर्म से नफरत है। पूरे देश के हिन्दुओं को ऐसे गद्दार तथाकथित हिन्दू नेताओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। उपर्युक्त नेता समाज में जहां कही भी दिखे, उन्हें देखते ही मुंह फेर लें। ऐसे गद्दार नेता हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के लिए आस्तिन के सांप है। ऐसे हिन्दू नेताओं से हिन्दुओं को बातचीत तक नहीं करनी चाहिए। ये सभी नेता हिन्दुओं की पीठ में छूड़ा घोंप रहे हैं।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने 1947 में वचन दिया था कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों यानि हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों को यदि अपने फैसले पर पछतावा है तो भारत के दरवाजे उनके लिए खुल हुए हैं और खुले ही रहेंगे। उन्हें भारत की नागरिकता देना, रोजगार देना और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। नागरिकता संसोधन बिल महात्मा गांधी के इसी वचन की पूर्ति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने शपथग्रहण के समय कहा था कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते जो भी वहां से विस्थापित होने को मजबूर किये जा रहे हैं, वे भारत आ सकते हैं। उनका यहां स्वागत है। इसी वचन को 2003 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता डॉ० मनमोहन सिंह ने भी दोहराया था। यह भी ध्यान रखने की बात है कि दिल्ली के गर्वनमेंट हाउस में 08 अप्रैल 1950 को 'नेहरू-लियाकत समझौता' पर दोनो देशों के तत्काल प्रधानमंत्रियों यानि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान ने दस्तखत किये थे। उस समझौते के तहत दोनो देश अपने-अपने देशों में मजहबी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण देने की प्रतिबद्धता जतायी थी, जिसपर भारत में सौ फिसदी अमल किया गया और पाकिस्तान में एक फिसदी भी नहीं।

भारत में जन्में चार धर्म है-हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन। इन धर्मों का प्रचार बगैर किसी हिंसा के शांतिपूर्वक पूरी दुनियां में उनके दर्शन की गुणवत्ता के आधार पर हुआ है। इन चारों धर्मों में हिन्दू धर्म सबसे पुराना है। दुनियांभर में हिन्दू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, जो सही मायने में धर्मनिरपेक्ष है। हिन्दू, स्वभाव से ही उदारवादी होते हैं। इसलिए भारत में इतने सारे धर्म जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म बगैर किसी रोक-टोक के पनपते चले गये। आज भारत में मुसलमानों को जितनी छूट मिली हुई है, वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में भी मुसलमानों को नहीं मिली हुई है। दुनियां में जहां कही भी हिन्दू बसे हैं, उस देश के लिए अपने हैं, अजीज हैं। ऐसा इसलिए कि किसी कारणवश दुनियां के जिस किसी भी देश में हिन्दू बसे हैं, उस देश को ही जी जान से अपना देश मानते हैं। उस देश के विकास में जी जान से जुटे रहते हैं। इसके लिए मन लगाकर कठोर मेहनत करते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वह देश समृद्ध और खुशहाल बने तथा उस देश का नाम पूरी दुनियां में रौशन हो। इसके लिए हर समय ईमानदारीपूर्वक पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करते रहते हैं। इसी हिन्दू धर्म को पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान ने खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है। आज देश के माहौल से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही हिन्दुओं के मूल देश भारत से हिन्दू धर्म खत्म हो जायेगा। यदि इसे बचाने का यथाशीघ्र कारगर उपाय नहीं किये गये तो, लेकिन दुख ही नहीं बहुत ही दुख

की बात है कि भारत में भी हिन्दू धर्म खात्मे के कगार पर है। मसलन, कश्मीर को ही ले लिजिए। आज से करीब 700 साल पहले कश्मीर में सिर्फ हिन्दू थे, लेकिन अपने उदार स्वभाव के कारण किसी कारणवश बाहर से आये कुछ मुसलमानों को शरण दे दिया, तभी से कश्मीर अशांत रहने लगा और मुसलमानों की बढ़ती आबादी के साथ वहां अशांती फैलने लगी। आज आलम यह है कि पिछले 30 सालों से दर-दर की ठोकरे खाने वाले एक भी कश्मीरी पंडितों के परिवार को वापस वहां नहीं बसाया जा सका। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए कि ज्यादातर मुसलमान जिस देश में जाते हैं, वहां अपने देश का प्रचार-प्रसार इतनी क्रूरतापूर्वक करते हैं कि समाज में अशांती पैदा हो जाती है। मसलन मुगल शासक औरंगजेब को ही ले लिजिए, जिसने सिखों और सिखों के कुछ धर्मगुरूओं को मौत के घाट उतार दिया। हिन्दुओं के कई गांवों को उत्पीड़ित करके जबरन धर्म परिवर्तन कराकर के हिन्दू से मुसलमान बना दिया। सिखों के दसवें और अंतिम गुरू गुरूगोविन्द सिंह के दो बेटों को औरंगजेब ने ही जिन्दा दिवार में चुनवा दिया था।

आज पश्चिम बंगाल में हिन्दू विधायक और सांसद तक के जमीन-जायदाद सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में आये दिन तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा हिन्दुओं की हत्या किया जाना आम बात होती जा रही है। देश में समाजिक सुधार करने वाले और देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले सख्सियतों से भरे रहने वाले पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों को देशद्रोहियों द्वारा सताया जाने लगा है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल अशांत हो गया है। पश्चिम बंगाल के विकास को लकवा मार गया है। वहां के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई-लिखाई के माहौल में तेजर से गिरावट होती जा रही है। आज देश का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल बुरी तरह से पिछड़ गया है। शारदा चीटफंड घोटाले के चलते वहां सैकड़ों लोगों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी है, हजारों लोग कंगाल हो गये हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में और अधिक समय तक शासन करने का मौका दिया जाना उस राज्य के लिए आत्मघाती साबित होगा। ऐसे में यदि पश्चिम बंगाल को रसातल में पहुंचने से बचाना है तो इस बात का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा कि विधानसभा के आगामी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी

जितने ना पाये। वहां के लोगां को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने कुशल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को वहां के विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटबैंक को चुनाव में जीत की गारंटी मानते हैं और उसी अनुसार चुनावी रणनीति तैयार करते हैं कि मुस्लिमों के वोटबैंक पर एकाधिकार प्राप्त कर ली जाये। इसके लिए संविधान का माखौल उड़ाना पड़े तो ऐसा करने में वे जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि संवैधानिक नागरिकता संसोधन विधेयक का विरोध करने के लिए देश की सभ राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करने में जी जान से जुटे हुए हैं।

आज बड़ी तादाद में देशभर में मुसलमान सड़कों पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के विरोध में तिरंगा लहरा रहे हैं और जन-गण-मन भी गा रहे हैं। अर्थात् वैध सीएए के विरोध में अवैध धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि बहुत सारे हिन्दू में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह एकजुटता एकतरफा है, क्योंकि इसी साल 26 जनवरी को झारखण्ड के लोहरदगा में जब विश्व हिन्दू परिषद द्वारा सीएए के पक्ष में निकाली गई रैली में मुसलमानों ने जबरदस्त पथराव कर दिया, जिससे रैली में भाग ले रहे ढ़ेर सारे लोग घायल हो गये। जिनमें से कुछ तो गंभीर रूप से घायल हो गये। क्या हो गया हिन्दू-मुस्लिम एकजुटता को? जब आज से 30 साल पहले कश्मीर के मुसलमानों द्वारा वहां के चार लाख कश्मीरी पंडितों को जबरन खदेड़कर भगा दिया गया, तो यह एकजुटता क्यों नहीं दिखी? भारत के मुसलमानों ने रैली निकालकर कश्मीरी मुसलमानों के विरोध

में एक बार भी क्यों नहीं प्रदर्शन किया? जिस वक्त श्रीनगर के लालचौक पर वहां के मुसलमानों द्वारा तिरंगे झंडे जला रहे थे, उस वक्त शेष भारत के मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध क्यों नहीं जताया? समाजिक स्तर पर हिन्दू-मुसलमान में एकजुटता है तो शाहीनबाग की तरह दिल्ली में ही मुस्लिम महिलाएं कश्मीरी पंडितों पर हुए अमानवीय अत्याचार के विरोध में धरना-प्रदर्शन क्यों नहीं करती? भारत में जब हिन्दुओं पर असंवैधानिक रूप से अत्याचार किया जाता है तो यहां के मुसलमान हिन्दुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिन्दुओं पर किये जा रहे नाजायज अत्याचार का विरोध क्यों नहीं करते? कारण स्पष्ट है, भारत के मुसलमान अपने आप को इंसान समझते हैं और हिन्दुओं को जानवरों से भी गया-गुजरा समझते हैं। ऐसे में हिन्दू-मुसलमान एक साथ कैसे रह सकते हैं? देश की सरकारें यह सब आजादी के बाद से ही देखती चली आ रही है, इसलिए भारत सरकार का पुणित कर्तव्य है कि संसद में बिल लाकर भारत को संवैधानिक रूप से हिन्दू राष्ट्र घोषित करा दे, जिससे की हिन्दुओं के मूल देश भारत में हिन्दुओं के वजूद को खत्म होने से बचाया जा सके। हिन्दुओं को इसके लिए जोरदार प्रयास करना होगा। याद रहे, बच्चे को कितनी भी भूख लगी रहे माँ दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। इसलिए हिन्दुओं का अपना वजूद बचाना है तो जोरदार लड़ाई लड़ने के लिए अभी से ही एकजुट हो जाये।

★ **भारत को पाकिस्तान बना देने का फरमान है शाहीनबाग का धरना-प्रदर्शन :-** शाहीनबाग में मुस्लिम महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शन को मुसलमानों द्वारा देश का सबसे बड़ा आन्दोलन करार दिया जा रहा है, जो की सौ फिसदी झूठ है। मुस्लिम महिलाएं सीएए के विरोध में वहां की सर्वाधिक अहम सड़क को बंद करके पूरी तरह से बंधक बना लिया है। सड़क पर ही खाना बनाना, सड़क पर खाना खाना, सड़क पर आराम फरमाना और सड़क पर मुस्लिम महिलाओं का जोड़-जोड़ से ताली बजाकर फ्री कश्मीर और जिन्ने वाली आजादी के नारे लगाना। इतना ही नहीं पांच से सात साल के बच्चे-बच्चियों के मन में जहर भरकर यह कहलवाना कि मोदी और शाह हमें मारने वाला है, हम उसको मारेंगे तथा जो हिटलर की चाल चलेगा, वह हिटलर की मौत मरेगा। कोई बच्चा बगैर बड़ो के सिखाय ऐसा बोल कैसे बोल सकता है? ये बच्चे कितनी घातक मानसिकता के साथ बड़े होंगे और कैसे-कैसे दिल को दहला देने वाली जुर्म करेंगे। यह सोचकर ही हिन्दू समाज भयभित हो रहा है। ऐसे में यदि हिन्दू समाज सोचने लगे कि ये बच्चे बड़े होकर कश्मीर की तरह समूचे देश से हिन्दुओं को खदेड़ देने का प्रयास करेंगे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मुसलमानों के लिए तो दुनियांभर में 58 मुस्लिम देश है, जहां उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हिन्दुओं के लिए पूरी दुनियां में एक भी हिन्दू देश नहीं है। अगर भारत के मुसलमान, भारत को पाकिस्तान बना देंगे और ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि कश्मीर के मुसलमानों ने कश्मीर को पाकिस्तान

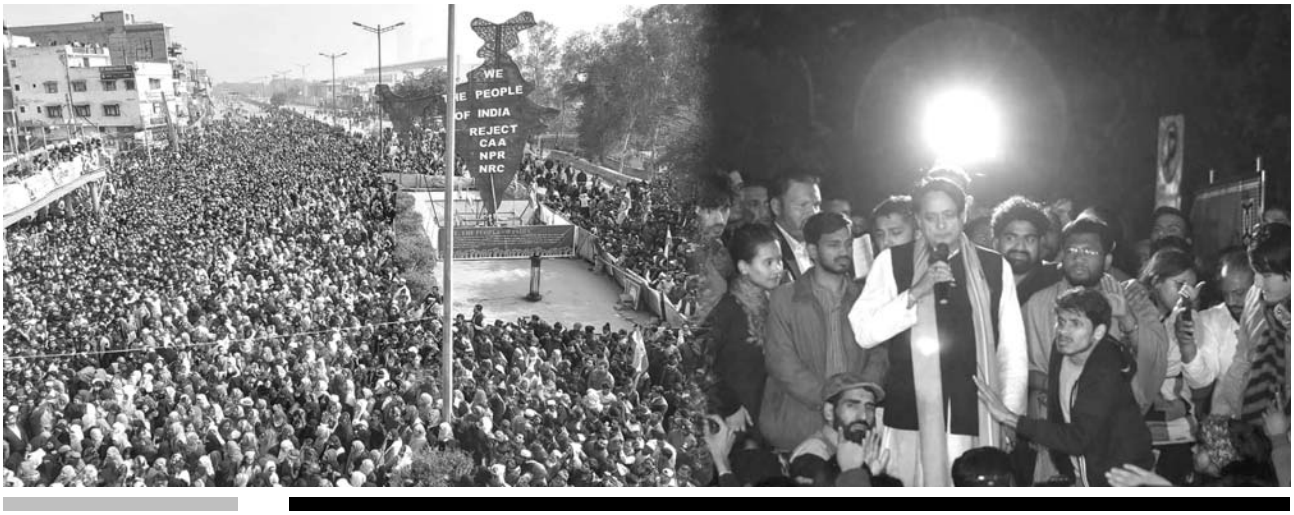

बना दिया है तो देश के अन्य हिस्सों के मुसलमान भी भारत में कश्मीर की तरह ढ़ेर सारे पाकिस्तान बना देंगे और देश के कई हिस्सों में इसकी शुरूआत हो गई है। दिल्ली का शाहीनबाग इसका ज्वलंत उदाहरण है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने घोषित कर रखा है कि पूरे देश में एक लाख शाहीनबाग बनाना है, अभी तो थोड़े ही बने हैं। ऐसे में भारत के हिन्दुओं के सामने आत्महत्या करने के सिवाय क्या विकल्प रह जायेगा? इसलिए पूरी दुनियां में कम से कम एक तो हिन्दू राष्ट्र होना ही चाहिए और भारत देश के हिन्दुओं का मूल देश है। इसलिए हर हालत में भारतीय संविधान में सुधार करके जल्द से जल्द भारत को हिन्दू राष्ट्र अवश्य घोषित कर देना चाहिए। जिससे की इस धरती से हिन्दुओं के वजूद को सदा के लिए खत्म होने से बचाया जा सके। आज पूरे देश में मुसलमानों की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि हिन्दुओं को पूरे दुनियां में बचाये रखने के लिए भारत को हर हालत में बगैर किसी विलंब के हिन्दू राष्ट्र बनाना अनिवार्य हो गया है। भारत के हिन्दुओं को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सूरज भले ही पूरब के बजाय एक दिन पश्चिम में उग जाये लेकिन भारत के मुसलमान कभी भी हिन्दुओं के साथ प्रेम-मोहब्बत से नहीं रह सकते हैं। इनमें बड़ों द्वारा उस समय ही बच्चों में हिन्दुओं के प्रति नफरत के बीज बो दिये जाते हैं, जब उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे होत हैं। इसका सबूत है पांच-छः साल के बच्चे-बच्चियों द्वारा दिल्ली के शाहीनबाग में लगाये गये नारे। बच्चे तो वही करेंगे जो उनके माँ-बाप सिखायेंगे। इनके धार्मिक स्थल पर धर्मगुरू भी यही सिखाते हैं। जबसे संसद में नागरिकता संसोधन बिल पारित हुआ है, तभी से देश के कोने-कोने में जुम्मे के नवाज के बाद आगजनी, तोड़फोड़ और खून-खराबा की बड़ी घटनायें घटी है। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि देश के मस्जिदों में नामाज के दौरान वहां के इमामो के द्वारा नामाजियों को उसकाने के कारण ही हुआ है।

★ इन तथाकथित महान हस्तियों को क्या कहा जाना चाहिए? :- वैसे तो देश में तथाकथित महान हस्तियों की कोई कमी नहीं है, जिन्हें देश के सभी तबकों से भरपूर स्नेह और सम्मान मिला है, जिन्हें देश की जानी-मानी संस्थाओं व संगठनों द्वारा खूब सराहा गया है, खूब सम्मानित किया गया है और जिन्हें देश की केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अलंकृत किया है और अपने सर माथे पर रखा है। मसलन, महान गीतकार, कहानीकार, लेखक और कवी जावेद अख्तर को ही ले लिजिए। इन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 5 बार बेस्ट लिरिक्स का नेशनल अवार्ड सहित ढ़ेर सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जावेद साहब को उनकी महान उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई। उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उनको सलाम। लेकिन उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की टिकट पर लड़ने वाले जेएनयू छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा देश के टुकड़े-टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य कन्हैया कुमार के समर्थन में अपनी पत्नी महान अदाकारा शबाना आजमी और कई नामी-गिरामी सिनेमा के कलाकारो के साथ हफ्तों बेगूसराय में सफेद झूठ बोलकर वहां की जनता को गुमराह करते रहे। टेलीविजन पर पूरा देश देखा है कि 13 दिसम्बर 2001 को संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू, जिसे 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई, उसकी बरसी पर आयोजित समारोह में कन्हैया कुमार और उमर खालिद अपने कुछ साथियों के साथ हांथ उठा-उठाकर किस तरह से नारा लगाया था कि, 'तब तक हम शांत नही बैठेंगे, जब तक कि देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं कर देंगे। अफजल गुरू तेरे बलिदान का बदला लेकर रहेंगे'। इस दृश्य को जावेद अख्तर साहब ने भी टीवी पर कई बार देखा है, फिर भी कन्हैया कुमार के पक्ष में झूठा प्रचार कर रहे थे कि वह निर्दोष है। बेगूसराय वालों को नाज है कि कन्हैया कुमार उनका बेटा है। एक नहीं दस जन्म ले लें तो भी जावेद अख्तर साहब सफल नहीं होंगे। बेगूसराय वाले राष्ट्रभक्त, राष्ट्रकवि स्व० रामधारी सिंह दिनकर को ही बेगूसराय का बेटा मानेंगे, देशद्रोही कन्हैया कुमार को तो हरगीज नहीं। बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान जावेद अख्तर साहब वहां की जनता को गुमराह करने के मकसद से कहते थे कि मोदी सरकार सिर्फ हिन्दू-मुसलमान और जात-पात के आधार पर देश की जनता को बांटने का काम कर रही है। मोदी सरकार का एक ही मकसद है, देश में सम्प्रदायिक दंगे फैलाना। लेकिन उन्होंने एक भी उदाहरण पेश नहीं किया। वे बेगूसराय की जनता से कहते रहे कि मुझपर विश्वास करे, मैं हरिश्चंद्र हूं। ऐसे मुंह मियां मिठ्ठू से भगवान ही बचाये। ऐसे में जावेद अख्तर साहब को क्या कहेंगे-झूठ के सौदागर या देशद्रोहियों का सरदार? नागरिकता संसोधन बिल के विरोध में अपनी पत्नी शबाना आजमी और बेटे फरहान अख्तर के साथ आक्रोश में आकर कहने लगे कि अब सिर्फ मुंह से बोलने का समय खत्म हो गया, मैदान में उतरकर और लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन करना होगा। क्या वे नहीं जानते हैं कि उनकी हरकत भारतीय संविधान के विरूद्ध है। जानते जरूर है, फिर भी भारतीय संविधान का खुल्लम-खुल्ला माखौल उड़ा रहे हैं। जब 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बहु-बेटियों और पत्नियों के साथ वहां के मुसलमानों ने बलात्कार किया, कश्मीरी पंडितों की हत्या की, उनके घरों में आग लगा दी, उनके मंदिरों को नेस्तानाबूत कर दिया और जमीन-जायदाद को हड़प लिया। कश्मीरी पंडितों पर दिल को दहला देने वाले इस घृणित कृत्य को लेकर वहां जाकर जावेद अख्तर साहब ने धरना क्यों नहीं दिया? अपने पद्मश्री, पद्मभूषण, फिल्मफेयर आदि पुरस्कारों को क्यों नहीं लौटा दिया? ऐसे में जावेद अख्तर साहब को क्या कहेंगे? क्या ये धर्मनिरपेक्ष भारत को मुस्लिम देश बनाने का भरपूर प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्या ये गद्दार या

देशद्रोही नहीं हैं? क्या यह जिस थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद नहीं कर रहे हैं? क्या ये इंसान के रूप में शैतान नहीं हैं? क्या ये भारत के मूल निवासी हिन्दुओं का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए नहीं है? जवाब देने की जरूरत नहीं है। देश की जनता इनके घृणित करतूतों को देख रही है। जोड़ों की दर्द की दवा डॉ० ऑर्थो के तेल का प्रचार एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा टीवी और अखबारों में करायी जा रही है, जो देश के टुकड़े-टुकड़े गैंग का प्रबल समर्थक है और जो भारतीय संविधान का खुल्लम-खुल्ला माखौल उड़ा रहा है। हम भारतीयों को इस प्रचार से काफी तकलीफ हो रही है। पता नहीं डॉ० ऑर्थो का तेल कितना लाभकारी है, लेकिन इस दवा के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में इस दवा का बहिष्कार किया जाना नितांत अनिवार्य है।

आज से पांच वर्ष पहले देश के महान कलाकार आमिर खान को भारत में रहने में घुटन महसूस हो रही थी। आमिर खान का इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? सच्चाई तो यह है कि भारत की जनता द्वारा उन्हें जितना प्यार और सम्मान मिल रहा है, उतना दुनियां के किसी भी दूसरे देश में नहीं मिलेगा। देश की जनता द्वारा भरपूर प्यार और सम्मान मिलने के बावजूद महान कलाकार सैफ अली खान देश के मौजूदा माहौल से काफी दुखी है। काश! जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, आमिर खान और सैफ अली खान पाकिस्तान में होते तो पता चल जाता कि उनके लिए भारत जन्नत है और पाकिस्तान दोजख, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है। इसलिए धर्म के आधार पर वहां मुसलमानों को प्रताड़ित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या ये नामी-गिरामी कलाकार देश के प्रति एहसान फरामोस नहीं तो और क्या हैं? इन्हें इस तरह का बयान देने में क्या जरा भी शर्म नहीं आती। यदि आती ही होती तो ऐसे शर्मनाक बयान देते ही क्यों? अब जरा देश के एक और महान अभिनेता नसरूद्दीन शाह के देशविरोधी शर्मनाक हरकत को भी जान लिजिए। महान अभिनेता अनुपम खेर ने जब अनुच्छेद 370 और 35ए हटाये जाने तथा नागरिकता संसोधन बिल को पारित कराने को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की तो नसरूद्दीन शाह तिलमिला गये। उन्होंने अनुपम खेर को यहां तक कह डाला कि खेर के खून में चमचागिरी है और वह एक जोकर की तरह है। उन्होंने देश में देश की सम्प्रदायिकता पर चिंता व्यक्त की। इसके पहले भी वे कई बार ऐसा देशद्रोही वक्तव्य दे चुके हैं। देश ने नसरूद्दीन शाह को नाम, शोहरत और दौलत सबकुछ दिया। उन्होंने अपने धर्म के बाहर शादी की, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके भाई सेना में लेफ्टिनेंट जेनरल बने। क्या उनको और उनके परिवार को भरपूर सम्मान नहीं दिया गया है? क्या इस देश के विकास में उनका योगदान हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा है कि उन्हें भी भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाये। देश के विकास में उनका योगदान डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम के मुकाबले जीरो है। फिर भी नसरूद्दीन शाह, मोदी सरकार से नाखूश हैं। कश्मीरी पंडित होने के नाते तो अनुपम खेर ने कश्मीरी मुसलमानों द्वारा उनपर किये गये जुल्मों को झेला है, फिर भी अनुपम खेर ने नसरूद्दीन शाह को कहा कि आप सफल अभिनेता हैं लेकिन कुंठा में जी रहे हैं। इसलिए आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे खून में हिन्दुस्तान है। दूसरा प्रमुख उदाहरण देश के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० इरफान हबीब को ही ले लिजिए। केरल के कन्नूर युनिवर्सिटी में 28 दिसम्बर 2019 को भारतीय इतिहास कांग्रेस के 80वें अधिवेशन को अवसर पर केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान के पहुंचते ही केरल कांग्रेस स्टूडेंड्स युनियन, युथ कांग्रेस और मुस्लिम स्टूडेड्स फ्रंट के कुछ समर्थकों द्वारा सीएए के विरोध में उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। प्रदर्शन करने वाले छात्र के हांथों में सीएए विरोधी तख्तियां लिए हुए थे। ऐसे में राज्यापाल को अपने संबोधन में बोलने पर मजबूर होना पड़ा कि सीएए का विरोध असंवैधानिक है, क्योंकि राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वह भारतीय संविधान के हिफाजत में सहयोग दे। और तो और मंच पर उपस्थित सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० इरफान भी गालियां देते हुए राज्यपाल पर आक्रमण करने हेतु उनके बिल्कुल समीप पहुंच गये थे। यदि राज्यपाल के बगल में खड़े उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक लिया, वरना इरफान हबीब राज्यपाल को कुछ भी कर देते-धक्का देते गिरा देते या थप्पड़ मार देते। ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को इंसान पहले होना चाहिए, इतिहासकार बाद में। अपने घृणित हरकत से इरफान हबीब ने देश के समस्त इतिहासकारों को शर्मसार कर दिया। आश्चर्य तो तब और अधिक हुआ, जब इरफान हबीब के समर्थन में कुछ सिरफिरे इतिहासकार 'राज्यपाल शर्म करो' के नारे लगाने लगे। जनता का द्वारा दिये गये टैक्स के पैसे पर अधिवेशन में भाग लेने आये ये कुछ इतिहासकार बहुत देर तक दहशतगर्दी करते रहे। क्या यही दहशतगर्द इतिहासकार छात्रों का करीयर बनायेंगे? भले ही यह दहशतगर्द इतिहासकार छात्रों का करीयर बनाये या नहीं बनाये, लेकिन छात्रों का करीयर बर्बाद जरूर कर देंगे।

देश की सुविख्यात लेखिका और समाजिक कार्यकर्ता अरूंधती राय को ले लिजिए। ये मुस्लिम तुष्टीकरण में विश्वास करती हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्रसिद्धी मिलती है। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए 2010 में डाटा एकत्रित किया गया था। यह रूटीन कार्य है, जिसके द्वारा प्रत्येक दस साल के अंतराल पर देश की जनसंख्या की गिनती की जाती है। इसकी

शुरूआत 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में की गई थी। नागरिकता कानून 1955 का, 2003 में संसोधित कर एनपीआर के प्रावधान जोड़े गये। इसका मकसद देश के हर व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करना है, जो दुनियां के हर देश के लिए अनिवार्य है। एनपीआर के तहत देश के हर व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, माता-पिता का नाम, यदि विवाहित है तो पत्नी या पति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, जन्म स्थान, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, मौजूदा पते पर रहने की अवधि, स्थायी आवासीय पता, व्यवसाय और शैक्षिणक योग्यता की जानकारी इकट्ठी की जाती है। ऐसा किया जाना ना सिर्फ संवैधानिक है, बल्कि देशहीत में अनिवार्य है। बावजूद इसके अरूंधती राय ने लोगों से अपील किया कि एनपीआर से जुड़ा कोई सरकारी मुलाजिम आपसे नाम पूछे तो रंगा-बिल्ला बताइएगा और पता की जगह 7 रेसकोर्स लिखवाइयेगा। ये देश की जनता को, देश के संविधान का माखौल उड़ाने के लिए भड़का रही हैं। भारतीय संविधान विरोधी ऐसा व्यक्ति देशद्रोही है, गद्दार है।

ऐसे ही एक व्यक्ति हैं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव। जो नागरिकता संसोधन बिल के विरोध में देशभर में अफवाह फैलाकर हर तरह से नागरिकता संसोधन बिल का विरोध करने के लिए देश की जनता को भड़का रहे हैं। अगर ये अपने आप को इतना काबिल समझते हैं तो यह साबित करके दिखा दें कि नागरिकता संसोधन बिल असंवैधानिक है, अन्यथा खुद कहे कि मैं जो कर रहा हूं वह असंवैधानिक है।

★ मुसलमानों के चमचे हैं भारतीय नेतागण :- अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय पर मेहरबान है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने पूरे देश में 2 करोड़ गरीब परिवारों को गरीब दिया है, जिसमें 31% मुसलमान है, 8 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया है, जिसमें 37% मुसलमान समुदाय के गरीब परिवार है। गैस कनेक्शन में चूल्हा के साथ गैस सिलिण्डर और रेगुलेटर भी मुफ्त दिये गये हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय बनवाने के लिए पैसे दिये गये हैं, जिनमें 34% गरीब मुसलमान परिवार है। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत छः हजार रूपये प्रति किसान प्रति वर्ष के हिसाब से तीन किश्तों में दिया जा रहा है, जिसका दो सौ रूपये के पहले किश्त का भुगतान किया जा चुका है। इससे 33% से ज्यादा गरीब अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमान किसानों को फायदा पहुंच

रहा है। 21 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों पर कर्ज दिये गये हैं। जिससे 36% अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों को लाभ पहुंच रहा है। 6 लाख गांवों में बिजली पहुंचायी गयी है, जिसमें 39% से ज्यादा अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम गांव है। 2014 से अभी तक गरीब नवाज रोजगार योजना, नई मंजिल, उस्ताद आदि योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मुहैया कराये गये हैं। इनमें लगभग 50% मुस्लिम लड़कियां शामिल हैं। देश के 1300 प्रखण्डों में युद्धस्तर पर अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों को रोजगार परख विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। प्रशिक्षण की समाप्ती पर आर्थिक सहायता तथा देश-विदेश में बाजार भी मुहैया कराया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान 33 डिग्री कॉलेज, 1393 स्कूल भवन, 40201 अतिरिक्त क्लास रूम, 574 हॉस्टल, 81 आईटीआई, 50 पोलटेक्निक, 123 आवासीय स्कूलों का निर्माण अल्पसंख्यक बहुल, विशेषकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कराया गया है। 39586 आंगनबाड़ी केन्द्र, 398 सद्भावना मंडप, 570 मार्केट शेड, 104 कॉमन सर्विस सेंटर आदि सुविधाओं का निर्माण अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र, विशेषकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कराया गया है। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय को मोदी सरकार से शिकायत है कि मोदी सरकार को उनके लिए जितना काम कराना चाहिए, उसके मुकाबले नहीं के बराबर की है और कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर मोदी सरकार हिन्दुओं का हकमारी कर रही है, फिर भी मुस्लिम समुदाय, मोदी सरकार से खफा है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए कितना भी करेगी, वे मोदी सरकार से नाराज ही रहेंगे। नागरिकता संसोधन कानून से भारतीय मुसलमानों को कुछ लेना-देना नहीं है। अर्थात् वे भारत के नागरिक हैं और भारतीय नागरिक ही बने रहेंगे। इस कानून से सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बुरी तरह से प्रताड़ित कर वहां से खदेड़कर भगा दिये गये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जायेगी। इसकी घोषणा संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने की है और संसद में प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बराबर कह रहे हैं, नागरिकता संसोधन बिल ऐसा बिल है। फिर भी मुस्लिम समुदाय पूरे देश में रोड़ा-पत्थर और पेट्रोल बम के साथ आगजनी और तोड़फोड़ को अंजाम दे रहा है, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच जाकर वे अफवाह फैलाकर उनको भड़का रहे हैं तथा उनसे भी तोड़फोड़ और आगजनी द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे हैं। इतना ही नहीं उनसे पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे भी लगवा रहे हैं। और तो और 30 वर्ष पहले कश्मीरी पंडितों को धर्म के आधार पर उत्पीड़ित कर खदेड़ दिया गया, जो अपने ही घर से विस्थापित होकर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। आखिर देश का मुस्लिम समुदाय क्या चाह रहा है? क्या देश में हिन्दुओं का वजूद खत्म कर दिया जाये? क्या हिन्दू समुदाय जानवर से भी बद्तर समुदाय है? इसके लिए मोदी सरकार पर संविधान के विरूद्ध कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए मुस्लिम समुदाय नाजायज तरीके से दबाब बना रहा है। क्या मुस्लिम समुदाय,

हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा को समाप्त करके ही दम लेगी? क्या देश में गंगा-यमुनी तहजीब को मिटा देगी? जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, बसपा, राजद, सीपीआई, सीपीएम आदि कोई भी हो, अपने नापाक इरादे को अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं होगी। देश की जनता टीवी पर सब देख रही है और अखबारों में भी पढ़ रही है। इसका अंजाम उपरोक्त सभी पार्टियों को आगामी हर चुनाव में, हर हालत में भुगतना ही पड़ेगा। देशभर में तोड़फोड़ और आगजनी कराने का मजा इन पार्टियों को अच्छी तरह से जनता चखा देगी। हाल ही में अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिलने के पहले तक पाकिस्तानी मुसलमान थे, अब भारतीय मुसलमान बन गये हैं। उनके पिता पाकिस्तानी वायुसेना के काबिल अफसर थे। उन्होंने 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें पुरस्कृत भी किया था। अदनान सामी के परिवार को पाकिस्तानी वायुसेना का बड़ा और काबिल अफसर रहने के कारण उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तान में हर तरह की सुविधाएं प्राप्त है। फिर ऐसे में मोदी सरकार ने अदनान सामी को भारतीय नागरिकता क्यों प्रदान की? यह मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों की चमचागिरी नहीं तो और क्या है? इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अदानान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने की घोषणा कर दी, जबकि अपने देश में एक से बढ़कर एक ऐसे हिन्दू गीतकार, गायक और संगीतकार हैं। जिनके सामने अदनान सामी काफी बौने हैं और जिन्हें पद्म पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। मोदी सरकार ने तो मुसलमानों की चमचागिरी की सभी हदे पार कर दी। ऐसा भाजपा में मौजूद रघुवर दास और राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे चाटूकार और गैर जिम्मेदार नेताओं की मौजूदगी के चलते हो रहा है। इसलिए पार्टी को बचाने के लिए तथा देशहीत को ध्यान में रखकर मोदी और शाह को ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता अविलंब दिखा देना चाहिए।

हर पार्टी के नेता मुसलमानों की चमचागिरी में लगे हुए हैं और इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। कांग्रेस पार्टी, रॉष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनकान्ति पार्टी, भीम पार्टी, इत्यादि। सभी पार्टियों के शीर्ष नेता मुसलमानों की जी हुजूरी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मसलन, जब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता आजम खॉ का भैंस खो गया था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पूरा का पूरा सरकारी अमला, सिपाही से लेकर डीजीपी तक राज्य के सभी कामकाज को छोड़कर भैंस की खोज में जुट गये थे और चौबिस घंटे के अंदर भैंस को खोज निकाला। मुस्लिम वोट बैंक के खातिर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हिन्दू प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भुनवा दिया था। सिवान के शहाबुद्दीन को चुनाव का पर्चा भरवाने के लिए स्वयं लालू प्रसाद यादव उनकी खातीरदारी में लगे रहते थे। जेल में रहने के कारण शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाबुद्दीन का पर्चा भरते समय उनके साथ कार्यालय में मौजूद नहीं रहे, लेकिन उस कमी की पूर्ति लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने पूरा कर दिया। हिन्दू ब्राह्मण होते हुए भी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिन्दुओं के महापर्व रक्षाबंधन के अवसर पर कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम को हर साल राखी बांधती हैं। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी से पीछे नहीं हैं। बिहार में हर साल नीतीश सरकार मुस्लिम विधवा महिलाओं को पांच हजार करोड़ रूपये की आर्थिक मदद देती है तो हिन्दू विधवा महिलाओं को क्यों नहीं देती? क्या विधवा हिन्दू महिलाएं अपने ही मूल देश भारत में हिन्दू होने का सजा भुगत रही हैं। एक तरह से राजनीतिक पार्टियों में मुसलमानों की खिदमतगिरी करने की होड़ मची हुई है। भारतीय मुसलमान और घुसपैठिये मुसलमान निश्चिंत हैं कि वे देश में कुछ भी जायज-नजायज करे, भारतीय राजनीतिक पार्टियों का समर्थन उन्हें मिलना ही मिलना है। यदि भारतीय मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करे या संसद द्वारा पारित कानून का विरोध करे, भारतीय राजनीतिक पार्टियां उनके साथ है। क्योंकि इन नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो, उन्हें चुनाव में मुसलमानों का वोट मिलता रहे। यही कारण है कि भारत आज अघोषित मुस्लिम देश बन गया है। भारतीय राजनीतिक पार्टियों और उनके शीर्ष नेताओं का यही हाल रहा तो निकट भविष्य में शीघ्र ही पूरे देश के हिन्दुओं का वही हाल होगा, जो कश्मीर के कश्मीरी पंडितों का हुआ है। पूरे देश में हिन्दुओं पर दिल को दहला देने वाला अमानवीय अत्याचार होने लगेगा, जिसके चलते उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जायेगा और भारत देश भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैनमुक्त देश बन जायेगा। हिन्दुओं के एकमात्र मूल देश भारत से भी उनका नामोनिशां मिट जायेगा और भारत दुनियां का 59वां मुस्लिम देश बन जायेगा। लेकिन, खाड़ी के मुस्लिम देशों की तरह भारत का विकास नहीं हो पायेगा, क्योंकि खाड़ी के मुस्लिम देशों के मुसलमानों और भारत के मुसलमानों की सोच में आकाश-पाताल का अंतर है। अंततः भारत भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर दुनियां में भीक्षाटन करने लगेगा।

☆ **क्यों जरूरी है भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाया जाना? :-** भारत में हिन्दुओं पर हो रहे भारतीय मुसलमानों के द्वारा दिल दहला देने वाले उत्पीड़न से बचाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय बचा है, भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाना। देश के हिन्दुओं को सारे आपसी मतभेद भुलाकर एकदम से एकजुट होकर भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए बगैर किसी विलंब के युद्धस्तर पर जुट जाना चाहिए। वरना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह भारत को इस्लामिक देश बनाने के मुसलमानों के जी-जान से आजादी के बाद से ही जुटे हुए हैं।

☆ **देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने के उपाय :-** हिन्दू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव लेकर देश के प्रत्येक सांसद और राज्यों के प्रत्येक विधायक के पास जाकर उनके हांथों में इस प्रस्ताव को देकर उनका हस्ताक्षरयुक्त प्राप्ति प्राप्त कर ले, जिससे की कल होकर कोई सांसद और विधायक को यह कहने का मौका नहीं मिले कि आपके प्रस्ताव को लेकर उन्हें सूचित नहीं किया गया है। प्रस्ताव के द्वारा उनसे निवेदन करे कि वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किये जाने का बिल पास करावें। प्रत्येक सांसद और विधायक को साफ-साफ कह दें कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का न सिर्फ बिल पेश करे बल्कि उसे हर हालत में पारित भी करावें। इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र बुलाना पड़े तो सांसद और विधायक बुलावें, वरना भूल जाये कि हिन्दुओं को एक भी वोट उन्हें मिलेगा। ऐसा बगैर किसी तरह की अव्यवस्था फैलाये, शांतिपूर्वक संविधान का पूरा पालन करते हुए किया जाना बिल्कुल संभव है। सिर्फ तख्ती लटका दे, जिसपर लिखा हो कि 'भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करो'। इसके लिए न नारा लगावें, न धरना-प्रदर्शन करे और न कोई रैली निकाले। अर्थात् किसी भी तरह से समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई व्यवधान पैदा न करे। यह सब बिल्कुल शांतिपूर्वक संविधान और इंसानियत को ध्यान में रखकर करे। देश में व्यवधान पैदा न करे, जिससे देश की एक भी जनता को किसी भी तरह के मुश्किल का सामना करना पड़े। ●

● **अमित कुमार**

ज्ञात हो कि 16 दिसम्बर 2012 का दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला भारत की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश को अश्रुओं से भर दिया था। इसमें पीड़िता का पहले सामुहिक बलात्कार तथा उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की गई थी। इस कृत्य की निन्दा करते हुए सोशल मीडिया में ट्वीटर, फेसबुक आदि पर काफी कुछ लिखा गया। इस घटना के विरोध में पूरे देश में उग्र व शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिसमें नई दिल्ली, कोलकाता और बैंगलुरू में हुए प्रदर्शन उल्लेखनीय हैं। वही उल्लेखनीय बात यह भी है कि नई दिल्ली में यौन अपराधों की दर अन्य मैट्रोपॉलिटन शहरों के मुकाबले सर्वाधिक (प्रति 18 घण्टे पर लगभग एक बलात्कार) है। इससे पूर्व भारत की एक मात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलात्कार के पाँच मामलों में दी गयी फाँसी की सजा को माफ करके उम्रकैद में बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निन्दनीय साबित हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई कड़े कानून संसद में पारित किये गए हैं। सनद् रहे कि इस मामले में 11 मार्च 2013 में राम सिंह नामक मुख्य आरोपी ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। हालाँकि राम सिंह के परिवार वालों तथा उसके वकील का मानना है कि उसकी जेल में हत्या की गयी थी। वही 14 सितम्बर 2013 को इस मामले के लिये विशेष तौरपर गठित त्वरित अदालत ने चारों व्यस्क दोषियों को फाँसी की सजा सुनायी गयी।

बताते चले कि इस घटना के बाद पीड़िता को निर्भया का नाम दिया गया। यह नाम पीड़िता को समाज व मीडिया द्वारा दिया गया नाम है। भारतीय कानून व मानवीय सद्भावना के अनुसार ऐसे मामले में पीड़ित की पहचान को उजागर नहीं किया जाता। नई दिल्ली में अपने पुरुष मित्र के साथ बस में सफर कर रही निर्भया के साथ 16 दिसम्बर 2012 की रात में बस के निर्वाहक, मार्जक व उसके अन्य साथियों द्वारा पहले भद्दी-भद्दी फब्तियाँ कसी गयीं और जब उन दोनों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब उसका पुरुष दोस्त बेहोश हो गया तो उस युवती के साथ उन सबों ने बलात्कार करने की कोशिश की। उस युवती ने उनका विरोध किया, परन्तु जब वह संघर्ष करते-करते थक गयी तो उन्होंने पहले तो उससे बेहोशी की हालत में बलात्कार करने की कोशिश की, परन्तु सफल न होने पर उसके यौनांग में व्हील जैक की रॉड घुसाकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में वे सभी उन दोनों को एक निर्जन स्थान पर बस से नीचे फेंककर भाग गये। किसी तरह उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बलात्कृत युवती की शल्य चिकित्सा की गयी। परन्तु हालत में कोई सुधार न होता देख उसे 26 दिसम्बर 2012 को सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उस युवती की 29 दिसम्बर 2012 को मौत हो गई। 30 दिसम्बर 2012 को दिल्ली लाकर पुलिस की सुरक्षा में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। निर्भया की घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर नए सिरे से एक नई बहस शुरू हुई। इस घटना के विरोध में पूरे देश में उग्र व शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया में ट्वीटर, फेसबुक आदि पर काफी कुछ लिखा गया। यहाँ तक कि महिलाओं की सुरक्षा सियासत का गेमचेंजर अजेंडा बन गयी बार और सभी दलों के ऊपर उनके सरोकारों के साथ खुद को दिखाने का सामाजिक दबाव भी पड़ा। यही कारण था कि सरकार ने जस्टिस वर्मा को कानून

में बदलाव करने के लिए सिफारिश करने को कहा। इसमें पहली बार बलात्कार करने वाले अपराधियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया। संसद ने अभूतपूर्व तरीके से इसे एकमत से पास किया। 16 दिसम्बर की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता भी बढ़ी है। महिलाएं भी अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ अब आवाज उठाने में हिचकिचा नहीं रही हैं। नए कानून से उन्हें मदद भी मिल रही है। इस घटना के बाद उषा मेहरा कमिशन का गठन हुआ, जिसने सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तमाम जिम्मेदार विभागों में संवाद की कमी और इसे कैसे दूर किया जाय से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की :-

☞ महिला बाल विकास मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्प लाइन नंबर की शुरूआत की।

☞ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने महिला सुरक्षा से कई गैजट बनाने की शुरूआत की जो जल्द ही बाजार में आएंगे।

☞ सरकार ने महिला बैंक की शुरूआत की। सरकार ने इसी घटना के बाद निर्भया फंड की शुरूआत की। तमाम राजनीतिक दलों के अजेंडे में महिला सुरक्षा पर फोकस किया गया।

☞ दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया।

☞ मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्म-हत्या कर लिया और विशेष तौर पर गठित त्वरित अदालत के द्वारा चारो वयस्क दोषियों को फाँसी की सजा सुनायी गयी, जबकि एक आरोपी को स्कूली प्रमाणपत्र के आधार पर नाबालिग मानते हुए उसे तीन साल किशोर सुधार गृह में रहने की सजा दी गई है। मसलन, देश की न्यायिक कानून व्यवस्था स्वयं में बार-बार प्रश्नचिन्ह् खड़ा करता है, क्योंकि जिस प्रकार उन दोषियों को फांसी मुव्वकील होने के बाद भी तारीख पर तारीख बढ़ रही है, जिससे देश की भयभित जनता सहित निर्भया के माता-पिता की आंखे अश्रुओं से नम दिखने लगी है।

2012 के मुकाबले इस साल राष्ट्रीय महिला आयोग को बलात्कार, छेड़खानी और घरेलू हिंसा जैसे मामलों की दोगुनी शिकायतें मिली हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है। सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में जीपीएस तो लगने लगे, उनके जरिये गाड़ियों की मॉनिटरिंग का कोई ठोस तंत्र अब तक नहीं बन पाया है। ऑटो वालों की मनमानी कायम है।

बहरहाल, देश की इतनी बड़ी दुर्दांत घटना से ये हैवान सहमे और ना ही फांसी का भय भी उनके अंदर दिखता है और फिर से बीते वर्ष के नवंबर महीने हैदराबाद में एक और निर्भया उन हैवान बहसियों का शिकार बन गई। बताते चले कि 27 नवंबर 2019 की रात 27 साल की जानवरों की डॉक्टर को इन दरिंदो ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। शराब पीते हुए आरोपियों ने डॉक्टर को स्कूटी पार्क करते हुए देखा था और यह दुस्साहसी प्लान बना लिया था। स्कूटी की हवा निकालकर पहले मदद का बहाना किया और फिर मोबाइल छीन लिया। हैदराबाद के शादनगर में जानवरों की डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या कर दी। किन्तु पुलिस जांच के बाद सारे आरोपी पकड़े गये। वही कानून को अमलीजामा पहनाने वाले ये बेखौफ अपराधियों में कानून का भय नहीं है, इस बाबत आम जनता के साथ पीड़िता के परिवार वालों में न्याय को लेकर विपरित सोच देखी ही जा रही थी कि इसमें एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। हुआ यूं कि सुबह ही केस के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस जांच के लिए इन आरोपियों को मौका-ए-वारदात पर लेकर गई थी। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। बता दें कि हैदराबाद शादनगर में जानवरों की डॉक्टर से रेप और हत्या के केस में पुलिस ने चारों आरोपियों शिवा, नवीन, केशवुलू और मोहम्मद आरिफ को पुलिस रिमांड में रखा था। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच के लिए चारों को उस फ्लाइओवर के नीचे लेकर गई थी, जहां उन्होंने पीड़िता को आग के हवाले किया था। वहां क्राइम सीन को रीक्रिएट किया जा रहा था। इसी बीच चारों ने भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने प्रतिक्रिया करते हुए गोलियां चलाईं और मुठभेड़ में चारों को ढ़ेर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि हैवानियत भरे इस कांड के बाद से देश भर में उबाल था और चारों को फांसी दिए जाने की मांग उठ रही थी। जहां इन आरोपियों को लेकर जाया गया, इन्होंने रेप के बाद के डॉक्टर की हत्या करके शव को वहीं जलाया था। इस पर पीड़िता के पिता ने सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं, एनकाउंटर के बाद तेलंगाना के कानून मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया से पहले ही भगवान ने आरोपियों को सजा दे दी। उन्होंने कहा, आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी तो मार गिराया गया। इससे हैदराबाद समेत पूरे देश में खुशी है।

विडम्बना है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, वह मंथन का विषय है। देश में दिल्ली की निर्भया की पीड़ा को देखा तो आज हैदराबाद की पशु चिकित्सा की पीड़ा को देखा, तो कही बदायुं की घटना को देखा, तो कही उन्नाव की घटना को देखा, तो कही बिहार के बक्सर की रेप घटना को देखा, तो कही झारखण्ड की निर्भया रेप की पीड़ा को देखा, और तो और पटना के पाटलीपुत्रा कॉलोनी की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की पीड़ा को भी देखा। प्रत्येक दिन हमारा समाज एक निर्भया की पीड़ा को देख रहा है किन्तु ये हैवान बलात्कारियों के अंदर के भय को किसी ने नहीं देखा।

गौरतलब हो कि हर वर्ष बलात्कार के

मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्ष 2011 में देशभर में बलात्कार के कुल 7,112 मामले सामने आए, जबकि 2010 में 5,484 मामले ही दर्ज हुए थे। आंकड़ों के हिसाब से एक वर्ष में बलात्कार के मामलों में 29.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 50 बलात्कार के मामले थानों में पंजीकृत होते हैं। इस प्रकार भारतभर में प्रत्येक घंटे दो महिलाएं बलात्कारियों के हाथों अपनी अस्मत गंवा देती हैं, लेकिन आंकड़ों की कहानी पूरी सच्चाई बयां नहीं करती। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, जिनकी रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। बलात्कार के मामलों में मध्यप्रदेश सबसे आगे है जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। इन तीनों प्रदेशों के आंकड़े मिला दिए जाएं तो देश में दर्ज बलात्कार के कुल मामलों का 44.5 प्रतिशत इन्हीं तीनों राज्यों में दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीबी के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली बलात्कार के मामले में सबसे आगे है। पिछले कुछ दिनों में ही दिल्ली में कार में बलात्कार के कई सनसनीखेज मामले दर्ज हुए। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर भी बलात्कार के मामलों में देशभर में पांचवें नंबर पर है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पुणे के बाद जयपुर का नंबर इस मामले में आता है। 2007 से 2011 की अवधि के दौरान अर्थात चार साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मामले में दिल्ली नंबर वन रही। एनसीबी के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी लगातार चौथे साल बलात्कार के मामले में सबसे आगे है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में साल 2011 में रेप के 568 मामले दर्ज हुए थे, जबकि मुंबई में 218 मामले दर्ज हुए। राज्यों की बात करें तो मध्यप्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में रेप के सबसे अधिक 15,275 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में 11,427, यूपी में 8834 और असम 8060 का स्थान है। 7703 रेप केस के साथ महाराष्ट्र इस सूची में पांचवें नंबर पर है यानी कुल 51 हजार 299 बलात्कार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2008 के बीच 18 से 30 की उम्र के करीब 57,257 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा यह आंकड़े सिर्फ महिला अत्याचार के आधार पर जारी किए गए हैं। 'विश्व स्वास्थ संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रत्येक 54वें मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है।' वहीं महिलाओं के विकास के लिए केंद (सेंटर फॉर डेवलॅपमेंट ऑफ वीमेन) अनुसार, 'भारत में प्रतिदिन 42 महिलाएं बलात्कार का शिकार बनती हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 35वें मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है।' रेप के मामलों की जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे अधिकतर मामलों में आरोपी को पीड़िता के बारे में जानकारी होती है। यह एक सामाजिक समस्या है और ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाना असंभव है। अधिकारियों की मानें तो इनमें से अधिकांश मामले बेहद तकनीकी होते हैं। अक्सर ऐसे अपराध दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं, जो पीड़िता को झूठे वादे कर बहलाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। कई बार ऐसे अपराध अज्ञात लोग करते हैं और पुलिस की पहुंच से आसानी से बच निकलते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि इसमें पीड़िता की रजामंदी होती है। उसे इस बात के लिए रजामंद कर लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि बलात्कार से पीड़ित महिला बलात्कार के बाद स्वयं अपनी नजरों में ही गिर जाती है, और जीवनभर उसे उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है, जिसे उसने नहीं किया।

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:''। अर्थात् जहाँ नारी को पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं, वैदिक काल से हमें यह बाते सिखाई व पढाई जाती है। किसी भी देश के इतिहास में इतनी सुन्दरता से इस तरह की शिक्षाओ का वर्णन नहीं मिलता जिस तरह से हमारे शास्त्रों में मिलता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम बलात्कार की वीभत्स खबरे पढ़ते है, महिला उत्पीडन पर समाचार देखते है। आइए, बलात्कार की घटनाओ के कारणों को समझते हैं:-

- ☞ सामाजिक परिप्रेक्ष्य
- ☞ सामाजिक व् आर्थिक परिप्रेक्ष्य
- ☞ कानूनी परिप्रेक्ष्य

★ **सामाजिक परिप्रेक्ष्य :-** सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर पहले नजरिए से देखे तो यह कारणों को मूलत: तीन वर्गों में बाँट देता है:-

क) पुरुष कामुकता (आदमी स्वयं में हो रहे यौनाग्रह को नियंत्रित नहीं कर पाता)।

ख) पुरुष रोग विज्ञान (दिमागी रूप से बीमार)।

ग) पुरुष शत्रुता (महिलाओं से दुश्मनी व नापसंद)।

पहले दो कारणों का अगर विश्लेषण किया जाये तो यह पायंगे की इन दो कारणों के लिए केवल पुरुषो को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है एवं किसी और नजरिये से देखा जाना भी प्रासंगिक नहीं होगा। हालांकि पुरुष रोग विज्ञान के लिए यह भी सोचना है की लड़कियों का पहनावा, जो कई जगह उत्तेजित करता है, लड़कियों का शराब पीकर मदमस्त हो जाना एवं ये परवाह ना करना की वो कहाँ व किसके साथ है भी ऐसी घटनाओ को अंजाम देती है। यह भी कहा जाता है की दिमागी रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सकता है, लेकिन चिन्हित होते हुए भी उससे बचना मुश्किल ही है।

★ **सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य :-** सामाजिक एवं आर्थिक कारण, जो इसके लिए जिम्मेदार है पर अगर मुख्यत: बात करे तो शिक्षित लोगो का प्रतिशत जो कुछ वर्षो में बढ़ा है, परन्तु फिर भी अब भी बहुत नाकाफी है और यह कारण सीधे-सीधे कई और समस्याओं से जुड़

जाता है, जिसमें अपराध बढ़ना शामिल है। वही गरीबी भी एक कारण है। देश में खुले में शौच के लिए मजबूर अब भी देश की 70% आबादी में देश की महिलाएँ बाहर अँधेरे में एकांत में निकलती है, जो आसान शिकार बनती है उन मानसिक विकृत लोगों का, जिन्हें उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी होती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये पाया गया है की बलात्कार के 88% से ज्यादा मामलो में बलात्कार की घटना रिश्तेदारों द्वारा, दोस्त या जान पहचान वाले द्वारा कारित की जाति है। ये केवल समाज में बढ़ते फूहड़पन एवं पाश्चत्य संस्कृति का प्रभाव है। जिससे रिश्तो में सम्मान एवं शर्म की कमी है तथा अत्यधिक खुलापन है। इन्टरनेट एवं टीवी पर परिवार के साथ देखे जाने वाली हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मों में नग्नता का खुला प्रदर्शन है या उनके बीच में प्रदर्शित भिन्न-भिन्न प्रकार के विज्ञापन, जिनमे से कई में नग्नता या द्विअर्थी बातो का कोई औचित्य नहीं होता, किन्तु फिर भी वैसे परोसे जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से किसी भी अनजान से तुरंत दोस्ती फिर साथ खाना-पीना एवं जश्न मनाना, जिसमे अर्धनग्न होकर जाना बहुत बड़ा कारण है। जिसे 21वीं सदी की सोच है, ऐसा बताकर सही ठहराया जाता है। किन्तु कई मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं की भारत जैसे देश में अभी उस तरह के खुलेपन की स्वीकार्यता नहीं है, जैसी अन्य विकसित देश में है। किन्तु अंधेपन में उनका अनुसरण दुर्गति की ओर ले जा रहा है। बहरहाल, देश की इसी सोच को बदलना है, ताकि जिस संविधान से देश चल रहा है उस संविधान के अनुसार उन लड़कियों एवं महिलाओ को अपने ढ़ंग से चीजें करने की आजादी मिले।

✯ **कानूनी परिप्रेक्ष्य :-** देश के कानून प्रक्रिया जो जटिल से जटिलत्तम तक का सफर तय करती है। देश में लाखो प्रकरण लंबित है एवं बलात्कार के कई मामलो में जहाँ एक तरफ ऐसा एक बड़ा प्रतिशत है, जो ये कहता की कई घटनाओं को या तो स्वयं लड़की द्वारा या उसके परिवार द्वारा केवल बदनामी और कानून की जटिलताओ के कारण दबा दिया जाता है एवं दूसरी तरफ यह भी है की देश में दर्ज हुए बलात्कार के लगभग आधे से ज्यादा प्रकरणों में आरोपी दोषमुक्त हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है देश की अति सुस्त एवं निराशाजनक प्रदर्शन है। जिसमे प्रारंभिक जाँच में सुस्ती, भ्रष्टाचार, आदि करने वाली पुलिस व्यवस्था, जहाँ लोग इनके होने से सुरक्षित महसूस करने के स्थान पर इनसे भयभीत रहते हैं।

दिल्ली में अगस्त 2012 के अध्ययन में यह सामने आया था की दिल्ली जिला न्यायालय में चले 40 बलात्कार के मामलो में 23 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया, जिसका कारण पुलिस की असफल एवं सुस्त जाँच थी। बलात्कार के मामले दर्ज एवं साबित होने पर भी कोई सख्त कानून नहीं, जो उदहारण के तौरपर समाज में प्रेषित किया जाये। आम जनता के मानस में यह अंकित है की आज नहीं तो कल आरोपी छुट ही जायेगा। इतने वीभत्स एवं संगीन अपराध करके भी आदमी का उस समाज में लौटना औरो के हौसला उस कृत्य को करने के समय बुलंद करते हैं। हालांकि बीते कुछेक दिनों में बलात्कार की घटनाओं पर दोषियों को फांसी की सजा मुव्वकील करने का कार्य न्यायालय द्वारा प्रकाश में आया है तो वही पुलिस भी बार-बार इन अपराधियों को न्यायालय से छूट जाने से तंग आकर उनका एनकाउंटर किया जाने से पीड़िता व समाज के कुछ लोग जरूर खुश हैं। बहरहाल, समाज को अगर ऐसे अपराधो से मुक्ति चाहिए तो हमें शिक्षा व संस्कारो को आज के युग से जोड़ना होगा। केवल किसी संस्कृति को दोष देकर पल्ला झाड़ना किसी की आजादी के लिए घातक है। ऐसी कठोर कानून व्यवस्था बनानी होगी, जो मिसाल बने व ऐसे अपराध करने वालो के हौसले तोड़े।

गौरतलब हो कि भारत के पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला देश के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से अलग नहीं है। धूल भरे मैदानों के बीच में बसे हुए गाँवों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ नाममात्र की नजर आती हैं। इस इलाके की महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन से परिचित होने के बाद पता चलता है कि यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने उनके साथ होने वाले बलात्कार या यौन हिंसा की शिकायत नहीं दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामले में तीसरे स्थान पर है। जाहिर है इन आंकड़ों में उन महिलाओं का मामला शामिल नहीं है जो अपने साथ होने वाले अपराध पर चुप रह गईं। इन इलाके की महिलाएं बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के बावजूद इनके चुप रह जाने के पीछे पाँच प्रमुख कारण उभर कर आए, जिसे हमारे सूत्र ने इकट्ठा किया। वे इस प्रकार है :-

☞ **लड़की की शादी करनी होती है :-** एक गाँव में एक किशोरी के साथ चार साल पहले हुई बलात्कार की घटना घटी। वो लड़की रोज की तरह सुबह शौच करने के लिए खेत में गई थी तब उसके संग बलात्कार हुआ। उसके माता-पिता को पता था कि किसने बलात्कार किया है, लेकिन उन्होंने इसकी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। कई गाँव वालों के द्वारा कहा गया कि उस व्यक्ति पर पहले भी एक बलात्कार का आरोप लग चुका था। लड़की के एक रिश्तेदार द्वारा कहा गया कि लड़की की अगले कुछ सालों में शादी करनी है। अगर बलात्कार की बात सार्वजनिक हो जाती तो उसके लिए वर ढूंढना मुश्किल हो जाता। ग्रामीण इलाकों में शादी के लिए कौमार्य एक जरूरी मानक है। लड़की और उसके माता-पिता नहीं चाहते कि उनकी पहचान जाहिर हो। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले सहयोग से उन्हें ढांढस तो मिला, लेकिन वो बलात्कारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। बलात्कारी को सजा दिलाने का मतलब होगा मामले को सबके सामने लाना। लड़की अब कॉलेज में पढ़ने जाती है और वो अपने दुखद अतीत को भूलकर जीवन में आगे

बढ़ना चाहती है।

☞ **बदनामी का डर :-** कथित निचली जाति से आने वाली और एक भूमिहीन किसान की पत्नी बंदना बागदी भी उसी गाँव में रहती हैं, उनके संग भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। एक तालाब के किनारे बनी अपनी जर्जर झोपड़ी में वो कहती हैं कि मेरा भी बलात्कार हो जाता लेकिन मैं भागने में सफल रही। जब वो अपने पति और भाइयों के साथ दोषी का सामना करने जाने लगीं तो गाँव वालों ने उन्हें रोक दिया। वो बताती हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक बुरी औरत हूँ जो एक अच्छे आदमी के पीछे पड़ गई है। यहाँ जैसे परंपरागत ग्रामीण समाजों में पीड़ित पर ही दोष मढ़ देने का चलन आम है।

☞ **दोषी ज्यादा ताकतवर :-** केलाई गाँव की 60 वर्षीय गोलेचरा बेवा अपने को असहाय पाती हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी 19 वर्षीय अजिदा खातून एक शाम जब घर वापस आ रही थीं तो किसी ने उन पर हमला किया। अजिदा भागकर अपने को बचाने में सफल रहीं। गोलेचरा कहती हैं कि एक गरीब अनपढ़ बूढ़ी महिला के लिए पुलिस में जाना बहुत मुसीबत भरा काम है। गाँव की पंचायत में जाया जा सकता है, लेकिन उससे लड़की की बदनामी होगी। वो कहती हैं, हमारे लिए इज्जत ही सब कुछ है। उसके बिना हम इस गाँव में नहीं जी सकते। उनकी घबराहट की एक बड़ी वजह है हमला करने वाले व्यक्ति का संपन्न होना, जिनके सामने वो खुद को असहाय महसूस करती हैं। खाड़ी देशों में मजदूरी के माध्यम से इस इलाके में पैसे की आमदनी का नया रास्ता खुला है। कई बलात्कार पीड़ितों का मुकदमा लड़ चुके स्थानीय वकील राजीव लोचन रॉय कहते हैं कि पैसे से लोगों में अहंकार बढ़ गया है। अपनी गलत हरकतों को पैसे और ताकत के बल पर जायज ठहराने का चलन बढ़ा है। वो कहते हैं, कि यह पुराने जमाने की तरह है जब सामंती जमींदार गरीब तबके की औरतों पर अपनी मर्जी थोपते थे। ऐसे मामलों में अक्सर पैसे लेकर मामला निजी तौरपर सुलटा दिया जाता है और पुलिस तक बात नहीं पहुँचती।

☞ **गाँव की इज्जत :-** व्यक्तिगत इज्जत की तरह गाँव की इज्जत भी ऐसे अपराधों के दर्ज नहीं होने का बड़ा कारण हैं। यहाँ के गाँव शादी-ब्याह और पारिवारिक संबंधों के कारण आपस में कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। अगर बलात्कार का मामला पुलिस में जाता है तो पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा दाँव पर लग सकती है। इस कारण समुदाय के अंदर ऐसे मामलों को दबा लेने का दबाव रहता है। ऐसे मामलों में माना जाता है कि चुप रहने पर कोई सार्वजनिक विवाद नहीं होगा और समाज में शांति बनी रहेगी।

☞ **राजनीतिक दबाव :-** बापी दास की पत्नी का मामला परेशान कर देने वाला है। पुलिस ने इस मामले को आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद हुई हत्या के मामले के रूप में दर्ज किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसका खंडन करती है। जिसके अनुसार महिला के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाया गया थ। बापी दास दिल्ली और कोलकाता के मानवाधिकार आयोगों में न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। दास की मदद करने वाले एक स्थानीय नागरिक अधिकार संगठन को लगता है कि पुलिस पर बलात्कार के मामलों में कमी दिखाने का राजनीतिक दबाव रहता है।

दिगर बात है कि भारत में वैसे तो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहीं देश में उन्हीं देवी समान महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे संस्कारी देश में बलात्कार की प्रथा कहां से आई या इसे कौन लेकर आया? प्राचीन भारत के रामायण, महाभारत आदि लगभग सभी हिंदू ग्रंथों के उल्लेखों में अनेकों लड़ाईयां लड़ी गईं और जीती गईं, लेकिन विजेता सेना ने कभी किसी स्त्री पर बुरी नजर या बलात्कार जैसा प्रयास नहीं किया। महाभारत में पांडवों की जीत हुई और लाखों सैनिक मारे गए। इस समय पांडव सैनिकों ने किसी भी कौरव सेना की विधवा स्त्री को हाथ नहीं लगाया। 220 से 175 ईसापूर्व में यूनान के शासक डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। उसके समयकाल में भी बलात्कार का जिक्र नहीं मिलता है। इसके बाद यूक्रेटीदस ने भारत पर राज किया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यहां भी बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। मीनेंडर ने सिंधु के पास पंजाब और स्वात घाटी से लेकर मथुरा तक राज किया लेकिन उसके शासनकाल में भी कभी कोई बलात्कार नहीं हुआ। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने पर लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन यूनानियों की सेनाओं ने किसी भी भारतीय महिला पर बुरी नजर नहीं डाली। इसके बाद शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। 130 ई० से 188 ई० तक उन्होंने शासन किया, लेकिन इनके राज्य में भी बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है। तिब्बत के सुइशि कबीले की लड़ाकू प्रजाति कुषाणों ने भी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, लेकिन इनके इतिहास में भी स्त्रियों के साथ बलात्कार की कोई घटना नहीं है। इसके बाद भारत पर हूणों ने आक्रमण किया और यहां पर राज किया। ये क्रूर तो थे, परंतु बलात्कारी होने का कलंक इन पर भी नहीं लगा।

अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, जहां से इस्लामिक आक्रमण शुरु हुआ और यहीं से भारत में बलात्कार का प्रचलन शुरु हुआ। सन् 711 ई०वी में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में खलीफा को तोहफा भेज दिया। तब शायद भारत की स्त्रियों पर पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ था, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियों और साधारण भारतीय स्त्रियों का जीती हुई आक्रांत सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार और अपहरण किया गया था। इसके बाद 1001 में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद उसकी सेना ने हजारों औरतों का बलात्कार किया। बस यहीं से शुरु हुआ भारत में बलात्कार का प्रचलन। महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का इतना घिनौना स्वरूप तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी नहीं दिखा। अंग्रेजों ने भी भारत को बहुत लूटा, लेकिन कभी उनकी गिनती बलात्कारियों में नहीं हुई। इतिहासकारों की मानें तो भारत में स्त्रियों पर अत्याचार और बलात्कार

की घटना ईस्लामिक आक्रमण और शासनकाल के बाद हुई। आज भारत में महिलाओं की दशा बहुत खराब है और इसका कारण इस्लाम के शासक हैं।

सनद् रहे कि बलात्कार का कोई बड़ा मामला सामने आते ही पश्चिमी दुनियां में भारत को बलात्कारियों का देश साबित करने की होड़-सी लग जाती है। कठुआ, उन्नाव और सूरत की घटनाओं के बाद एक नाबालिग से बलात्कार के दोषी आसाराम को मिली सजा से पश्चिमी जगत की बांछें एक बार फिर खिल गई हैं। एक बार फिर एक सुर में ऐसा स्वांग भरा जा रहा है, जैसे ऐसे घिनौने कुकर्म केवल भारत जैसे देश में ही हो सकते हैं। बाकी दुनिया, विशेषकर यूरोप-अमेरिका मानो दूध के धुले इतने पाक-साफ हैं, कि उनके यहां ऐसा कुछ होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फ्रांसीसी अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्द ने यह कहना जरूरी समझा कि 'भारत में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी और अन्य पदाधिकारी महिलाओं की सुरक्षा की तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे। भारत में इसकी जरूरत भी है।' सुश्री लगार्द भूल गयीं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जिस ऊंचे पद पर वे आज बैठी हैं, उसी पद पर, एक नवंबर 2007 से 18 मई 2011 तक, उन्हीं के देश के जो जाने-माने सोशलिस्ट नेता दोमिनीक त्राउस-कान विराजमान थे, उन्हें एक होटल की महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार के आरोप में ही अपना पद गंवाना पड़ा था। त्राउस-कान 1997 से 1999 तक फ्रांस के अर्थ और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। यह कहा जा सकता है कि उनकी प्रबल संभावना थी कि 2012 में वे फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाते, पर ऐसा नहीं हो सका। 18 मई 2011 वाले दिन अमेरिकी पुलिस ने न्यूयॉर्क में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे जिस होटल में ठहरे थे, वहां कमरे की साफ-सफाई करने वाली एक अफ्रीकी महिला कर्मचारी ने अपने साथ बलात्कार का उन पर आरोप लगाया था। जरा सोचिये! जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सर्वोच्च पदाधकारी था, फ्रांस का अगला राष्ट्रपति बन सकता था, वह साफ-सफाई करने वाली एक महिला के साथ बलात्कार के प्रयास में गिरफ्तार हो जाता है! उसकी उत्तराधिकारी भारत के प्रधानमंत्री से कहती है कि 'महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान दें'। त्राउस-कान को करीब तीन महीने पुलिस की हिरासत तथा घर के भीतर नजरबंदी में रहना पड़ा. एक गोपनीय आपसी समझौते के आधार पर उन्हें रिहाई मिली. एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने माना कि होटल की

उस महिला कर्मचारी के साथ उनके 'अवैध संबंध' थे. दोमिनीक श्त्राउस-कान अपनी कामुकता के लिए जाने जाते थे। लेकिन, तब उन्हें या अपने देश के अन्य नेताओं को सुश्री लगार्द ने वैसे कोई सलाह नहीं दी, जैसी वे आज भारत के प्रधानमंत्री को देना उचित समझती हैं. ऐसा भी नहीं है कि त्राउस-कान प्रकरण के साथ फ्रांस में महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, दुराचार या कामुकतापूर्ण यौनशोषण का अंत हो गया है. बल्कि स्थिति तो यह है कि यूरोपीय संघ में जर्मनी के बाद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देश फ्रांस में लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन हिंसा की प्रवृत्ति सोचनीय बन गयी है।

फरवरी 2018 में प्रकाशित एक सबसे नवीनतम सर्वेक्षण से सामने आया कि फ्रांस की औसतन हर आठ मे से एक महिला (12 प्रतिशत, कुल 40 लाख) को अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार तो रतिक्रिया की सीमा तक के (पेनिट्रेटिव) बलात्कार का शिकार होना ही पड़ता है. इस तरह की महिलाओं में 31 प्रतिशत का बलात्कारी उनका अपना ही पति या जीवनसंगी था. 19 प्रतिशत का बलात्कारी उनके परिचितों में से कोई था और और 17 प्रतिशत का कोई अपरिचित था. 58 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनके साथ यौन-दुराचार हुआ और 43 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें कामुकतापूर्ण ढंग से सहलाया गया. उन महिलाओं की संख्या भी 50 प्रतिशत तक थी, जिन्हें शाब्दिक अपमान या कामुक फब्तियों का निशाना बनाया गया. अधिकतर को अपने साथ कई बार दुराचार झेलना पड़ा. वास्तव में, क्रिस्टीन लगार्द के फ्रांस में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति सोचनीय ही नहीं, इतनी अधिक सोचनीय है कि राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों को, महिलाओं के साथ हिंसा-विरोधी 25 नवंबर 2017 वाले अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, इस बारे में अपने आवास में एक अलग सभा बुलानी पड़ी। सभा में दुख प्रकट करते हुए राष्ट्रपति माक्रों ने कहा, "हमारा समाज कामुकता से बीमार है," यह बेवाक स्वीकारोक्ति सबके लिए बहुत चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि फ्रांस में यौन-अपराध भयावह होते जा रहे हैं, औसतन हर तीन दिन पर, कोई न कोई महिला अपने जीवनसाथी की हिंसा के कारण दम तोड़ बैठती है। राष्ट्रपति-भवन 'एलिजे पैलेस' में आयोजित इस सभा में उन्होंने इस समस्या से लड़ने के लिए एक ऐसी कार्ययोजना (ऐक्शन प्लान) की घोषणा की, जिसके अधीन कुछ नये कठोर कानून भी बनाये जायेंगे। भाषण से पहले उन्होंने और आमंत्रित लोगों ने उन 123 महिलाओं की याद में एक मिनट का मौन रखा, जो 2016 में अपने मौजूदा या पिछले जीवनसाथी के हाथों मारी गयीं।

ज्ञात हो कि फ्रांस में स्त्री-पुरुष समानता के लिए एक अलग से मंत्रालय है। राष्ट्रपति माक्रो ने ऐलान किया था कि इस मंत्रालय के बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी. ऐलान और भी हुए. जैसे नारी-समानता की विभिन्न योजनाओं के लिए 2018 से 42 करोड़ यूरो अलग से आवंटित किये जायेंगे। यौन-अपराधों से बचाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों और किशोर छात्रों के लिए यौनशिक्षा के नये पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे। राष्ट्रपति माक्रों ने बताया कि एक नया कानून बनाकर राह चलती लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी या अभद्र छींटाकशी को भी दंडनीय अपराध बना दिया जायेगा। उनका यह भी कहना था कि इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए व्यस्कों के लिए भी

नैतिक शिक्षा के कोर्स चलाये जायेंगे। साथ ही, महिलाओं के प्रति हिंसाभाव उकसाने वाले इंटरनेट-वीडियो वगैरह पर कड़ी नजर रखी जायेगी।

राष्ट्रपति माक्रों ने माना था कि फ्रांसीसी समाज कामुकता से बीमार है, पर यह नहीं बताया कि यह अति कामुकता आती कहां से है? जो लोग फ्रांस को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि फ्रांसीसी कला, संगीत, साहित्य और फिल्मों में कामवासना की सदा प्रचुरता रही है। इस प्रचुरता का लोगों की मानसिकता और जीवन-शैली पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक ही है, रही-सही कमी इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील वीडियो पूरी कर दे रहे हैं। बच्चों का अश्लील यौन-ज्ञान तो बड़ों से भी बढ़-चढ कर है। लेकिन, बात जब बलात्कारों की आती है तो फ्रांस सहित यूरोप के करीब हर देश में 'भारत के हिंदू समाज' को कोसने-धिक्कारने और उसे 'बलात्कारियों का देश' सिद्ध करने की होड़-सी लग जाती है। इस बार पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके और अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस होड़ में शामिल होते हुए कठुआ की बलात्कारी हत्या को भयावह करार दे दिया।

गौरतलब हो कि कोई सुनने-समझने को तैयार नहीं है कि स्त्री-समाज का यौन-शोषण और बलात्कार के रूप में उसकी पराकाष्ठा भारतीय नहीं, फिल्मों, सेटेलाइट टीवी और इंटरनेट के माध्यम से अपनी स्वच्छंद जीवनशैली की नग्नता और अश्लीलता को घर-घर पहुंचाने वाली पश्चिमी संस्कृति की फैलायी हुई एक विश्वव्यापी बीमारी है। भारतीय फिल्मों में चुंबन-आलिंगन के अभाव को यही पश्चिमी संस्कृति 'दकियानूसी पिछड़ापन' कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करती थी। अब, जबकि भारतीय फिल्म, कला और मीडिया जगत ने यह 'दकियानूसी पिछड़ापन' पीछे छोड़ दिया है, तो पश्चिम वाले कुपित हैं कि भारत में यौन-अपराध बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय समाज को बदलना होगा। यदि भारतीय समाज को बदलना इतना सरल है और वही, न कि पश्चिम का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद बीमारी की जड़ है, तो फिर स्वयं पश्चिम में यौन-अपराध, हत्या और बलात्कार भारत से कई गुना अधिक क्यों हैं? स्वयं पश्चिम अपना समाज बदल कर अपने यहां यौन-अपराधों और बलात्कारों का अंत क्यों नहीं कर देता? सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बहत्तर छेद! इस बीच यौन-अपराधों और बलात्कारों वाली यह बीमारी अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में भी इतनी संक्रामक हो गयी है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे तक यौन-अपराध करने लगे हैं। उन्हें इसका बोध ही नहीं होता कि टेलीविजन फिल्मों, इंटरनेट वीडियो या स्मार्ट फोन की तस्वीरों में व्यस्क जो क्रीड़ाएं करते दिखते हैं, वे हम बच्चों के लिए वर्जित, हानिकारक या अपराध क्यों हैं? फ्रांस के स्कूलों में यौन-हिंसा के प्रति आंख

खोलने वाले नये पाठ्यक्रम शुरू करने की राष्ट्रपति माक्रों की कार्ययोजना इस बात की पुष्टि है कि लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन-हिंसा व्यस्कों के बीच ही नहीं, छोटे-छोटे स्कूली बच्चों के बीच भी भयावह आयाम धारण कर चुकी है। स्थिति यह है कि जर्मनी और फ्रांस ही नहीं, सारा यूरोप दशकों से नारी-समानता की सौगंध खा रहा है, पर हर जगह असमानता-भरे दुराचार की दुर्गंध ही फैलती मिल रही है। 28 देशों और 50 करोड़ जनसंख्या वाले यूरोपीय संघ की एक 'मौलिक अधिकार एजेंसी' है, जिसे संक्षेप में 'एफआरए' कहते हैं। संघ के देशों में महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने के लिए उसने सभी 28 देशों की 18 से 74 वर्ष आयु के बीच की 42 हजार (हर देश में डेढ़ हजार) महिलाओं के बीच एक सर्वेक्षण किया। मार्च 2014 में प्रकाशित उसके नतीजों की सूची बड़ी लंबी और निराशजनक है। सबसे अधिक चौंकाने वाले कुछ तथ्य और आंकड़े इस प्रकार हैं:-

☞ 42 हजार में से हर तीसरी महिला ने बताया कि उसे अपने 15वें जन्मदिन के बाद कम से कम एक बार शारीरिक या यौन-हिंसा या दोनों झेलनी पड़ी हैं।

☞ हर 20वीं महिला (93 लाख) को कम से कम एक बार बलात्कार की वेदना सहनी पड़ी है। 12 प्रतिशत (2 करोड़ 10 लाख) को तो 15 साल की होने से पहले ही किसी व्यस्क की हवश का शिकार होना पड़ गया।

☞ 22 प्रतिशत (4 करोड़ 18 लाख) को अपने जीवनसंगी की ओर से शारीरिक या बलात्कारी हिंसा झेलनी पड़ी। 43 प्रतिशत (7 करोड़ 15 लाख) को मानसिक यातना से गुजरना पड़ा। दोनों प्रकार की 67 प्रतिशत पीड़िताओं ने पुलिस के पास कभी शिकायत नहीं की।

☞ 33 प्रतिशत (6 करोड़ 13 लाख) को अपने बचपन में ही किसी वयस्क की ओर से शारीरिक प्रताड़ना या लैंगिक हिंसा का कटु अनुभव मिल गया।

☞ 11 प्रतिशत (1 करोड़ 85 लाख) को भद्दे ई-मेल और एसएमएस भेज कर तंग किया गया।

☞ 32 प्रतिशत (6 करोड़ 8 लाख) ने कहा कि उन्हें अपने अधिकारियों, सहकर्मियों या ग्राहकों ने तंग किया।

☞ अपने पति या संगी से इतर यौन-हिंसा झेल चुकी हर दसवीं महिला ने कहा कि उसे अपरिचित लोगों ने सामूहिक बलात्कार या शीलभंग का शिकार बनाया।

यूरोपीय संघ की इस 'मौलिक अधिकार एजेंसी' के व्यापक सर्वेक्षण से एक और चौकाने वाला तथ्य भी सामने आया। इस पर शायद ही कोई विश्वास करेगा कि जिस देश का समाज जितना अधिक खुशहाल, उदारवादी और सुशिक्षित है, वहां महिला उत्पीड़न का अनुपात भी उतना ही अधिक है! यूरोपीय संघ के देशों में स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड (हॉलैंड) और फिनलैंड इन तीनों कसौटियों के अलावा भ्रष्टाचार-मुक्त सुशासन में भी सबसे अग्रणी माने जाते हैं। इन देशों की 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने कहा कि 15 साल की उम्र के बाद कभी न कभी यौन-उत्पीड़न से उनका सामना हो ही गया। यूरोपीय संघ का सबसे उदार और सबसे समाज-कल्याणकारी देश कहलाने वाला स्वीडन, उत्पीड़न की 81 प्रतिशत शिकायतों के साथ पहले नंबर पर रहा। उसके बाद के स्थानों पर 70 प्रतिशत से अधिक शिकायतों के साथ क्रमशः डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और फिनलैंड रहे। स्वीडन की संसद में 47 प्रतिशत महिलाएं बैठती हैं। देश के 22 मंत्रियों में से नौ महिलाएं हैं। तब भी, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के लिहाज से यूरोप में वही नंबर एक है। गरीब बुल्गारिया में सबसे कम यौन-हिंसा यूरोपीय संघ के इस सर्वेक्षण में उसके सबसे गरीब और कुशासित देशों में गिने

जाने वाले बुल्गारिया को 24 प्रतिशत शिकायतों के साथ, सबसे अंतिम स्थान मिला। यानी, वहां महिलाओं का सबसे कम यौन-उत्पीड़न होता है। महिलाओं के साथ गंभीर किस्म की यौन-हिंसा के मामले में भी डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन क्रमशः 52, 47 और 46 प्रतिशत के साथ प्रथम तीन स्थानों पर रहे। स्वीडन की विदेशमंत्री मार्गोट वालस्त्रौएम ने एक ट्वीट में लिखा था कि उन्हें तो यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलनों तक में 'जांघ पर हाथ रखने' जैसी शरारतों का सामना करना पड़ा है। इससे यही संकेत मिलता है कि पश्चिम के सबसे सभ्रांत लोगों के बीच भी महिलाएं सबसे पहले कामवासना की ही चीज हैं। यौन-उत्पीड़न की 35 प्रतिशत शिकायतों के साथ जर्मनी का नाम यूरोपीय सर्वेक्षण के मध्यक्रम में दिखायी पड़ता है। इटली, क्रोएशिया या बुल्गारिया जैसे देशों के नाम जहां आर्थिक खुशहाली और शिक्षा का सूचकांक कहीं नीचे है तो कुशासन और भ्रष्टाचार का सूचकांक उतना ही ऊपर है। 30 प्रतिशत से भी कहीं कम अनुपात के साथ गंभीर किस्म की यौन-हिंसा के सबसे निचले क्रम में मिलते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि महिलाओं के साथ यौन-हिंसा या दुराचार एक ऐसी अय्याशी है, जिस का शौक ऊंची शिक्षा और मोटी आय वाले लोगों के लिये ही पालना सबसे सरल है।

सच तो यह है कि यदि बलात्कारों के लिए भी कोई नोबेल पुस्कार होता तो वह नोबेल पुरस्कारों के देश स्वीडन को ही मिल रहा होता। प्रति 10,000 निवासियों पर प्रतिवर्ष 53.2 बलात्कारों के साथ स्वीडन इस लिहाज से पूरे यूरोप में पहले नंबर पर और विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत में यह अनुपात केवल 2.6 है, तब भी उसे दुनियां के सबसे बलात्कारी देश के तौरपर बदनाम कर दिया गया है। भारत की जनसंख्या यदि एक अरब 30 करोड़ के बदले स्वीडन की ही तरह एक करोड़ से भी कम होती, तो उसका कोई नाम भी नहीं लेता। स्वीडन में 1975 में बलात्कार के केवल 421 मामले दर्ज किये गये थे, जबकि 40 साल बाद यह संख्या लगभग 16 गुना बढ़ कर 2014 में 6,620 हो गयी थी। भारत में हम जिस इंग्लैंड-अमेरिका की भाषा और रहन-सहन पर मरते हैं, उनका रिकॉर्ड भी बहुत ही शर्मनाक है। इन दोनों देशों की सरकारें यौन-हिंसा के बारे में भरोसेमंद आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित करने से बचती हैं। छह करोड़ 30 लाख जनसंख्या वाले ब्रिटेन के सरकारी अभियोक्ता कार्यालयों के महानिदेशक एलिसन साउन्डर्स ने ब्रिटिश दैनिक 'गार्डियन' को सितंबर 2016 में वहां की स्थिति की झीनी-सी झलक दी, साउन्डर्स ने बताया था कि लड़कियों -महिलाओं के साथ घरेलू दुर्व्यवहार, बलात्कार और मारने-पीटने जैसे अपराध, 2015-16 के दौरान, 10 प्रतिशत से बढ़कर 1,17,568 हो गये। लेकिन, बलात्कार के केवल 4,643 मामले अदालतों तक पहुंचे, जिनके बल पर 2,689 फैसले सुनाये गये। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य तकनीकी माध्यमों द्वारा धौंस-धमकी देने, फोटो या शब्दों द्वारा अपमानित और तंग करने जैसे मानसिक कष्ट पहुंचाने वाले मामले और भी तेजी से बढ़ रहे हैं, साउन्डर्स का कहना था कि इंटरनेट की आड़ लेकर बेझिझक ऐसे अपराध करना बहुत आसान हो गया है। यौन-अपराधों की जांच-पड़ताल सरकारी अभियोजकों के काम का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा बन गया है। ब्रिटेन की स्थिति के बारे में ठोस सरकारी आंकड़ों के अभाव में इस समय जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वहां हर एक लाख जनसंख्या पर साल भर में औसतन 24 से अधिक बलात्कार होते हैं। यह अनुपात भारत की तुलना में कम से कम नौ गुना अधिक है! ब्रिटेन में भी सभी यौन-अपराध पुलिस के कानों तक नहीं पहुंचते। वहां भी ऊंचे तबकों के कैसे नामी लोग भी अपनी कामवासना को काबू में नहीं रख पाते, इसका एक सबूत नवंबर 2017 में रक्षामंत्री सर माइकल फैलन के त्यागपत्र से मिलता है। एक महिला रेडियो पत्रकार ने आरोप लगाया था कि 2002 में टोरी पार्टी के एक रात्रिभोज-सम्मेलन के समय, सर फैलन ने कई बार उसके घुटने पर अपना हाथ रख दिया। महिला पत्रकार का कहना था, 'मैंने बिना किसी गुस्से के, नम्रतापूर्वक उनसे कहा कि यदि उन्होंने फिर यह हरकत की तो मैं उनके मुंह पर तमाचा जड़ दूंगी'।

गौरतलब हो कि ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी यौन-अपराधों के आंकड़े इधर-उधर से जुटाने पड़ते हैं, वे किसी एक ही स्रोत से नहीं मिलते। वहां के 'राष्ट्रीय अपराध सर्वे' (एनसीवीएस) की एक रिपोर्ट का कहना है कि 2008 में वहां हर दिन औसतन 500 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था। 2005 में हर दिन औसतन तीन महिलाओं की हत्या हो रही थी। उस वर्ष कुल मिलाकर 1, 181 औरतें मार डाली गयीं। एक-तिहाई मौतों के लिए उनके पति या प्रेमी जिम्मेदार थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफ्रीकी मूल की अश्वेत अमेरिकी महिलाओं के साथ, श्वेत अमेरिकी महिलाओं की अपेक्षा, 35 प्रतिशत अधिक यौन-हिंसा होती है। 'एनसीवीएस' का ही यह भी कहना है कि 2006 में अमेरिका में महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन-उत्पीड़न के कुल 2,32,960 ऐसे भी मामले हुए, जिनकी पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची। इन सब आंकड़ों के बारे में सोचते समय याद रखना जरूरी है कि अमेरिका की 32 करोड़ जनसंख्या भारत की एक अरब 30 करोड़ जनसंख्या के केवल एक-चौथाई के बराबर है। भारतीय मीडिया की ही तरह विदेशी मीडिया की भी आदत-सी बन गयी है कि जनसंख्या बताये बिना वे भारत जैसे भीम की तुलना ब्रिटेन या बेल्जियम जैसे बौनों से करने लगते हैं। वही अमेरिका में जो महिलायें 20 से 24 साल उम्र की हैं, उनके साथ घरेलू यौन-हिंसा होने का खतरा सबसे अधिक पाया गया है। जो 24 साल या उससे कुछ कम की हैं, उनके साथ बलात्कार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अमेरिका के न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) का आंकलन है कि अपने कॉलेज के दिनों में हर पांच में से एक छात्रा को बलात्कार हो जाने या उसके प्रयास के कटु अनुभव से गुजरना पड़ेगा। इस अनुभव को झेल चुकी पांच प्रतिशत छात्राएं भी पुलिस के

पास शिकायत करने नहीं जायेंगी! 2015 में अमेरिका के 27 विश्वविद्यालयों में किये गये एक अध्ययन से सामने आया कि ग्रेजुएशन कर रही 23 प्रतिशत छात्राएं अपने साथ यौन-हिंसा प्रेरित बलप्रयोग या कामुकतापूर्ण दुर्व्यवहार झेल चुकी थी। यूरोप और अमेरिका से हटकर यदि विश्व-स्तर पर देखा जाये, तो केवल पांच करोड़ 30 लाख की जनसंख्या वाले दक्षिण अफ्रीका का नाम महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन-हिंसा की संयुक्त राष्ट्र सूची में हर साल पहले नंबर पर मिलता है। वहां हर साल 64,000 से अधिक बलात्कार होते हैं। प्रति एक लाख जनसंख्या पर 115 बलात्कार। महिला यौन-उत्पीड़न के अन्य प्रकारों के आंकड़े तो और भी भयावह होंगे। जनसंख्या में दक्षिण अफ्रीका से 24.5 गुना बड़े भारत के राष्ट्रीय अपराध कार्यालय ने 2014 में बलात्कार के 34,651 मामले दर्ज किये थे।

बताते चले कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियेना में संयुक्त राष्ट्र का करीब 500 कर्मचारियों वाला एक ऐसा कार्यालय है, जिसका काम है मादक द्रव्यों और हर प्रकार के अपराधों से संबंधित जानकारियां जमा करना और उनका अध्ययन करना। 'यूएनओडीसी' (यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स ऐन्ड क्राइम) नाम का यह कार्यालय यौन-अपराधों की भी खोज-खबर रखता है। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य देश से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने यहां होने वाले यौन-अपराधों के बारे में भी नवीनतम जानकारियां दिया करें, पर मुश्किल से आधे सदस्य देश ही इस पर ध्यान देते हैं। 'यूएनओडीसी' का कहना है कि करीब 140 देशों ने घरेलू हिंसा के बारे में भी कानून बनाये हैं और 144 देशों में यौन-उत्पीड़न की रोकथाम के भी कानून हैं, पर जरूरी नहीं है कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खड़े उतरें या उनपर ईमानदारी से अमल होता ह ै। 37 देश ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने पर या किसी दूसरी स्त्री के साथ बलात्कार करने के बाद उससे विवाह कर लेने पर, बलात्कारी पुरुष को कानूनी कार्रवाई से छूट देते हैं।

बहरहाल, ऐसे ही लचर कानूनों और पैसे वालों, बाहुबलियों और सत्ताधारियों के निहित स्वार्थों के चलते सारी दुनियां में महिलाओं के साथ बलात्कारों, उनकी हत्याओं और शोषण-उत्पीड़न के अपराधों की बाढ़-सी आ गयी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुमानों में कहा गया है कि हर तीन में से एक (35 प्रतिशत) महिला, अपनों ही या गैरों के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेल चुकी है। उसके बाकी अनुमान इस तरह हैं:-

☞ महिलाओं की दुनियां भर में होने वाली 38 प्रतिशत हत्याएं उनका पुरुष पति या प्रेमी ही करता है। उच्च आय वाले देशों में यह प्रवृत्ति 23.2 प्रतिशत और कम आय वाले दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में 37.7 प्रतिशत है।

☞ अपने जीवन साथी की हिंसा झेल चुकी महिलाओं को अवसाद (डिप्रेशन) ग्रस्त हो जाने की संभावना दो गुनी और उन्हें एड्स रोग हो जाने की संभावना डेढ़ गुनी बढ़ जाती है।

☞ बाल विवाह भी यौन-उत्पीड़न है। दुनिया भर की इस समय जीवित 75 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी गयी।

☞ दुनियां की 12 करोड़ लड़कियों (हर 10 में से एक) को कभी न कभी सहवास या किसी यौनक्रीड़ा के लिए बाध्य किया गया।

☞ खतने की प्रथा वाले 30 देशों में कम से कम 12 करोड़ औरतों और लड़कियों को अधिकतर उस समय गुप्तांग के खतने की पीड़ा भुगतनी पड़ी जब, उनकी आयु पांच साल से कम थी, कुछ की आयु तो केवल कुछ महीने ही थी।

☞ मानव-तस्करी के शिकारों में 71 प्रतिशत अनुपात औरतों व अव्यस्क लड़कियों का होता है। इस तरह की हर चार में से तीन लड़कियों या औरतों से वेश्यावृत्ति करवाई जाती है।

बहरहाल, अदनी ही नहीं, हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां और यूरोपीय संसद की महिला सांसदों जैसी बिरली महिलाएं भी, अक्टूबर 2017 से, गुहार लगा रही हैं कि उन्हें भी महिला होने के नाते यौन-उत्पीड़न भुगतना पड़ा है। अमेरिका के 'द न्यूयॉर्क टाम्स' और 'द न्यूयॉर्क' ने अक्टूबर 2017 में भंडाफोड़ किया था कि हॉलीवुड के सबसे बड़े और जाने-माने फिल्म-निर्माता, हार्वे वाइनस्टीन, अपनी फिल्मों की अभिनेत्रियों के साथ यौन-दुराचार करते हैं। इन दुराचारों की पहली खबर छपते ही ऐसी दर्जनों अभिनेत्रियां और अन्य महिलाएं खुलकर सामने आयीं, जो वाइनस्टीन की तिकड़मों, उत्पीड़नों और बलात्कारों की भुक्तभोगी रह चुकी हैं। इस घटना ने ट्विटर पर 'मी टू' (मैं भी) नाम से एक ऐसे हैशटैग को जन्म दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्वीडन की विदेशमंत्री और यूरोपीय संसद की महिला सांसदों से लेकर महिला वैज्ञानिकों, कलाकारों, पत्रकारों इत्यादि तक हजारों महिला भुक्तभोगियों ने अपनी आपबीतियां् पोस्ट की हैं। वही विश्व के विभिन्न देशों की संसदों के सदस्यों की 'अंतर संसदीय यूनियन' (इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन) ने पांच अलग-अलग भू-खंडों के 39 देशों में महिला सांसदों के अनुभवों का अध्ययन किया। अध्ययन में भाग लेने वाली 82 प्रतिशत महिला सांसदों ने कहा कि अपने संसदीय कार्यकाल में उन्हें भी अपने प्रति मानसिक हिंसा के किसी न किसी रूप को झेलना पड़ा। यह हिंसा पुरुष सांसदों की ओर से किसी भद्दी टिप्पणी, भाव-भंगिमा, इशारेबाजी, घेराव या धमकी के रूप में थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यौन-हिंसा या यौन- उत्पीड़न के अनगिनत रूप-स्वरूप हैं और हर कोई यह हिंसा करने के सक्षम है। चिंता का विषय यह है कि जब नेता, अभिनेता और कानून बनाने वाले सांसद भी यौन-उत्पीड़न के परपीड़ा सुख से मुक्त नहीं कहे जा सकते तो फिर पीड़ितों को कौन और कैसे मुक्ति देगा? लड़कियों और महिलाओं के यौन-उत्पीड़न का वैश्विक आयाम वास्तव में जितना विशाल और भयावह है, उसके प्रति चेतना और जानकारी उतनी ही क्षुद्र और हास्यास्पद है। उत्पीड़ित महिलाओं का ही जीवन नरक नहीं बन जाता, उनकी मर्मांतक पीड़ा की छाया में पले बच्चों के भावी विकास का भी बेड़ा गर्क हो जाता है।●

अपराध नियंत्रण में आम नागरिकों का सहयोग जरूरी : राघव

लोकतंत्र की जननी कहा जाने वाला वैशाली जिला हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे मामला विश्वप्रख्यात हरिहर क्षेत्र मेला (सोनपुर) का हो, जहां छोटे-बड़े पशुओं का बड़े पैमाने में क्रय-विक्रय होता है या फिर अपराध को लेकर हो या फिर पर्यटन को लेकर हो। दूसरी ओर इस जिले की चर्चा हम इस रूप में भी करते हैं कि यहां भगवान महावीर की जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलम्बियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। वही भगवान बुद्ध का इस धरती पर तीन बार आगमन हुआ, यह उनकी कर्म भूमि भी थी। महात्मा बुद्ध के समय सोलह महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्त्वपूर्ण था। अतिमहत्त्वपूर्ण बौद्ध एवं जैन स्थल होने के अलावा यह जगह पौराणिक हिन्दू तीर्थ एवं पाटलीपुत्र जैसे ऐतिहासिक स्थल के यह निकट है। साथ ही साथ मशहूर राजनर्तकी और नगरवधू आम्रपाली, अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध थी और इस शहर को समृद्ध बनाने में एक बड़ी मदद की। आज वैशाली पर्यटकों के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। वैशाली में आज दूसरे देशों के कई मंदिर भी बने हुए हैं। गौरतलब हो कि 12 अक्टूबर 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग होकर वैशाली एक नया जिला बना और इसका मुख्यालय हाजीपुर बनाया गया। आज इसी हाजीपुर में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर दिलेर, कर्मठ एवं तेजतर्रार राघव दयाल को अपराध नियंत्रण एवं अपने अनुमंडल में शांति-व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी मिली है और वह इसे निर्भीकता के साथ अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। सनद् रहे कि 1994 बैच के राघव ने लखीसराय जिले में अपने प्रशिक्षण के साथ बिहार पुलिसिंग में योगदान देना प्रारंभ किया और कई अपराधग्रस्त जिलों के थानों में कार्य करके उस क्षेत्र को भयमुक्त बनाते हुए, अपराधियों के छक्के छुड़ाते हुए आज सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हाजीपुर के पद पर कार्यरत्त हैं। कई थानों में कार्य के बाद पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत्ति होते ही इनकी प्रथम पोस्टिंग पुलिस विभाग के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) में हुई और यहां पर उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों के साथ मिलकर कई संगीन अपराधियों को पकड़ा और कई हथियारों को बरामद भी करवाया। ज्ञात हो कि एसटीएफ में कार्य करने के बाद बीते वर्ष अगस्त 2019 में राघव दयाल को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सदर, हाजीपुर बनाया गया है। चूकि हाजीपुर सहित पूरा वैशाली अपराधियों के निशाने पर फिलवक्त देखा जा रहा है, इस बाबत कड़ी सुरक्षा के साथ अपराध पर नियंत्रण करना, केश का उद्भेदन करना एवं टाइम टू टाइम क्राइम मिटिंग कर अपराध पर कैसे लगाम लगे, इसकी समीक्षा करने में इनकी व्यस्तता देखी जा सकती है। वर्तमान परिस्थिति में हाजीपुर में अपराध नियंत्रण कैसे हो, की चर्चा को लेकर प्रस्तुत है पत्रिका के संयुक्त संपादक **अमित कुमार** द्वारा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हाजीपुर, **राघव दयाल** के साक्षात्कार के प्रमुख अंश :-

❖ आपने पुलिस उपाधीक्षक पद पर पहला योगदान एसटीएफ में दिया और इसके बाद अभी आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सदर, हाजीपुर के पद पर अपना योगदान दे रहे हैं, क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं?

दोनो का कार्य प्रणाली अलग है। कार्य करने का पैर्टन अलग है। एसटीएफ को पब्लिक के बीच में नहीं रहना है। उनका काम करने का टारगेट फिक्स है और अनुमंडल में हमेशा विधि-व्यवस्था की समस्या बनी रहती है। विधि-व्यवस्था का कार्य देखते हुए अपराधियों पर कार्यवाई करना है, उनपर अंकुश लगाना है। हमलोगों को यहाँ प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनो तरह का कार्य करना होता है। घटना कारित न हो, इसके लिए भी कार्यवाई करना है और घटना हो गया है तो डिटेक्शन करना है, उसपर ठोस कार्यवाई करना होता है, तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहकर हमें दोनो तरह का कार्यवाई करना होता है। पब्लिक से चौबिसो घंटे रू-ब-रू होते रहना है।

❖ जिस तरह से हाजीपुर में अपराध घट-बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अपराधी हाजीपुर को टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं? क्या कारण मानते हैं?

ऐसा है अमित जी की मैं यहाँ पर अगस्त 2019 में ज्वाइन किया था। सदर अनुमंडल हाजीपुर के क्षेत्र में अपराध है और अपराध की घटना घटती है और अपराध होता है तो उसपर डिटेक्शन भी होता है। इसके साथ ही अपराधी पकड़ा भी रहे हैं और मैं समझता हूं कि अपराध पर धीरे- धीरे हमलोग नियंत्रण भी कर रहे हैं। चूकि वैशाली जिला पटना से सटा हुआ जिला है और हाजीपुर को पटना का द्वार बोला जाता है। हाजीपुर से आपको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण और पुनः घुमकर दानापुर-दिघा इलाके से पटना जाने का रास्ता है। यहां चारो तरफ से रास्ता खुला हुआ है। यहां पर दियारा का क्षेत्र मुख्य तौरपर है, क्योंकि यहां पर उनको छिपने में, आने-जाने और भागने में

आसान होता है। वही एक जिला से दूसरे जिला में जाना आसान है। घटना कारित किया और दूसरे जिला में चला गया। यहां पर अगल-बगल जिले के भी अपराधी आते हैं और घटना कारित करके निकल जाते हैं। कुछ अपराधी अगल-बगल के जिले में किराये के मकान पर रहकर अपराध को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। जैसे पटना, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर में पढ़ने के नाम पर डेरा लेकर रह रहा है और अपराध करके निकल गये। कुछ अपराधी हमारे अनुमंडल क्षेत्र के हैं। यहां के अपराधी बहुत ही संगठित रूप से अपराध करने में माहिर हैं। लेकिन, हरेक परिस्थिति में अपराधियों पर नकेल कसने में हमलोग तत्पर हैं और बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा भी गया है तथा जेल के अंदर भी किया गया है और हम नकेल कसने में कामयाब हैं तथा अपराध नियंत्रण किया जा रहा है।

❖ सोना लूट, पेट्रोल पंप डकैती, रायपुर व्यवसायी का अपहरण सहित दर्जनों मामलों में पुलिस को क्या सफलता मिली है?

एक सोना लूट की घटना घटी थी और घटना घटने के तुरंत बाद जब हमलोगों ने सी.सी.टी.वी. फुटेज को खंगालने लगे तो उसी दरम्यान हमलोगों को यह क्लीयर हो गया कि कौन-कौन अपराधी इस घटना में शामिल है। काण्ड का उद्भेदन समझीए की घटना घटी और हमलोग वहां पहुंचे और दो-ढ़ाई घंटे के अंदर ही काण्ड का उद्भेदन हो गया था। इस घटना में मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस सोना लूट काण्ड को जो कारित किया गया था, उसी के कुछ अपराधकर्मी पकड़े भी गये और लूटा हुआ सोना में से कुछ सोना का बरामदगी भी हुआ है। कुछ अभी फरार चल रहे हैं, उनपर कार्यवाई जारी है। दूसरा पेट्रोल पंप लूट काण्ड करीब-करीब उद्भेदित है। इसमें जो भी अपराधी घटना कारित किये थे, करीब-करीब मैं समझता हूं कि शत्-प्रतिशत पेट्रोल पंप केश का उद्भेदन किया जा चुका है तथा एक को पकड़ा भी गया है। उसमें से कुछ अपराधी फरार है, उसे हमलोग पकड़ने के फिराक में है। तीसरा आपने पूछा व्यवसायी अपहरण मामले के बारे में तो, छत्तीसगढ़ व्यवसायी के अपहरण का जो मामला है, उसमें भी कुछ तार यहां पर जुड़ा हुआ था और छापामारी भी किया गया था, लेकिन जो अपहृत थे वह यूपी से बरामद हुए।

❖ पुलिसिंग जीवन के अब तक के सफर में सबसे चुनौतीपूर्ण केश कौन सा है, जो कि आपके लिए यादगार बन गया हो?

अमित जी, पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं पढ़ता था तो हमेशा मन में लालसा रहती थी की वर्दी पहनकर अपने देश की सेवा, राज्य की सेवा, समाज की सेवा करूं और संयोग से मुझे पुलिस की नौकरी मिल गयी। पुलिस की नौकरी में मैं पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अपना योगदान दिया एवं पुनः सर्विस का पहला अध्याय लखीसराय जिला से प्रारंभ किया। जिस समय मैंने लखीसराय जिला ज्वाइन किया था उस वक्त लखीसराय अपराधग्रस्त जिला माना जाता था। जब ट्रेनिंग सेंटर में मैं इस जिले में आया और यहां पर कार्य करके जो अनुभव हुआ, वह पूरा जीवन हमारे काम आया तथा जब भी यह जिला याद आता है तो लगता है कि वह हमारा विद्यालय रहा है और इसी नाते लखीसराय जिला को अपना जिला के नजर से मैं देखता हूं। चूकि लखीसराय हमलोगों का प्रशिक्षण स्थल भी था और प्रशिक्षण के दरम्यान बहुत सारी घटना को सिखने की व्यू से किये भी और कार्यवाई करते हुए देखे भी। वहां के कई काण्ड हमलोगों के लिए यादगार रहा है। एक घटना पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि जब मेरे प्रशिक्षण का करीब एक-डेढ़ महीना ही हुआ था, इस दरम्यान एक गिरोह का गैंग पहाड़ के किनारे रहता था और हमलोगों को वहां पर एक पुराने एएसआई के साथ ड्यूटी पर लगाया गया था। उसी दरम्यान अपराधी घटना घटने लगी। हमलोगों ने उस गैंग का पीछा किया, फायरिंग-वायरिंग भी हुई। कुछ एकाध अपराधकर्मी पुलिस की गोली से मारे भी गये थे, फिर बाद में और भी लोग पकड़े गये। इस कार्यवाई पर वहां की जनता खुश थी और पुलिस को उनका प्रोत्साहन भी मिला, जो आज तक मुझे याद आते रहता है। लखीसराय की ही एक घटना थी डकैती की। डकैती होने के बाद एस.पी. साहब ने तुरंत मिटिंग बुलायी और कहा कि मुझे आज रात में ही रिजल्ट चाहिए। हमलोग फिल्ड में निकले। कुछ समय मात्र लगभग दो या तीन घंटे के अंदर डकैती के सारे अभियुक्त पकड़े गये। अपराधकर्मी घटना कारित करके सिनेमा देखने चला गया था, उसे सिनेमा घर से ही पकड़ लिया गया और जो डकैती का सारा सामान था, वह भी बरामद हो गया। यह देखकर एस.पी. साहब को अच्छा लगा। चूकि हमलोग अभी ट्रेनिंग में ही थे तो इसपर उनका प्रोत्साहन भी हमलोगों को बहुत अच्छा मिला। इस तरह से हमलोगों का मनोबल वहां की जनता के तरफ से भी और विभागीय प्रशासन के तरफ से भी मनोबल बढ़ाया जाता था और हमलोग ट्रेनिंग अच्छे से प्राप्त किये। ट्रेनिंग समाप्त होने पर स्वतंत्र रूप से जेएसआई और थानाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बहुत सारा अनुभव वहां प्राप्त किया। बहुत सारे काण्ड में अच्छे तरह से कार्यवाई भी किया। मैं शेखपुरा जिला में भी काम किया, बरबिघा थाना में भी काम किया। बक्सर जिला में भी रहा और बक्सर जिला में भी कुछ काम ऐसा रहा जो पुलिस के रूप में उपलब्धि भरा अपने आप में रहा है, साथ ही कैमूर जिले के चेनारी में भी काम किया है। इसके साथ पटना जिला में भी मैंने काम किया है। यहां की पुलिसिंग कुछ अलग तरह की पुलिसिंग है। पटना जिला के पुलिसिंग में काफी मन लगा और लगातार दूर-देहात के थानों में भी कार्य किया, जैसे- पटना जिला अंतर्गत घोषवरी थाना, सिगौड़ी थाना, बिक्रम थाना, नौबतपुर थाना, रामकृष्णा नगर थाना, बिहटा थाना सहित अन्य थानों में सफलतापूर्वक और पूरे मनोयोग से फ्री होकर काम किया। इसके लिए कई प्रशस्ती-पत्र भी मुझे मिला। कही कोई परेशानी नहीं हुई। हमे हमेशा वरीय पदाधिकारियों का सहयोग मिलता रहा है और निर्भीक होकर मैंने काम किया, जिससे पुलिस कार्य में सफलता भी पाया। तो इस तरह कई थानों को होते हुए सब इंस्पेक्टर में भी, इंस्पेक्टर रैंक में भी कार्य करते हुए आज मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हाजीपुर के पद पर कार्यरत्त हूं और मुझे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पद पर पहला अनुमंडल मिला है।

❖ आप पटना के रामकृष्णा नगर थाने में लंबे समय तक प्रभारी रहकर काम किया एवं अपने काम से लोकप्रियता भी हासिल की। किस तरह याद करते हैं रामकृष्णा नगर थाने को?

रामकृष्णा नगर थाना पटना जिला का थाना है और टाउन से सटे हुए थाना है। बाईपास से सटे हुए थाना है। रामकृष्णा नगर थाने में कुछ टाउन का भी अनुभव है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र का भी। दोनो तरह का मिश्रित वातावरण वहां देखने को मिलता है। जब मैं वहां ज्वाइन किया था, उस वक्त लूट और डकैती की घटना ज्यादा हो रही थी। समीक्षा करने के बाद अपराध ग्रस्त इलाके को चिन्हित करके लगातार चार-चार, पांच-पांच पेट्रोलिंग करना, रात-रात भर गस्ती करना, जो पूर्व के काण्ड का अपराधी था, चिन्हित करके धर-पकड़ कर गिरफ्तारी करके इस स्तर पर कार्यवाई किया कि बाद के दिनों में लूट और डकैती एकदम बंद हो गया। वही दूसरी ओर बाईपास उस टाइम में बन रहा था। हमलोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती थी की बाईपास चलते रहना है। उस वक्त सिंगल लेन था और गाड़ियां सिंगल लेन में ही चलती थी तथा गांधी सेतु का जो पुल है वह हमेशा जाम के कगार पर रहता था। अपराध पर नियंत्रण रखते हुए और रात-दिन हमलोग ट्रैफिक में भी लगे रहते थे कि कभी कोई जाम की समस्या ना हो। उस वक्त वाहन दुर्घटना बहुत अधिक संख्या में होता था, इसे देखते हुए उस परिस्थिति में मैने

अच्छे रूप से काम किया। साथ ही रामकृष्णा नगर थाना के अगल-बगल चौहद्दी के जो थाने थे-अगमकुआँ थाना, पत्रकार नगर थाना, कंकड़बाग थाना, जक्कनपुर थाना, बाईपास थाना एवं गोपालपुर थाना मिलकर एक टीम की तरह काम करते थे। किसी भी थाना में कोई क्राइम हुआ तो इसकी सूचना मिल जाती थी और फिर हमलोग एकजुट होकर धड़-पकड़ का काम शुरू करते थे। कही कोई लगता ही नहीं था कि हमलोग पुलिसिंग का कार्य कर रहे हैं, मानो एकदम घर का काम कर रहे है। ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि नौकरी कर रहे हैं। हंसते-खेलते घर के माहौल की तरह वहां पर मैने कार्य किया। वहां पर जो भी समय बीता, बहुत ही अच्छे तरह से सफलतापूर्वक बीता। वही मेरा आवास थाने से महज एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही था। किन्तु काम का प्रेशर अत्यधिक होने की वजह से 15-20 दिन घर जाना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि वहां पर हमारे साथ कार्य कर रहे सभी पुलिसकर्मी के साथ परिवारिक माहौल में काम किया।

❖ **शहर की ट्रैफिक समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है?**

यहाँ पर दो तरह की ट्रैफिक की समस्या है-एक बाजार का और दूसरा हाइवे का। बड़ी गाड़ियों के आने-जाने के लिए हाइवे का एक न्यू गंडक पुल है और दूसरा गंगा ब्रीज। गंगा ब्रीज पर अभी सिंगल लाईन है तथा गंडक पुल भी सिंगल ही है। गंडक पुल से सोनपुर के तरफ जो रास्ता जाता है, वह भी सिंगल ही रास्ता है। अगर थोड़ा सा भी गाड़ी ओवर टेक हुआ या कोई एक गाड़ी भी रास्ता में खराब हो गया तो जब तक गाड़ी हटती नहीं है, तब तक लाईन चालू नहीं होता है तथा दोनो लाईन बंद। गंगा ब्रिज का भी वही हाल है। यह ब्रिज लगभग 5-6 किलोमीटर लंबा है और रास्ते में एक भी गाड़ी खराब हो गई तो यातायात बाधित हो जाता है। फिर क्रेन जायेगा और उस खराब गाड़ी को लायेगा। इस बीच 7-8 किलोमीटर लंबा गाड़ियों का लाइन लग जाता है। फिर दिनभर का हमलोगों का वह प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन फिर भी हमलोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक अच्छे तरह से चलते रहे और चल भी रहा है। मेहनत करना पड़ता है और मेरी टीम इसमें लगी रहती है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलते रहता है। दूसरा बाजार के अंदर की यातायात समस्या है। चूकि पुराना रोड है, संकीर्ण है। उसी में सभी लोगों का दुकान भी, ठेला भी रोड पर ही लगाते हैं, जगह-जगह पर कट वगैरह है। वही आज कल तीन चक्का ई-रिक्सा भी चलने लगा है। इस तरह से कई परिस्थितियां है, जो सड़क को जाम करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन उन लोगों को भी व्यवस्थित रखते हुए ट्रैफिक का एक अलग विभाग है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है।

❖ **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सदर, हाजीपुर के नाते आम जनता को आपका क्या संदेश होगा?**

मैं आपकी पत्रिका केवल सच के माध्यम से आमलोगों से अपील करता हूं कि पुलिस को अपना समझे। हम उन्ही के हैं, उन्ही के लिए हैं और हमेशा उनके लिए काम करने के लिए हैं। मेरा एक-एक काम आम जनों के लिए ही है, वो हमें अपना माने। घटना-दुर्घटना जो भी घटती है, तत्परता के साथ जल्द से जल्द हमलोगों को सूचित करे और जो भी अपराधितत्व है, कही न कही गांव-देहात, टाउन, टोला-मोहल्ला जहां भी रहते हैं, वह लोगों के बीच में ही रहते हैं। अगर आम जन चाह ले की अपराधी को समाप्त करा देना है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, पब्लिक सबको देखता है। भय से, डर से, किसी भी कारणवश पुलिस तक उनकी सूचना पहुंचने में विलंब होती है और इसी का लाभ लेकर अपराधी अपराध करने में बरकरार रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपराधी को अपराध करते देखकर पुलिस को सूचना दे दे तो पुलिस उस पर कार्यवाई करने के लिए पहुंच जायेगी। हो सकता है उस समय अपराधी भागने में कामयाब हो जाये, लेकिन मन में उसका भय बना रहेगा कि हम बच नहीं पायेंगे। तो मैं आपकी पत्रिका के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अगल-बगल में अपने आस-पास के वातावरण में जहां कही भी अपराध होते या अपराधी को घूमते-टहलते या अपराध पनपते देखे, तो पुलिस को इसकी अविलंब सूचना दें और पुलिस से काम लें और कार्यवाई करवाये।

विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर बच्चों ने प्रस्तुत किया रंगारंग कार्यक्रम

● **त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

बीते दिनों ब्राईट स्टार किडजी स्कूल, भागवतनगर, पटना में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों द्वारा ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' ''व्हाट्स एप के कारण माता-पिता द्वारा बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है'' इत्यादि पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बच्चों द्वारा गीत-संगीत के तहत मईया यशोदा आदि गीतों पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जे.जे. कॉलेज, गया, के प्राचार्य, माननीय डॉ. कुमार राजीव रंजन अपनी विशिष्ट गरिमा के साथ उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथिगण के रूप में सर्वश्री प्रो. गजेन्द्र प्रसाद गड्कर, रविन्द्र कुमार एवं चन्द्रमणि कुमार भी मंच पर उपस्थित थे। विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती शुभा ने छात्रों को संबोधित करते हुये कहा कि बच्चों के सर्वांगिण विकास के लिये पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समावेश किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कार्यक्रम में आये हुये अभिभावकों को यह अवगत कराया गया कि बच्चों से उनका बचपना कभी नहीं छीनना चाहिये, बच्चे तो नटखट होते ही है, इसी प्रकार से वे कुछ सीखते हैं और उनके मौलिक जीवन का विकास होता है। ●

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं में भारी गड़बड़ी

● **बिनय भूषण झा**

मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओ में से प्रमुख दो तीन योजनाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है जिसमे भारी गड़बड़ी एवं घोटाले के शिवा कुछ नही दिखता ये नजारा वैशाली जिले के अनगिनत आँचल अंतर्गत अनेको पंचायतों का है जमीनी हकीकत। हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना इस निश्चय योजना का उद्देश्य बिहार के हर नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था जो बिहार के लगभग 8500 गांव एवं नगर तक पहुंचाना एक मात्र बिहार सरकार का लक्ष्य था, मगर वैशाली जिले के अंतर्गत अनेको अँचल और पंचायतों में भारी गड़बड़ी एवं नकली समान का उपयोग एवं मोटर का उपयोग बिना स्टेपलाईजर का उपयोग होता दिखता है जिसमे कुछ छेत्र में तो ये योजना कही दिखता ही नही जिसमे 'मुख्यत: सहदेई बुजुर्ग (अँचल) के विभिन्न पंचायतों में तो कही नल है और जल गायब, कही जल ऐसे ही बेकार बहता हुआ दिखता है बाजितपुर चकस्तूरी, फतेहपुर बुजुर्ग, चकजमाल, डुमरी, तोई, मजरोहि, बिकर्मपुर, रामपुर, पोहियार बुजुर्ग, दुव्हा, शेकोपुर, सहरिया, सलहा मुख्यत: है जहाँ अत्यंत दु:खद अहसास कराता है जमीनी हकीकत !

देसरी आँचल के - नायगांव ,धरमपुर, किचनी, माधोल, ममरेजपुर, खोक्सा , लखनपुर, देसरी, खेरका मुखयत: है और देसरी अंतर्गत कुछ एक पंचायत में जातियता दंश भी झेल रहा है ग्रमीणों का कहना है कि पंचायत मुखिया दलित है तो बाबू साहब के इलाके में ये योजना आया ही नही है ये ग्रामीणों का आरोप है जो दु:खद है! महनार अंतर्गत बसुदेवपुर, फटिकवार, लावपुर, हसनपुर, महनार नगर पंच.एवं अनेको जगह दयनीय स्थिति है जो जमीनी हकीकत है। जन्दाहा ब्लॉक अंतर्गत देढ़पुरा, चकममडिद, रामपुर, लोमा, कतकलोनी, सर्वोदय मैदान स्थित कुछ एक मुहल्लों का स्थिति तो नारकीयय जैसा हो गया है एवं जिसके द्वारा भी कार्य किया गया वो गड्ढा खोदकर जैसे तैसे कर काम को अंजाम दिया गया जो वहा के रहने वालों के लिये दिक्कत का कारण बन चुका है ये वहां के जनता का वक्तव्य है! बिदुपुर ब्लॉक के अन्तर्गत खलौत, रंदहा, कुसियारी, रामदौल, फुलपुरा, चेचर, चांदपूरा, कुछेक ऐसे पंचायत में ये योजना तो कही दिखता ही नही जिससे गांव वासी नाराज है और सरकार को कोसते है और इस कार्यो की देख रेख की या कार्य प्रणाली की व्यवस्था जिस किसी के द्वारा करवाई गई हो वो शिर्फ एक फण्ड का दुरूपयोगता को ही दर्शाता है अस्पस्ट तौर पर यह योजनाओ में भारी गड़बड़ी की आशंका हुई मालूम पड़ती है, जो जांच का बिषय है। गली नाली योजना इस योजना में तो खुलेआम धांधली हुई है सहदेई अँचल अंतर्गत अनेको पंचायत में नाली का आधा अधूरा कार्यो का निष्पादन कर सरकारी फण्ड का दुरुपयोग के शिवा कुछ नही मालूम पड़ता ये नजारा वैशाली जिले के अनेको छेत्र की समस्या है जिसे मैं गांव गांव जाकर यह जनता के द्वारा बताया गया है जो वास्तविकता मालूम पड़ती है जिसमे बहुत गड़बड़िया सामने आई है जो ग्रामीणों के दुख का कारण है जो जाँच का विषय मालूम पड़ता है।

★ **मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना क्या है? :-**

- ☞ आर्थिक हल युवाओ का बल।
- ☞ आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार।
- ☞ हर घर बिजली लगातार।
- ☞ मुख्यमंत्री पेयजल योजना, हर घर नल-जल योजना।
- ☞ गली-नाली योजना, घर-घर तक पक्की नाली योजना।
- ☞ शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना।
- ☞ अवसर बढ़े, आगे पढ़ें। कुशल युवा कार्यक्रम, शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण योजना।

★ **शौचालय निर्माण घर का सम्मान:-** निश्चय योजना लागू करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोहिया स्वछता अभियान के तहत गांव में इस योजना के अंतर्गत गांव के विकास में एक नई पहचान देने की बात किया गया था सरकार के द्वारा इस योजना को 2008 में स्वीकृति दी गयी थी इस योजना के तहत एपीएल/बीपीएल परिवार को बिना भेदभाव के सभी को 12000 हजार रूपए की सहायतार्थ राशि लाभुक के खाते में देने की बात है जिसको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य मिशन के द्वारा निर्गत करने का प्रवधान है, लेकिन वैशाली जिले के किसी भी ब्लॉक पंचायत में इस योजनाओ का असर दिखता ही नही जो मुख्यत: जाँच का विषय है। जनता की जुबानी अफसरों एवं नेताओ द्वारा मिलकर अमीर गरीब एपीएल, बीपीएल को अपने हिसाब से वर्गीकरण कर इस योजना का हिसाब किताब लगाकर इस योजना पर वर्तमान समय मे भी ग्रहण लगाए हुए हैं और इसे जुड़े सरकारी फण्ड का दुरुपयोग खुलेआम दुरुपयोग कर रहे है सैकड़ो लोगो ने ये जानकारी दिया है और इस योजना में ये बात भी सामने आई है कि शौचालय योजना का लाभ लेने वाले को दो से तीन हजार रुपये भी देने होते है जिस कारण ये योजना गरीबो को ना के बराबर ही मिला है। जो सरकारी अफसरशाही रवैये से बेहद परेशान है। अत: मैं खुद गांव गांव जाकर यह अस्पष्ट हो गया कि इस योजना में वाकई भारी गरबरी मालूम पड़ती है इसलिए जनता द्वारा सरकारी तन्त्र व्यवस्था से पूछना चाहता हूं की सरकार की कोई भी योजना खास कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है उसे पूरा कैसे करना है या कितना पूरा हुआ इन पहलुओं पर देख रेख या निष्पादन का सर्वेक्षण क्यो नही करवाया जाता है, जिसमे सही कार्यों की रूपरेखा का वितीय समीक्षा हो जिससे इसकी दुरूपयोगता पर अंकुश लगाया जा सके और सरकारी फण्ड का सदुपयोग हो सके और डायरेक्ट जनता को इसका लाभ मिल सके।

★ **अंत में आम जनमानस द्वारा निवेदन :-** सरकारी तन्त्र व्यवस्था बिहार सरकार से अनुरोध है कि मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र में जो भी योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्गत होता है चाहे वो कोई भी योजना हो उसकी कार्यप्रणाली एवं उससे जुड़े कार्यो की जाँच की जाय जिससे घोटाले की पोल खुल सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके इसकी जाँच होनी अत्यंत आवस्यक है इसलिए जाँच हेतु अग्रसित करने की कृपा की जाये।●

कोरोना के कहर से लड़ने के लिए मुस्तैद है स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन

● **अविनाश कुमार**

देश सहित पूरी दुनियां में चर्चा का मुख्य खबर बना कोरोना वायरस को लेकर हर कोई काफी गंभीर और चिंतित है। इसके मद्देनजर बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे किसी भी संक्रामक बीमारी की संदिग्ध मामलों की लगातार निगरानी की जा सके। वही इसे लेकर जिलाधिकारी एस०के०एम०सी०एच पहुंचे और कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। उक्त मौके पर अस्पताल अधीक्षक सुनील शाही भी उपस्थित थे और उन्होंने जिलाधिकारी को इस संबंध में की गई तैयारियो से अवगत कराया। एस०के०एम०सी०एच में उक्त खतरनाक बीमारी (कोरोना वायरस से प्रभावित) को देखते हुए 10 बेड का आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उक्त वार्ड में ऐसे संधिग्ध मरीजों के देख-रेख एवं रख-रखाव के लिये सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

गौरतलब हो कि आजकल सोसल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक अस्पताल के बेड पर कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यह मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की यह ताजी तस्वीर है। किन्तु सच्चाई यह है कि यह तस्वीर लगभग दो साल पुरानी है। हालांकि इस खबर को एक दैनिक समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापा और न्यूज 24 ने इस खबर को चलाया भी था। ध्यान योग्य बातें यह है कि आज अस्पताल में काफी बदलाव आ चुका है, हर दरवाजे पर पर्दा लग चुका है। साथ ही बेडसीट भी हर बेड पर लगा हुआ है। उस वक्त टाइल्स नया था, आज पुराना पड़ चुका है। इसके मद्देनजर किसी भी तस्वीर को शेयर करने के पहले उसकी सत्यता जांच लेना अवाश्यक है।

बताते चले कि बीते वर्ष गर्मियों में

मस्तिष्क ज्वर (ए०ई०एस/जापानी इंसेफ्लाइटिस/दिमागी बुखार/चमकी बुखार) से कई बच्चों की जाने चली गयी थी और कुव्यवस्था को लेकर सरकार की काफी फजीहत भी हुई थी। अब चूकि पुन: गर्मी का मौसम आने वाला है तो इस प्रकार की चिंताएं बनना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए लाजमी है। इसी को लेकर 10 फरवरी 2020 से जिले के प्रभावित प्रखंडों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जिला जनसंपर्क कार्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा मस्तिष्क ज्वर(एईएस/जापानी इंसेफ्लाइटिस/दिमागी बुखार/चमकी बुखार) के लक्षण उससे बचाव के तरीकों के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस संबंध में जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि 10 फरवरी से जिले के 5 प्रखंड, जो मुख्य रूप से प्रभावित रहे है में छ: नुक्कड़ नाटक के टीमों द्वारा सघन प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिले के कांटी, मुशहरी मोतीपुर, बोचहां, मीनापुर प्रखंड मुख्य रूप से एईएस से प्रभावित थे। इन्हीं प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों के 291 चिन्हित स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चमकी बुखार के लक्षण, उससे बचाव के उपाय एवं सावधानियां, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस की सेवा हेतु टॉल फ्री नंबर, आदि की जानकारी लोगों को दी जाएगी।

सनद् रहे कि इस वक्त कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इस बाबत एसकेएमसीएच अस्पताल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभावित खतरे से निपटने हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगो से अपील करते हुए कहा है कि यदि चीन से आने वाले व्यक्ति की तबियत खराब हो या उनमें प्रारंभिक लक्षण दृष्टिगोचर होते हों तो इसकी तत्काल सूचना जिला प्रशासन को दी जायें। उन्होंने सिविल सर्जन को भी निर्देश दिया है कि तत्काल सरकारी अस्पतालों में ऐसे संदिग्ध मरीजों की देख-रेख एवं रख-रखाव से संबंधित आवश्यक व्यवस्था सभी अस्पतालों में करना सुनिश्चित करें। इधर सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड़ में है। इस संबंध में सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। ●

पुलिस की मुस्तैदी से पकड़ा गया हथियार तस्कर

● अविनाश कुमार

भारतीय पुलिस सेवा बिहार कैडर के तेज-तर्रार पुलिस पदाधिकारी एस. एस.पी. मुजफ्फरपुर जयंतकान्त बीते माह अपने जिले का प्रभार संभालते ही अपराधियों के लिए कहर बनकर काम कर रहे हैं, मसलन अपराधियों में इनका भय देखा जा सकता है। यही कारण है कि लगातार इनकी कार्यवाई से एक तरफ शराब का खेप पकड़ा जा रहा है तो दूसरी ओर हथियारों का जाखीरा बरामद किया गया। वही जिले में एक खबर प्रकाश में आया कि पुजारी के वेश में महिला को साथ लेकर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी एवं वैशाली जिले में कारतूस का तस्कर जिला पुलिस एवं एसटीएफ के नेतृत्व में पकड़ा गया। गौरतलब हो कि बस स्टैंड के पास 500 कारतूस व शराब के साथ पटना एसटीएफ के हत्थे चढ़े आर्म्स तस्करों को बिहार के कई जिलों में नेटवर्क फैला है। पुलिस को गिरफ्तार तस्करो से पूछताछ में उक्त कारतूस मेरठ से लौट जाने की जानकारी मिली है। इसे कई जिलों में खपाना था, पुजारी के वेश में महिलाओं को साथ लेकर कारतूस की सप्लाई की जाती थी। गिरफ्तार तस्करों के मोबाइल से कई नामचीन लोगों का नंबर मिला है। उक्त कार्रवाई को लेकर एसएसपी जयंतकांत ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार तस्कर अपनी वेशभूषा से लोगों व पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आर्म्स की तस्करी करते थे। इसे मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी जिले के अपराधियों को सप्लाई करते थे। वही इस तस्करी में संलिप्त गिरफ्तार महिला भी आर्म्स व कारतूस की तस्करी में पकड़ी गई है। इनके पास से पुलिस को 500 कारतूस, बाइक, 18 हजार रूपये, 20 बोतल शराब मिला है। ध्यान रहे कि इस गिरोह ने पहले भी दो खेप कारतूस पहुंचायी है और इनका एक संगठित गिरोह है। बेगूसराय जिले के मसूरचक थानाक्षेत्र के समसा गांव निवासी रवीना खातून कारतूस की खेप लेकर यहां पहुंची। वही मोतिहारी के मधुवन थानाक्षेत्र के वलि आलम व ठाकुरबाड़ी निवासी मो० इरशाद इसे रिसिव करने पहुंचे थे। ज्ञात हो कि सरैया थानाक्षेत्र के गोपीधनवत निवासी रवि पाण्डेय पुजारी के वेश में कारतूस को वैशाली पहुंचाता था।

बताते चले कि वर्ष 2018 में जीआरपी ने और बीते वर्ष 2019 में फकुली पुलिस ने कारतूस की बड़ी खेप के साथ तस्करो को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार जीआरपी व फकुली से पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरफ्तार आर्म्स तस्कर आपस में रिश्तेदार बताये जा रहे हैं। दोनो के साथ बैरिया से गिरफ्तार तस्करो का भी आपस में संलिप्तता होने की पुलिस को आशंका है। पुलिस तीनो मामले की एक साथ जांच करेगी। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि तीनो मामले की संयुक्त रूप से जांच की जा रही है, साथ ही जांच में संलिप्तता मिलने पर दोनो घटना में जेल जा चुके तस्करों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा सकती है। वही बीते 2019 में फकुली चौक के समीप से पुलिस ने तीन शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तस्करों में आशिक अंसारी, गायघाट और शमशेर, मुशहरी का रहने वाला है जबकि अकील दरभंगा का है। इनके पास से 7.65 एमएम पिस्टल की 1300, 30 बोर की 100, 315 बोर की 180 और 12 बोर की 30 गोलियां मिली थी। दूसरी तरफ झपहां इलाके से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब के दो बड़े धंधेबाज को गिरफ्तार किया। दोनो ही शराब की सूचना देने वाले लोगों का अपहरण कर लेते थे। शराब बरामदगी के कई मामलो में गिरफ्तार अहियापुर थाना के शिवराहां निवासी सुनील कुमार, मीनापुर थाना के शाहपुर निवासी समीर कुमार की इसमें संलिप्तता मिली है तथा तलाशी के दौरान इनके पास से पुलिस को चरस व दो मोबाइल मिला है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में बिना नंबर वाले वाहनों की जांच की जा रही थी, इसी दौरान दोनो वहां पहुंचे। पुलिस को देखकर ये दोनो वहां से भागने का प्रयास किये किन्तु पुलिस ने पीछा करके दोनो को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पॉलीथीन में लपेटा हुआ डेढ़ किलो चरस के साथ दो मोबाइल भी मिला है। समीर कुमार पर अहियारपुर थाना में 17 जनवरी के शराब बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। ●

जिले की हर समस्या दूर करने का प्रयास है जारी : डी.एम.

बिहार के बांका जिला के रहने वाले 2008 बैच के कर्तव्यनिष्ठ आई.ए.एस. आलोक रंजन घोष अपने कर्तव्यपरायणता एवं मृदुभाषी के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि अपने कार्य के प्रारंभिक समय से आज तक अपने सहकर्मियों एवं जनता के चहिते बने हुए हैं। ज्ञात हो कि आलोक रंजन यूपीएससी परीक्षा में 10वाँ स्थान पाकर बिहार के बांका का तो मान बढ़ाया ही तथा अपने भूतपूर्व सैनिक पिता का भी सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं की। विदित हो कि सर्वप्रथम सिवान में सहायक समाहर्ता के पद पर अपने कुशल कार्य का परिचय देते हुए आज बिहार की मिनी राजधानी कहे जाने वाला मुजफ्फरपुर जिला के यह जिलाधिकारी हैं। चूकि मुजफ्फरपुर जिला, बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है तथा राजधानी से सटा हुआ जिला भी है, तो इस बाबत इनको इनके कार्य में जिम्मेदारियां भी ज्यादा रहती है। वही पिछले वर्ष चमकी बुखार से मासूम बच्चों के मौत का मातम देखा गया, उसे भुलां पाना इतना आसान नहीं। अब सवाल यह है कि इसके लिए दुरूस्त व्यवस्था के साथ जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष किस तरह की योजना बनाकर जिले में कार्य करते हैं? इन तमाम सवालों को लेकर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर **आलोक रंजन घोष** का साक्षात्कार पत्रिका के मुजफ्फरपुर ब्यूरो **अविनाश कुमार** द्वारा किया गया। प्रस्तुत है इसके महत्वपूर्ण अंश :-

★ अपने जीवन के बारे में बताएँ?

मेरा जन्म बाँका के चान्दन प्रखंड में 03 दिसम्बर 1980 में हुआ एवं तत्पश्चात् मैंने प्रारम्भिक शिक्षा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब) दसवीं कक्षा चेन्नई (तमिलनाडू) एवं 12वीं कक्षा जलपाईगुड़ी से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् ICAR की परीक्षा पास कर मद्रास वेटनरी कॉलेज, चेन्नई से पशु चिकित्सा में स्नातक की परीक्षा पास की। इसके पश्चात् मैंने Symbiosis College, Pune (Maharastra) से MBA की डिग्री प्राप्त की। SBI Life Company में Management Trainee के रूप में वर्धमान (पश्चिम बंगाल) में लगभग डेढ़ वर्ष कार्य किया। वर्ष 2008 में Civil Service की तैयारी प्रारम्भ की एवं दूसरे प्रयास में UPSC परीक्षा में 10 वाँ स्थान प्राप्त किया। उसी वर्ष IAS में चयनित होने से पूर्व भारतीय वन सेवा प्रवेश परीक्षा में भी 23 वाँ स्थान प्राप्त किया। मेरे पिताजी भूतपूर्व वायु सैनिक हैं एवं माताजी गृहणी है। बड़े भईया एवं भाभी वर्तमान में चेन्नई में कार्यरत है। मेरी अर्धांगिनी भारतीय स्टेट बैंक, पटना में मुख्य प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हैं।

★ बाँका जिले से आई.ए.एस. की सफर में क्या-क्या कठिनाईयाँ हुई?

सेवा में प्रवेश पाने के पूर्व मैंने जीवन में काफी संघर्ष किया और आनेवाली हर चुनौती ने मुझे दिन प्रतिदिन सशक्त बनाया।

★ आप कहाँ-कहाँ पदस्थापित रहे है?

बिहार में सर्वप्रथम मैंने सहायक समाहर्त्ता के रूप में सिवान जिले में योगदान दिया। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में मोतिहारी सदर और राजगीर अनुमंडल में पदस्थापित रहा। निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में एक वर्ष तक कार्य किया। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के रूप में मेरी तीसरी पोस्टिंग है, इसके पूर्व जिलाधिकारी, अरवल एवं जहानाबाद में रह चुके हैं।

★ इस समय चमकी बुखार की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा क्या उपाय की गई है?

यूँ तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप लगभग 25 वर्षों से है। परन्तु विगत वर्ष अप्रयाशित रूप से लगभग 150 बच्चों की मृत्यु चमकी बुखार से हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नवम्बर, 2019 से ही चमकी बुखार से निपटने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है। गृह भेंट, जागरूकता रैली, आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था, कलाजत्था, जागरूकता रथ, एफ.एम. चैनल, जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद मीडिया के साथ कार्यशाला, समन्वय समिति की बैठक आदि आरम्भ किये जा चुके हैं। आशा है चमकी बुखार को परास्त करने में सफल होंगे।

★ बाढ़ से निपटने हेतु जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्य किये जा रहे हैं?

बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, जिसपर मनुष्य का कोई नियंत्रण नही है। परन्तु मेरा मनना है कि आवश्यक तैयारी हो तो जानमाल की क्षति को अत्यंत न्यून किया जा सकता है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में बाँध बनाया जाना संभव नहीं है। हाँलाकि तटबंध के निर्माण के कारण बहुत हद तक बाढ़ से होनी वाली क्षति को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मोटर बोट, नाव राहत सामग्री, उच्च शरणस्थली को चिन्हितकर, बाढ़ पूर्व मानव संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना इत्यादि गतिविधियाँ की जानी है, जिससे क्षति को न्यून रखा जा सके।

★ कोरोना वायरस के लिए क्या उपाय है?

कोरोना वायरस का अबतक कोई भी Positive Case बिहार में नहीं पाया गया है। इससे निपटने हेतु मुजफ्फरपुर जिले में आवश्यक तैयारी की जा चुकी है। SKMCH मुजफ्फरपुर में Issolation, Medical Team, सभी तरह की दवाईयों की उपलब्धता, कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

★ आपको कई बार सम्मानित भी किए गए इसके बारे में जनता को कुछ बताना चाहेंगे?

मेरा मानना है कि कोई भी कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण ससमय की जाए तो सफलता की संभावनाएँ बढ़ जाती है। जिलाधिकारी के रूप में अप्रमंडल स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने टीम के लिए सम्मानित किया गया है, जिसका पूरा श्रेय टीम वर्क को देना चाहेंगे। "A leader is as good as his team" अत: टीम वर्क यदि अच्छा हो तो सफलताएँ कदम चुमती ही है।

★ क्या ये सच है कि जनता दरबार में सिर्फ तारीख मिली है कार्रवाई कुछ नहीं होती?

मैं इस कथन से एकदम सहमत नहीं हूँ। जनता के साथ साक्षात्कार के दौरान कई समस्याओं का समाधान तत्क्षण किया जाता है। कुछ समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी को जाँच करने हेतु एवं कुछ समस्याओं को तुरंत हल करना संभव नहीं हो पाता है एवं परिवादी को उचित माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जिला प्रशासन का यह प्रयास होता है कि किसी परिवादी को दूसरी बार साक्षात्कार करने का कष्ट नहीं करना पड़े, जिसमें हम सफल भी होते हैं और कुछ में असफल।

★ मुजफ्फरपुर जिले की क्या खास बात है जो प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न है?

हालांकि मुजफ्फरपुर कई कारणों से विख्यात है, परन्तु अगर विशिष्ट रूप से बात की जाए तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश एवं विदेश में विख्यात है। मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार की राजधानी भी कहा जाता है। मशहूर साहित्यकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी एवं स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जुब्बा सहनी की जन्मस्थली भी मुजफ्फरपुर ही है।

★ आपके पदग्रहण के बाद किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है?

मुजफ्फरपुर एक विकासशील जिला है, परंतु कई मायनों में अन्य जिलों की तुलना में विकास के मानकों में कहीं आगे है। मेरे पदभार ग्रहण करने के उपरान्त मैंने इस जिले को नित-प्रतिदिन नई चुनौतियों से जुझते देखा है, इसके बावजूद भी जिले के नागरिकों एवं पदाधिकारियों का हौसला देखते ही बनता है। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। नीति आयोग द्वारा यह जिला आकांक्षी जिला भी घोषित है। अत: चुनौतियां अनेक है साथ ही कई संभावनाएँ भी हैं।

★ क्या आप अपने पदाधिकारी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं?

समय के साथ प्रशासन एवं जन सामान्य के बीच की दूरियाँ घटी है। विगत दसकों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने असीम तरक्की की है, जिससे आम जनता की सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अपेक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र में अब भी कुशल कर्मियों एवं पदाधिकारियों का अभाव है, जिसे कम करने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। सीमित संसाधनों एवं बढ़ती अपेक्षाओं के बीच जिले के पदाधिकारी एवं कर्मी यथासंभव कर रहे हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि हर मानक पर प्रत्येक सरकारी कर्मी का खरा उतर पाना हर समय संभव नहीं होता है। पदाधिकारी एवं कर्मी अपने स्तर से यथासंभव प्रयास कर रहे हैं एवं मुझे अपनी टीम का नेतृत्व करने का गर्व भी है।

★ आप नकसलवाद एवं अपराध को किस प्रकार विकास का अवरोध मानते हैं?

मुजफ्फरपुर जिले में नक्सलवाद अब लगभग समाप्ति की ओर है। यदि देखा जाए तो विगत वर्षों में नक्सली गतिविधियाँ लगभग नगन्य रही है। निश्चित रूप से नक्सलवाद/अपराध में वृद्धि होने पर किसी भी प्राप्त में अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। पूंजी का निवेश करने से व्यवसायी भी हिचकते हैं। पुलिस कप्तान के नेतृत्व में पुलिस बल इस पर नकेल कस रही है एवं कई नामचिन अपराधियों को, शराब माफियाओं को, असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए सलाखों के पीछे डाला गया है। पुलिस गश्ती की संख्या बढ़ाई गयी है एवं विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

★ क्या यह सत्य है कि सरकारी लाभ दिये जाने के लिए मोटी रकम पदाधिकारियों/कर्मियों को देना अनिवार्य होता जा रहा है?

भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा जीरो टोलरेन्स नीति अपनायी गयी है। इस तरह जिले में भी इस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। दोषियों पदाधिकारी एवं कर्मी को बक्सा नहीं जाता है। यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो समय-समय पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है।

★ वर्तमान एवं पूर्व की सरकार में क्या अंतर महसूस करते हैं?

मैं अपना हर कार्य पूरी निष्ठा एवं इमानदारी के साथ करने का प्रयास करता हूँ, जिस कारण से सरकार के परिवर्तित हो कोई असर मेरी कार्यशैली पर नहीं पड़ता। सरकार कोई भी हो कार्य करने का अवसर हर समय उपलब्ध रहता है, आवश्यकता है तो सिर्फ दृढ़तापूर्वक आवश्यक कार्रवाई करने की।

★ मुख्यमंत्री के लाख दावे के बाद भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है?

भ्रष्टाचार पूर्णत: एक नैतिक विषय है। एक व्यक्ति विशेष को प्राप्त संस्कार का प्रतिफल है। मैं आपके कथन से सहमत नहीं हूँ। यदि भ्रष्टाचार कहीं है तो वैसे भ्रष्टाचारियों पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। किसी एक दृष्टांत को आधार बनाकर व्यापक अनुमान लगाना किसी प्रकार उचित नहीं है।

★ क्या आप अपने जिले के सभी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विकास कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों?

अपेक्षाओं और संभावनाओं का अंत नहीं। अगर अपेक्षाएँ है तो उन्हें पूर्ण करने हेतु संभावनाओं की कमी नहीं। साकारात्मक पहल एवं कालबद्ध प्रयास से सब संभव है।

★ जिले में बड़े पैमाने पर मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत है, जनता की, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं?

जब भी कोई योजना विशेष संबंधित गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त

होती है, तो संबंधित सक्षम पदाधिकारियों से जाँच कराते हुए कार्रवाई की जाती है।

☆ जिले में किस विभाग की लापरवाही की वजह से आपको गुस्सा आता है?

अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन नहीं करनेवाले किसी भी स्तर के पदाधिकारी एवं कर्मी मेरे क्षोभ का कारण बनते हैं। हालाँकि यह बात और है कि मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता है। मेरा प्रयास रहता है कि पदाधिकारी/कर्मी के व्यवहार में आवश्यक हृदय परिवर्तन हो एवं वे जनता को किसी प्रकार का शिकायत का मौका न दे। यदि वे ऐसा नहीं करते, जिसके फलस्वरूप जन सामान्य को कठिनाई का सामना करना पड़े तब अवश्य वे मेरे कोपभाजन का शिकार होते हैं।

☆ जिले में उद्योग की संभावनाएँ क्या है?

जैसा कि आप अवगत होंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया बेला इण्डस्ट्रीयल एरिया है, जहाँ विभिन्न उद्योग स्थापित हैं एवं कई लोगों को इससे रोजगार प्राप्त है। मुख्यत: मुजफ्फरपुर जिला कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कपास का उत्पादन न होने के बाद भी बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्त्र का बाजार है जहाँ निकटवर्ती जिलों से ही नहीं बल्कि निकटवर्ती देशों के भी बड़े व्यापारी एवं थोक बिक्रेता कपड़ा खरीदने आते हैं। शाही लीची की लुग्दी/प्रसंस्कृत लीची कन्सन्ट्रेट की एक बहुत बड़ी एवं एकमात्र फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, जिसे देश की नामी ग्रामी कम्पनियों को विक्रय किया जाता है।

☆ आपके द्वारा जिले में किये गया वैसा विकास जो आपके तबादला के बाद भी लोगों को आपके विषय में सोचने पर मजबूर कर दे बतायेंगे?

मेरा मानना है कि निष्ठा एवं ईमानदारी से किया गया छोटा एवं बड़ा कार्य लोगों को दिलों दिमाग में हर समय कैद हो जाता है। मेरी राय से इस संबंध में प्रशासन के कार्यों से लाभान्वित हो रहे लाभुकों से सही प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है।

☆ क्या जिले के विकास के लिए सरकार सही समय पर राशि उपलब्ध करा पाती है?

यह आँकड़ा विभाग विशेष पर निर्भर करता है। कई आवंटन समय से पहले, कई ससमय एवं कई आवंटन समय के उपरान्त भी प्राप्त होते हैं। वित्तीय नियमों के मद्देनजर अक्सर विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवंटन के व्ययगत होने की संभावना रहती है। CFMS प्रणाली के पूर्णरूपेण लागू हो जाने के कारण गिरावट आएगी ससमय आवंटन प्राप्त होगी जो विकास के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी।

☆ क्या जिले के विकास में राशि रोड़ा बन रही है या फिर विभागीय लापरवाही की वजह से जितना आप चाहते हैं, विकास नहीं हो पा रहा है?

सरकार द्वारा चलायी जा रही वर्तमान में सभी योजनाएँ तथा सात निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना इत्यादि अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं विकासोन्मुखी योजनाएँ है। अधिकांश योजनाओं हेतु पर्याप्त राशि मुहैया करा दी जा चुकी है एवं विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

☆ जिले के विकास में क्या राजनीति परेशान नहीं करती?

मेरा मानना है कि जन प्रतिनिधिगण लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत निर्वाचित होते हैं, जिनका सहयोग एवं सुझाव प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि लोक सेवा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। जनता की समस्या को निपटारा किया जा सके। मैंने सौभाग्यवश अपने कार्यकाल में किसी भी राजनीतिक दबाव का अनुभव नहीं किया है एवं सदैव उनसे सहयोग ही प्राप्त किया है, जिससे जिला के उत्तरोतर विकास का गतिशीलता का अनुभव किया है।

☆ गरीब आदमी की बात आपके अधिकारी नहीं सुनते ऐसा कहना है कि आपके जिलावासियों का, आप क्या कहना चाहेंगे?

लोक सेवक के रूप में किसी भी सरकारी कर्मी का मुख्य लक्ष्य होता है कि वे समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की हर संभव मदद करें एवं उन्हें सरकारी योजना का लाभ पहुँचाएँ। मैंने हर समय इस सिद्धांत का अनुसरण किया है और अपने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से ऐसी ही आशा रखता हूँ। व्यक्ति हर व्यक्ति इस विषय पर संवेदनशीलता अलग हो सकती है। परन्तु मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, परन्तु जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि कुछेक दृष्टान्त को आधार बनाकर सभी पर विस्तारित नहीं किया जा सकता।

☆ क्या विधि-व्यवस्था में जिले का पुलिस विभाग का रवैया से आप संतुष्ट है?

मुझे अपने कार्यकाल के दौरान दो अत्यंत ऊर्जावान वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनकी कार्यशैली बिल्कुल ही भिन्न है। दोनों के कार्यकाल के दौरान अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की गयी एवं नित-प्रतिदिन आनेवाली समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गयी। जिसके फलस्वरूप अपराध के ग्राफ में कमी आयी। हालाँकि शहरी इलाके के कुछ थाना क्षेत्र अहियापुर, ब्रह्मपुरा अधिक अपराध कारित किये जाने की बात मेरे संज्ञान में है। लापरवाह थानाध्यक्ष पर आवश्यक विधि-सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारी दोनों मिलकर भयमुक्त, अपराधमुक्त वातावरण बनाने में अग्रसर है। इसमें हम सफल भी होंगे।

☆ जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मुजफ्फरपुर जिला बिहार की सांस्कृतिक एवं व्यवसायिक राजधानी मानी जाती रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिले का विशिष्ट स्थान है। यह जिले कई प्रसिद्ध साहित्यकारों का जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही है। कई राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में जिले के साथ-साथ राज्य का मान बढ़ाया है। सही दिशा में यदि जिले के युवा कदम बढ़ाएँ साहित्यकार एवं शिक्षाविद् अपने ज्ञान का प्रसार करें एवं जन प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों के बीच आवश्यक समन्वय बना रहे तो निश्चित रूप से जिले का उतरोतर विकास संभव है। मेरी इच्छा है कि हम सब हाथ में हाथ लिए साथ-साथ चले और धर्म, जाति, सम्प्रदाय वर्ग की सीमाओं को मिटाते हुए मुजफ्फरपुर जले की एक अमिट गाथा गढ़ें।

सहयोग एवं संयोग का मिश्रण है यूपीएससी : आशुतोष

आईएएस की प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं यह हर युवाओ की सपना ,चाहत एवं उम्मीद की पंख को एक नई उड़ान देता हैं। हर साल लाखों परीक्षार्थी यूपीएससी के सपना संजोए परीक्षा में बैठते हैं लेकिन उसमें सिर्फ पॉइंट में ही सफल हो पाते हैं जिनका जोश जुनून एवं आत्मविश्वास लबरेज रहता हैं और वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से भटक नहीं पाते। यूपीएससी से सफल विद्यार्थियों का इतिहास बेहतर शानदार होता हैं जहाँ राजा भोज के साथ गंगू तेली एक साथ सफल हो नए कृतिमान स्थापित करते आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही युवाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए एक नहीं बल्कि तीन-तीन बार यूपीएससी में सफलता हासिल की एवं अंतिम चयन आईएएस के रूप में होने के उपरांत उन्होंने जॉइन किया हैं और वह शख्सियत हैं 2018 बैच बिहार कैडर यूपी के रायबरेली के मूलनिवासी आशुतोष द्विवेदी का। हमारे पत्रिका प्रतिनिधि **श्रीधर पाण्डेय** ने आईएएस **अशुतोष द्विवेदी** से खास मुलाकत कर उनसे सफलता की राज एवं इस मुकाम पर पहुंचने में होने वाली चुनौतियों को करीब से समझने का प्रयास किया,जिसके संपादित कुछ अंश :-

बातचीत के क्रम में आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि वह बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन शिक्षा का माहौल असाधारण था,जहाँ उन्होंने अपने पिता डॉ महावीर प्रसाद द्विवेदी के संघर्षों की गाथा को देखा, सुना एवं आत्मसात करते हुए इस मुकाम तक को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। किसान परिवार में जन्मे लेकिन खेती के लिए उतनी भूमि का न होना जो परिवार को खाना पीने की जरूरत के साथ उचित शिक्षा दिला दे, लेकिन शिक्षा प्रेमी होने के चलते सभी लोगो ने पिता जी पढ़ने के लिए प्रमोट किया। उनकी शादी महज 8 सालो में हो गई थी,मम्मी उतना पढ़ी लिखी नहीं थी इसके बावजूद भी उन्होंने पिताजी को पढ़ाई के लिए मदद करने को कहा। मेरे पिताजी पंत नगर से डिग्री लेने के पश्चात पशुधन प्रसार पदाधिकारी बने जिस समय मेरा बड़े भाई 12 की बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे। यह सच्चाई मेरी जिंदगी को परखने की कसौटी थी,और शिक्षा के प्रति परिवार के जागरूकता को दिखाता हैं जो विपरीत हालातो से उबर कर शिक्षा के मायने को समझा।

पिता जी के जानवरों का डॉक्टर होने की वजह से अधिकतर उनकी पोस्टिंग गावो में रहती थी एवं ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर ज्यादा होता रहता था ,जहाँ मुझे साइकिल से 12 किमी तक जाकर पढ़ाई करना पड़ता था,स्कूल पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन था,लेकिन खेलकूद एवं अन्य प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे। 10जी करने के उपरांत मैंने उचित शिक्षा के लिए कानपुर आ गया और आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कानपुर से ही किया। दो भाई बहनों में छोटे आशुतोष के बड़े भाई वेटेनरी अफसर हैं,भाभी टीचर,बहन नोएडा में टीचर तो बहनोई साइंटिस्ट हैं। पूरा परिवार शिक्षित होने के साथ साथ लोगो को शिक्षा के लिए प्रेरित करता आ रहा हैं। मेरी पत्नी प्रज्ञा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब के उपरांत समाजिक उद्यमता,मुम्बई से मास्टर कर रही हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कॉलेज से ही मारुति में जॉब मिला,इसरो त्रिवेंद्रम में काम किया, इसके बाद गेल जॉइन किया जहाँ मेरी पोस्टिंग आगरा में थी। मैं वहाँ एक बूढ़ी महिला से काफी प्रभावित हुआ जब उसके जमीन के नीचे से पाइप लाइन गुजर रही थी तो एक जनसुनवाई से बुलाकर उन्होंने मुझे अपने घर ले गया और बताया कि

मेरी तीन बेटियां हैं और पति नहीं हैं,मैं अपनी यह जमीन का टुकड़ा बेचकर ही इसकी शादी कर सकती हूं मगर पाइप लाइन हो जाने से इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी इसलिए मुझे इसका ज्यादा पैसा दिलवा दो। मैं उनको भरोसा दिलाया कि मां आपके जितना पैसा होते हैं उससे एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे नही हो पाता हैं तो कॉलक्टर साहब से बोलवा दो। तब मुझे पता चला कि कॉलक्टर के प्रति आज भी निचली पंक्ति में खड़े लोगो का भरोसा बरकरार है,इसलिए इसकी तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी यूपी बिहार के लोगो को यूपीएससी पर भरोसा ज्यादा रहता था,मेरे बड़े भाई पहली अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक गए थे तो उनका मार्गदर्शन मिला और मैं नौकरी के साथ साथ तैयारी में जुट गया। 2014 में मुझे सफलतर मिला लेकिन मैं जॉइन नहीं किया,2015 में आईपीएस मिला तो मैं गेल से रिजाइन किया,फिर 2017 में मुझे कस्टम मिला लेकिन 2018 में मुझे अंततः आईएएस मिला और मैं बिहार कैडर के रूप में फिलवक्त भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में ट्रेनिंग ले रहा हूँ।

यूपीएससी की तैयारी करने वालो छात्रों को सन्देश देते हुए युवा आईएएस अधिकारी आशुतोष ने बताया कि हर एटेम्पट नया अटेम्प्ट होता हैं,इसलिए अपनी लक्ष्य पर फोकस रखे,नियमित पढ़ाई कीजिये ,कम से कम 6 से 8 घण्टे पढ़ाई की जरूरत होती हैं,पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सफल न हो पाने की पीछे एक और वजह हैं कि वह आंसर लिखते कम हैं,इसलिए आंसर राइटिंग करे,अपनी आत्मविश्वास को बनाये रखे कोई भी व्यक्ति जो इस परीक्षा में सफल होता हैं वह श्योर नहीं रहता है कि उसका रिजल्ट जरूर आएगा। परीक्षा को कभी अपने ऊपर हावी न होने दे,जो भी कर रहे हैं मन लगाकर करे,दुसरो का काम अच्छा लगता हैं वह नहीं होनी चाहिए,बहुत लोग 12 वीं के बाद ही तैयारी में लग जाते हैं जबकि उन्हें बढ़िया से ग्रेजुएशन करना चाहिए,कोई भी काम जरूरत के हिसाब से करे। मेरी यह आखिरी यूपीएससी की परीक्षा अन्य यूपीएससी की परीक्षाओ से अच्छी नहीं थी क्योकि एग्जाम के 15 दिन पहले मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब थी,मैं विस्तर पर था और मेरी पत्नी प्रज्ञा मेरा नोट्स बोलबोलकर सुनाती थी,इस एग्जाम में सबसे कम सम्भावना थी लेकिन इसमें ही मैं आईएएस के लिए सफल हो पाया। यह एग्जाम संयोग एवं सहयोग का मिक्सचर हैं।

संक्रमण से सावधानी ही सुरक्षा व बचाव है : डॉ. रविकीर्ति

कहा जाता है कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो उसे आप डॉक्टर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही वह व्यक्ति होता है जो मानव शरीर के मानसिक या शारीरिक पीड़ा से जुझ रहे मरीज को अपने अनुभव से ठीक करने का प्रयास करता है तथा जीवन के अंतिम सांस को भी पुन: वापस लाकर व्यक्ति को जीवित कर देता है, तो वह धरती का भगवान ही हुआ ना! आज हम उसी चिकित्सा कौम से जुड़े एक सख्स डॉ० रविकीर्ति की बात कर रहे हैं, जो एक चिकित्सक के साथ-साथ राजधानी पटना स्थित फुलवारी में मरीजों के लिए अत्याधुनिक उपचारों से सुसज्जित बनाये गये एम्स के विभागीय एचओडी भी हैं। मसलन, देश सहित पूरी दुनियां के लिए बड़ा खतरा बना कोरोना वायरस का कहर जिस तरह फैल रहा है, उससे भय की आशंकाओं का बनना लाजमी है। ऐसे में इससे बचाव एवं सुरक्षा को लेकर तैयार रहना हर व्यक्ति के लिए जानकारीप्रद है। इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए पत्रिका प्रतिनिधि **पूनम जायसवाल** ने एम्स पटना (फुलवारी) के चिकित्सक व विभागीय एचओडी **डॉ० रविकीर्ति** से साक्षात्कार किया, प्रस्तुत है इसके प्रमुख अश :-

★ आपका नाम?

डॉ० रविकीर्ति

★ आप अपनी शिक्षा के बारे में बतायें?

मेरी स्कूली शिक्षा पटना में पूरी हुई। दसवीं और बारहवीं मैंने संत माइकल्स हाई स्कूल से पास की। 1996 में मेरा मेडिकल में चयन हुआ। एम.बी.बी.एस.की पढ़ाई मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के आर जी कार मेडिकल कॉलेज से की। तदुपरान्त मैं यूके चला गया जहाँ मैंने उच्चतर शिक्षा ग्रहण की। वहाँ मैंने एम.आर.सी.पी., सी. सी.टी. और एफ.आर.सी.पी. की डिग्रियाँ प्राप्त कीं। 2010 से 2013 तक मैं वहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विसेज में कन्सलटैंट था।

★ आप यू.के. और इंडिया की शिक्षा में क्या अंतर पाते हैं?

भारत में प्रतिस्पर्धा अधिक है। प्रतिभा की यहाँ कोई कमी नहीं है। परन्तु यूके में मैंने पाया कि वहाँ व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है।

★ आपने डॉक्टर बनने का विकल्प क्यों चुना, क्या यह आपकी ड्रीम जॉब है?

जी, बचपन से ही मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा थी। हालाँकि बीच-बीच में दूसरे विकल्प भी मन में आते थे। दसवीं पास करते-करते मेरी इच्छा दृढ़ हो गयी थी। ईश्वर की कृपा से मेरा चयन भी हो गया। मैं आज अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ।

★ अभी कोरोना वायरस चर्चा में है, इसके बारे में बताएं।

करोना वायरस का संक्रमण मनुष्य के साथ-साथ पशु-पक्षियों में भी पाया जाता है। मनुष्यों में यह सर्दी-जुकाम और बुखार करता है। कभी-कभी यह गंभीर रूप ले सकता है। चीन में अभी जो वायरस फैल रहा है वह काफी संक्रामक है। कई लोग मारे जा चुके हैं। भारत में केरल में अभी कुछ मामले पाये गये हैं। वे सभी चीन से लौटे हैं।

★ इससे बचने के लिए लोगों को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

हमें बचाव के लिये वही सावधानियाँ बरतनी चाहियें जो फ्लू के लिये बरतनी होती हैं। किसी को सर्दी-जुकाम हो तो उससे दूरी बनाये रखें। रुमाल आदि साझा न करें। हाथ धोने में परहेज न करें।

★ आप डॉक्टर के साथ-साथ एम्स, फुलवारी के एच.ओ.डी. होने के नाते क्या-क्या सुधार लाना चाहते हैं?

एम्स एक नया संस्थान है। अत: हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है एक ऐसी कार्य संस्कृति स्थापित करने का जिसमें मरीज का हित सर्वोपरि हो। न्यूनतम खर्च में कैसे विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा दी जा सके। इसी ओर हमारा सारा प्रयास केन्द्रित होना चाहिये। साथ ही, स्वास्थ्य सेवा एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें कभी भी मानवीय पहलुओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारे कार्य दल में हर स्तर पर इस बात का ध्यान रखा जाए।

★ आप अपने परिवार के बारे में बताएं?

मेरे माता-पिता अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं। मेरी मां, प्रो. जयश्री मिश्र मगध महिला कॉलेज, पटना में इतिहास की प्राध्यापक थीं और प्राचार्या भी रहीं। पिताजी, श्री राम नरेश शर्मा बिहार सरकार में अभियंता थे। मेरी बहन बेंगलुरु में एक सॉफटवेयर कंपनी में कार्यरत हैं। मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे मूल्य दिये। मेरे बचपन का काफी समय अपने ननिहाल में बीता। मेरे नाना प्रो. योगेन्द्र मिश्र ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे जिन्होंने वैशाली पर काफी शोध किया था।

★ आप केवल सच पत्रिका के माध्यम से मरीजों और अपने छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। अत: आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत सफाई के साथ-साथ अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखें। समाज और सरकार के परस्पर सहयोग से ही समुचित कचड़ा प्रबंधन संभव हो सकेगा। प्लास्टिक पर्यावरण का शत्रु है। इसके प्रयोग को हमें कम करना चाहिये और अंत में यही कहूँगा कि स्वस्थ शरीर के साथ-साथ स्वस्थ समाज भी आवश्यक है। अत: मेरी सबसे अपील है कि हम जात-पात के बंधन तोड़कर मिलजुल कर देश के विकास के लिये कार्य करें।

झारखण्ड मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार

मिथिलेश, चम्पई,जोबा, जगरनाथ, बन्ना व बादल ने ईश्वर की तो हाजी हुसैन ने अल्लाह के नाम की ली शपथ

संथाल से चार तो पलामू व दक्षिणी छोटानागपुर से एक एक विधयक को मिली जगह

● **अमित कुमार**

मैराथन दौड़ के 29 दिन बाद आखिर 28 जनवरी को झारखंड में हेमन्त मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए अपने विरोधियों से यह मौका छीन लिया जो झारखण्ड की भी तुलना महाराष्ट्र से करते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में काँग्रेस का पेंच फंसा होने का दावा करते फिर रहें थे। इस प्रकार से मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों वाले झारखण्ड मंत्रिमंडल में कुल 11 सदस्य हो गये।अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड के प्रमंडलों का ठीक उसी तरह ख्याल रखा जिस तरह से सम्पन्न चुनाव में मतदाताओं ने इनका तथा इनके सहयोगी दलों का ख्याल रखा है। 18 में से 13 सीटें झामुमो के झोली में डालने वाले संथाल परगना तथा 14 में से 13 सीटें झामुमो गठबंधन को देने वाले कोल्हान को 3-3 सीटों की हिस्सेदारी मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के कारण संथाल का प्रतिनिधित्व अधिक माना जा सकता है। 21 में से 9 सीटें देने वाले उत्तरी छोटानागपुर को 2 मंत्री तथा 15 में से 8 तथा 9 में से 4 सीटें झामुमो गठबंधन को देने वाले दक्षिणी छोटानागपुर तथा पलामू प्रमंडल को 1-1 मंत्री की हिस्सेदारी देकर हेमन्त सोरेन ने जनता को जनाधार आधारित राजनीत की राजनीति का संदेश देने का भरपूर प्रयास किया है। हेमन्त सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार

में जनाधार के साथ-साथ जातीय समीकरण और सहयोगी दलों का भी ख्याल रखा है।इनके मंत्रिमंडल में स्नातक से लेकर दसवीं पास विधायक तक को जगह मिली है वहीं जन-जंगल और जमीन के संघर्ष के बलबूते अपनी पहचान बनाने से लेकर तारा शाहदेव जैसे विवादित घटना क्रम से सम्बन्ध रखने वाले कद्दावर नेताओं को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है।

झामुमो के 30 तथा काँग्रेस के 16 विधायकों में से मात्र 12 लोगों का चयन वास्तव में एक कठिन कार्य था। कांग्रेस पार्टी जहाँ अपने भविष्य को साधने के लिये पुराने नये हर एक चेहरों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही थी वहीं पुरानी सरकार में बनें पुराने नेताओं के मंत्रित्व का हुए नफा-नुकशान का भी भरपूर आकलन कर किया। शायद यही कारण रहा कि कांग्रेस ने इस बार अपने पार्टी के कई पुराने चेहरे को दरकिनार कर नये चेहरों को मौका दिया। काँग्रेस पार्टी के लिए उस समय और निर्णय लेना कठिन साबित हो रहा था। जब काँग्रेस के वरिष्ठ व जेल की सजा काट रहे योगेंद्र प्रसाद की बेटी तेज तर्रार नेत्री अम्बा प्रसाद के योग्यता के कारण इनका नाम मानव संसाधन मंत्री के रूप में सोशल मीडिया पर पुर जोर उछाला जा रहा था। जितनी

दसवीं पास जगरनाथ सवारेंगे

झारखण्ड की शिक्षा व्यवस्था

रघुवरदास ने अपनी सरकार में झारखंड की शैक्षणिक व्यवस्था को संवारने की जिम्मेवारी वाणिज्य विषय मे मास्टर डिग्री प्राप्त व शिक्षक प्रशिक्षित नीरा यादव के कंधों पर दी थी। जिसका परिणाम झारखंड के शैक्षणिक व्यवस्था में देखने को मिला। सर्वशिक्षा अभियान के कारण कुकुरमुते की तरह गाँव-गाँव मे उग आये संसाधन विहीन विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था को मुँह चिढ़ रहे थे। जिसे समेटते हुए नजदीक के विद्यालयों में विलय कर उन विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाने का भरपूर प्रयास किया। यही नही राष्ट्रपति शासन से ही चली आ रही प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ती में बाहरी-भीतरी की पेंच फंसा कर अपने पिछले कार्यकाल में शिक्षकों की नियुक्ति नही कर सकने वाले हेमन्त सरकार की गुथियों को भी सुलझा कर नीरा यादव ने झारखंड के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के अलावे उच्च तथा उच्चतर विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति, बच्चों को बैठने हेतु बेंच-डेस्क तथा अन्य भौतिक तथा मानव संसाधनों की प्रतिपूर्ति कर यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भरपूर प्रयास किया।जिसका प्रतिफल है कि झारखण्ड में आज विद्यालय अब बच्चों से गुलजार मिलते हैं।

वहीं हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और राज्य की प्रतिभाओं को सँवारने की जिम्मेवारी दसवीं पास जगरनाथ महतो को दी है। नवनियुक्त विधानसभा में इनके तथा इनके सहयोगी दलों के पास एक से बढ़ कर एक योग्य विधायक थे। काँग्रेस की नई सही लेकिन तेज-तर्रार अम्बा प्रसाद इसके उदाहरण हैं। लेकिन ऐसे लोगों को दरकिनार कर दसवीं पास को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी राज्य के शिक्षाविदों को रास नही आ रही है। हालांकि जगरनाथ महतो को शिक्षा की जिम्मेवारी देने से राज्य के पारा शिक्षक खुश हैं। पारा शिक्षकों का मानना है कि अपने संघर्ष के बूते राजनीति में स्थान बनाने वाले जगरनाथ ही हमारी संघर्षों को समझ सकेंगे। लगातार डुमरी से चार-चार बार विधायक रहे जगरनाथ महतो अपने अनोखे क्रियाकलाप व संघर्ष के लिए जाने जाते हैं।इनकी राजनैतिक लोकप्रयिता को इसी से समझा जा सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ श्राद्धकर्म में पूड़ी छानने से लेकर अपने समर्थकों के समर्थन में रेलवे स्टेशनों पर चिनिया बादाम तक बेच कर विरोध दर्ज कराने का तरीका इनके राजनीति की पूँजी है।यही कारण है कि जगरनाथ अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। अब देखना यह है कि राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में जगरनाथ झारखण्ड के जनता के दिल मे कितना जगह बना पाते हैं। राज्य के पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह वेतनमान देना, सरकारी शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तरह उत्क्रमित वेतनमान देना, शिक्षकों को पुरानी पेंशन देना, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति, राज्य के विद्यालयों को चाहरदीवारी उपलब्ध कराना, पुस्तकालयों और प्रयोगशालायों को संसाधन युक्त करना इनके लिए चुनौतीभरा कार्य होगा।

मुश्किल घड़ी काँग्रेस के लिए थी शायद उतनी मश्किलें झामुमो के लिए नही था। क्योंकि यहाँ उमीदें और ख्वाइशें शिबु सोरेन और हेमन्त सोरेन के दहलीज पर आते-आते ही समाप्त हो जाती है। बावजूद झामुमो ने भी मंत्रियों की चयन में,चेहरों और अनुभवों को प्राथमिकता देते हुए परम्परागत नामों को तबज्जो नही दे नये चेहरों को भी स्थान दिया है।स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, मथुरा महतो को दरकिनार कर झामुमो ने मिथिलेश ठाकुर और जगरनाथ महतो सरीखे लोगों को जगह दिया।वहीं कांग्रेस ने भी बेरमो के अपने कद्दावर विधायक राजेन्द्र सिंह जैसे नेताओं को दरकिनार कर परम्परागत परम्परा को तोड़ने का प्रयास कर कार्यकर्ताओं को एक अच्छा सन्देश दिया है। बावजूद दोनों दलों ने पूर्व में भी मंत्री रहे जोबा मांझी, चम्पई सोरेन, हाजी हुसैन को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। मंत्रियों के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के अलावे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, काँग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, मंत्री रामेश्वर उराँव, आलमगीर आलम, सत्यानन्द भोक्ता के

अलावा कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे।राजभवन के खचाखच भरे बिरसा मण्डप में राजपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जहाँ चम्पई सोरेन, जोबा मांझी, जगरनाथ महतो, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर ने ईश्वर की नाम से पद और गोपनीयता की शपथ ली वहीं हाजी हुसैन अंसारी ने अल्लाह के नाम से पद और गोपनीयता की शपथ लिया। गौरतलब हो कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पांच मंत्री झामुमो कोटे से हैं जबकि कांग्रेस से चार और राजद से एक को मंत्री पद मिला है। इस लिहाज से गठबंधन की सरकार का खाका तैयार हुआ कि सभी समीकरण के साथ-साथ दलों ने जनाधार और क्षेत्रीय संतुलन का हिसाब रखा है। हालांकि राजद के पास मात्र एक विधायक होने की वजह से उसे मंत्री पद दिया गया, लेकिन झामुमो के 30 और कांग्रेस के 16 विधायकों में मंत्री के लिए चयन एक कठिन टास्क था। इसके लिए लगातार मशक्कत होती रही। कांग्रेस आलाकमान ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए मंत्रियों के नाम तय किए

रघुवर मंत्रिमंडल में रहे 5 मंत्रियों की सम्पत्ति में हुआ कई गुना वृद्धि

नीलकंठ मुंडा

रणधीर कुमार सिंह

लुईस मरांडी

अमर कुमार बाउरी

डॉ० नीरा यादव

अपने हरेक सभाओं में अपनी सरकार की छवि को लेकर दहाड़ मारने वाले रघुवर दास के मंत्रियों की पोल सत्ता जाते ही अब धीरे-धीरे खुलने लगी है। इनके सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाफ पंकज यादव नामक युवक के तरफ से, अधिवक्ता राजीव कुमार ने, एक जनहित याचिका दायर कर 5 वर्षो में आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप लगाया है। याचिका कर्ता ने अपने आवेदन में रघुवर सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री निलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व खेल मंत्री अमर बाउरी, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव तथा पूर्व कल्याण मंत्री लुईस मरांडी द्वारा 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में नामांकन के वक्त दीये गए शपथ पत्र को आधार बना आरोप लगाया है कि पांच वर्षों के अपने कार्यकाल में इन लोगों ने 200 से 1000 गुना तक सम्पति अर्जित की है। इनके अलावे कृषि सचिव, शिक्षा सचिव, खेल सचिव, कल्याण सचिव पर्यटन सचिव सहित ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों सहित कई अन्य को भी प्रतिवादी बनाते हुए इसकी जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने की मांग की है। यही नही रघुवर दास भले ही स्थापना दिवस से लेकर अपनी हरेक सभाओं में अपनी सरकार की छवि को लेकर ढिंढोरा पीटते फिरते रहें हो लेकिन अपने सभाओं में यह कभी नही बताया कि इनके मंत्रियों के के सम्पतियों में प्रत्येक वर्ष लगातार इतनी तीव्र गति से वृद्धि कैसे हुई। नामांकन के समय दिये गए शपथ पत्र को ही माने तो जहां 2014 में नीरा यादव के पास 80.65 लाख रुपये की सम्पति थी वह 2019 में बढ़ कर 3.65 करोड़ रुपये हो गई,अमर बाउरी के पास 7.34 लाख रुपये थी जो 5 वर्षो में बढ़ कर 89.49 लाख रुपये हो गई, निलकंठ मुंडा के पास 2014 में 1.46 करोड़ की सम्पति थी जो 5 वर्षो में बढ़ कर 3.65 करोड़ हो गई, रणधीर सिंह की सम्पति 2014 में 78.92 लाख थी जो 5 वर्षो में बढ़ कर 5.06 करोड़ हो गई,लुईस मरांडी की सम्पति 2014 में 2.25 करोड़ थी यह 5 वर्षो में बढ़ कर 9.06 करोड़ हो गई। याचिका कर्ता ने इससे इससे पहले भी मोमेंट ऑफ झारखंड के आयोजनों को लेकर भी रघुवर दास और इनके पदाधिकारियों के खिलाफ एसीबी में आवेदन देकर मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया था।

झारखण्ड के नवनिर्वाचित मंत्रियों के विभाग

रामेश्वर उरांव	- वित्त, वाणिज्यकर, खाद्य आपूर्ति
मिथिलेश ठाकुर	- पेयजल स्वच्छता
जगरनाथ महतो	- शिक्षा, उत्पाद विभाग
जोबा मांझी	- महिला एवं बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग
हाजी हुसैन अंसारी	- अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन विभाग
बादल पत्रलेख	- कृषि एवं पशुपालन व सहकारिता
आलमगीर आलम	- ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्यमंत्री
बन्ना गुप्ता	- स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग
चंपई सोरेन	- परिवहन विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग
सत्यानंद भोक्ता	- श्रम विभाग

तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपेक्षाकृत अनुभवी के साथ-साथ नए चेहरों को मौका दिया। दोनों दलों ने अपने संगठन के आधार वोट का खास ख्याल रखा है। सनद् रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्रिमंडल के गठन में कुछ परंपरागत नाम को इस दफा दरकिनार किया है। इसकी वजह भी थी। संताल परगना से ज्यादा झामुमो ने कोल्हान पर फोकस किया। स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली जबकि चंपई सोरेन स्थान पाने में कामयाब रहे। मथुरा प्रसाद महतो के स्थान पर झामुमो ने जगरनाथ महतो को आजमाया। मिथिलेश ठाकुर को मंत्री पद देकर झामुमो ने संकेत दिया है कि एक दायरे से बाहर संगठन विस्तार को इच्छुक है। हाजी हुसैन अंसारी को मुस्लिम चेहरे के नाम पर मौका मिला। उन्हें किसी प्रकार की चुनौती नहीं थी। वही कांग्रेस कोटे से मंगलवार को दो विधायकों बन्ना गुप्ता और बादल ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे वैसे विधायकों को झटका लगा, जो लगातार लाबिंग कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से दो मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा कांग्रेस ने पिछड़े और सामान्य वर्ग से मंत्री देकर सबको साधने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल बंटवारे में सभी प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व देने में हेमंत सोरेन सफल रहे हैं। सीएम के साथ-साथ चार मंत्री संथाल परगना क्षेत्र के हो गए हैं तो तीन मंत्री कोल्हान से बनाए गए हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से दो को मंत्री बनाया गया है तो दक्षिणी छोटानागपुर से महज एक मंत्री बने हैं। संथाल परगना से ही विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही हेमंत कैबिनेट में भले ही पलामू प्रमंडल से एक नाम मिथिलेश ठाकुर का दिख रहा हो, लेकिन वास्तविकता में उनका कर्म क्षेत्र कोल्हान ही है और वे विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के पूर्व तक चाईबासा में नगर निकाय के अध्यक्ष थे। विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ लेने के पूर्व उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से राजद कोटे से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता का नाम है तो झामुमो के जगरनाथ महतो को इस बार मौका मिला है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के दो मंत्री संथाल परगना क्षेत्र से बने हैं। इन दोनों मंत्रियों में आलमगीर आलम पहले ही मंत्री बन चुके थे जबकि बादल पत्रलेख ने शपथ ली। अन्य दो मंत्रियों में एक बन्ना गुप्ता कोल्हान के हैं तो दूसरे रामेश्वर उरांव दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ●

बच्ची दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया

● ओम प्रकाश

रॉची के जगन्नाथपुर में एक नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला रविवार को प्रकाश में आया है। बच्ची के साथ सत्रह साल के नाबालिग ने दुष्कर्म किया है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बताया जाता है कि बच्ची मूल रुप से सोनाहातू की रहने वाली हैं। बच्ची के माता-पिता खूंटी में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। बच्ची और उसका छह साल का भाई जगन्नाथपुर स्थित अपने नानी के घर में रहकर पढ़ाई करते हैं। पीड़ित बच्ची एक स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती है। घटना वाले दिन नाना-नानी काम करने बाहर गए थे। मामा घर में नहीं था। इस बीच बच्ची को अकेला पाकर आरोपित घर में घुसा और बच्ची से मारपीट की। मारपीट के बाद उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान घर में सो रहा छह वर्ष का भाई उठ गया और शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चे के शोर की वजह से आरोपित घटना को अंजाम देने के बाद भाग निकला। बच्ची के नाना-नानी जब वापस घर पहुंचे तो तब बच्ची ने रोते हुए पूरी बात उन्हें बतायी। इसके दूसरे ही दिन खुद आरोपी उनके घर पहुंचा और बोला कि इस बात की जानकारी मोहल्ले में या पुलिस को दी, तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना चार फरवरी की है। बच्ची जब घर में अकेली थी तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए आरोपी लड़के ने बच्ची के मामा से मारपीट की। बच्ची के मामा के साथ आरोपी ने आठ फरवरी को मारपीट की थी जिससे वह बेहोश हो गया था मारपीट और हो हल्ला देख पड़ोसियों और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसके मामा को आरोपी से बचाया। इसके साथ ही आरोपी ने बच्ची के मामा को धमकाया कि पुलिस के पास जाने या अन्य किसी और को बताने पर जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद बच्ची के साथ रेप किये जाने की घटना की जानकारी उसके पिता को मिली, जिसके बाद वह रविवार को बच्ची के नाना के घर पहुंचे और बच्ची के साथ हुई घटना की जानकारी वहां के बस्ती वालों को दी। इसके बाद सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज कराया जाए इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के मोहल्ले में जाकर छापामारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया। वही, बच्ची को सोमवार को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ●

करोड़ों की विद्युत पावर ग्रिड में सेंधमारी

● हरिओम प्रसाद

लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र जो जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और आज भी विकास कें कई प्राथमिक आयाम लोंगों कघि पहुँच से दूर हैं इसका प्रमुख कारण हैं उग्रवाद और नक्सलवाद। आज के वैज्ञानिक दौर में बिजली, दूरसंचार, यातायात और शिक्षा के वगैर विकास की कल्पना करना बेईमानी होगी। बड़ी मुश्किल से जिला प्रशासन द्वारा विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण गारू के सरयू स्थित सोनवार घाटी में लगभग बनकर तैयार हो चुका था लोंगों में उत्साह व खुशी थी की अब बिजली का लाभ हमलोगों को मिलेगा। भय भूख और आतंक में जीने वाला गारू अब बिजली से रात में जगमगाएगा। परंतु लोंगों का सपना अधूरी ही रह गयी और चोरों ने 29 जनवरी की रात में जहाँ लोग सरस्वती पुजा में लगें थें वहीं दूसरी ओर बिजली ट्रांसफॉर्मर की महँगी तांबे की तारे व क्वाइल समेत लगभग 69 लाख 50 हजार की संपति रातों रात सेक्यूरिटी गार्ड कों बंधक बनाकर चोरी कर ली और एक नयी मुसीबत खड़ी कर आम अवाम और प्रशासन को चुनौती दें डाली। तत्पश्चात विद्युत ग्रिड कें कार्य करने वाले संवेदक गौहर अली चिश्ती नें गारू थाना कों मामलें की लिखित शिकायत दर्ज करवायी। मामलें को गंभीरता से लेते हुए तत्परता के साथ थाना प्रभारी आलोक दुबे ने एक एक पहलू पर छापेमारी शुरू कर दी और बहुत जल्द ही चोरों कों पकड़ने में सफलता मिल गयी। मामलें की जानकारी देते हुए श्री दुबे ने केवल सच को बताया की रेलवे स्टेशन लातेहार पुलिस लाईन के पास कबाड़ी दुकान से छापेमारी में आधुनिक विधुत कट्टर मशीन बरामद किये गये जो उक्त चोरी में प्रयुक्त किये गये थे जिसे चोरों नें कूरियर से ऑर्डर देकर मंगवाया था। साथ ही चोरों की निशानदेही पर लातेहार और गारू की संयुक्त पुलिस टीम ने लातेहार सदर प्रखंड के नावागढ़ निवासी पारस प्रसाद उर्फ बूटन के घर से विद्युत पावर ग्रिड से चोरी किये गये तांबा और क्वाइल के अलावा रेलवे का भी लोहा भारी मात्रा में बरामद किया गया, जिसका अंदाजा पुलिस को भी शायद पहले से नहीं था। पूरे मामलें की जांच पड़ताल के बाद पता चला की क्वायल और अन्य सामग्रियों की चोरी में विजय सिंह व यशवंत कुमार पासवान दोनों लातेहार व मो इरशाद उर्फ सोनू और मो अशरफ दोनों चंदवा के चोर शामिल थे। जिसमें विजय सिंह का आपराधिक इतिहास रहा हैं और वह हाल फिलहाल में ही जेल से छूटा था। जिसे लातेहार पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनन्द एक प्रेस वार्ता कर चोरी कांड का खुलासा करते हुवे उक्त चारों चोरों कों जेल भेज दिया हैं। जबकि अभी भी इस घटना में शामिल मास्टर माईंड पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं वहीं चोरी में संलिप्त पिकअप वाहन भी पुलिस जब्त कर आगे की पुलिसिया कारवाई में जुटी हैं। बताते चलें की पुलिस ने अभी तक अपराधियों की निशानदेही पर 14 तांबा तार 5 मोबाईल सेट 3 पीस वोल्ट कटर 1 पीस खाली वोल्ट बॉक्स व 1 पीस बड़ी ताला बरामद कर लिया हैं। गारू थाना प्रभारी आलोक दुबे ने केवल सच को आगे बताया की बहुत जल्द ही इसमें संलिप्त अन्य अपराधियों को पुलिस पकड़ कर जेल भेजेगी ताकि आगे आने वाले समय में कानून को हाथ में लेने वाले अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना कर सकें। वहीं छापेमारी संयुक्त टीम कें लातेहार थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता के प्रयास का ही नतीजा हैं की किसी भी आपराधिक मामलें कों चुनौतीपूर्ण लेते हुए अपने क्षेत्र की जनता के साथ समन्वय बनाकर शांति और सौहार्दय स्थापित करने का ही सफल परिणाम हैं की लातेहार में पहले के दशक से अपराध में कमी आयी हैं। चोरों की पकड़ कर में संयुक्त टीम पुलिस कें जेम्स कुजूर (स.अ.नि.) दूति कृष्ण महतो, राजीव कुमार भगत, रूपलाल प्रसाद (परि.प.अ.नि.) अन्थनदेव कुजूर (आ. 251) रामकुमार सिंह (आ.186)के अलावा चौकीदार मुस्लिम अंसारी, सुशील कुमार पासवान शामिल थें।

वहीं गारू कें लोगों ने पुलिस प्रशासन को चोरी कांड का उद्भेदन करने हेतू धन्यवाद दिया हैं और जिला प्रशासन से विद्युत पावर ग्रिड को जल्द से चालू कराने की माँग की हैं। ●